

खान भारती

विशेषांक वर्ष 2023

मराठी मराठी हिन्दी
ತುಳುಗು ಶಿವಿ ಸಂಸ್ಕೃತಮ್
ગુજરાતી ಭાષા اُردُو
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା অসমীয়া
മലയാളം
वांशना தமிழ்
ಕನ್ನಡ

हिन्दी

कामायनी - जयशंकर प्रसाद

गोदान - प्रेमचंद

साकेत - मेथिलीशरण गुप्त

राम की शक्ति पूजा
- शुकनास विपरीत निराल

दीपशिखा
- महर्षि वर्मा

रश्मि



भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर



संसदीय राजभाषा समिति द्वारा राँची क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण



राँची क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण के दौरान माननीय लोकसभा सांसद डॉ. मनोज राजोरिया को शॉल भेंट करते हुए डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी



खान मंत्रालय द्वारा भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय एवं इसके समस्त अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा समीक्षा बैठक



खान मंत्रालय द्वारा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शकील आलम, आर्थिक सलाहकार, खान मंत्रालय



भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विशेष हिन्दी कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर अध्यक्षीय भाषण देते हुए श्री पी. एन. शर्मा, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी)



हिन्दी पखवाड़ा - 2022 के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह में संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि श्री मुकुन्द पी. चौधरी, अध्यक्ष सह - प्रबंध निदेशक, मॉयल लिमिटेड

खान भारती



हिन्दी अनुभाग भारतीय खान ब्यूरो

संरक्षक

संजय लोहिया

भा.प्र.से.

अपर सचिव एवं महानियंत्रक (प्रभारी)

संपादक मंडल

मुख्य संपादक

डॉ. योगेश जी. काले

खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी

संपादक

अभिनय कुमार शर्मा

संपादक

साज-सज्जा एवं टंकण

प्रदीप कुमार सिन्हा

उच्च श्रेणी लिपिक

संपादन सहयोग

मिताली चटर्जी

वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

असीम कुमार

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

किशोर डी. पारधी

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

वीनू खत्री

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

राहुल कौशिक

उच्च श्रेणी लिपिक



संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री
भारत सरकार
नई दिल्ली
MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS,
COAL AND MINES
GOVERNMENT OF INDIA
NEW DELHI



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

प्रल्हाद जोशी
PRALHAD JOSHI
ಪ್ರಲಾಹ ಜೋಶಿ



सन्देश

मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय खान ब्यूरो का प्रधान कार्यालय अपने 75 वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी हिंदी गृह-पत्रिका 'खान भारती' के विशेषांक का प्रकाशन कर रहा है।

हिंदी गृह-पत्रिका राजभाषा के प्रचार-प्रसार का एक सशक्त माध्यम है। इससे कर्मचारियों को अपनी सृजनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करने का एक मंच मिलता है। साथ ही, हिंदी में कार्य करने के लिए एक प्रेरणादायी वातावरण का भी निर्माण होता है।

हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में हमारे संविधान निर्माताओं द्वारा प्रतिष्ठित किया गया, और हिंदी को संघ सरकार के काम-काज की भाषा बनाने का दायित्व देशवासियों को सौंपा गया। राजभाषा हिंदी में काम करना और इसके विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य होने के साथ-साथ हमारा नैतिक दायित्व भी है।

मैं आशा करता हूँ कि 'खान भारती' पत्रिका में पाठकों के लिए रुचिपूर्ण और ज्ञानवर्धक कृतियां प्रकाशित की जाएंगी। मैं पत्रिका से जुड़े सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक बधाई देता हूँ और इसके सफल प्रकाशन एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

प्र. वे. जोशी
(प्रल्हाद जोशी)

Office : Room No. 15, Parliament House, New Delhi-110001,
Tel : 011-23017780, 23017798, 23018729, Fax : 011-23792341

Office : Room No. 353, 'A' Wing 3rd Floor, Shastri Bhawan, New Delhi,
Tel : 23387277, 23383109, 23386402

Residence : 11 Akbar Road, New Delhi - 110001, Tel : 011-23014097, 23094098
H. No. 122-D, 'Kamitartha' Mayuri Estate, Keshwapur, Hubli-580023 (Karnataka)
Tel No. : 0836-2251055, 2258955, E-mail : pralhadvjoshi@gmail.com



राज्य मंत्री
रेल, कोयला एवं खान राज्य मंत्रालय
भारत सरकार
MINISTER OF STATE OF RAILWAYS,
COAL & MINES
GOVERNMENT OF INDIA



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

रावसाहेब पाटिल दानवे
RAOSAHEB PATIL DANVE



सन्देश

मुझे यह जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि खान मंत्रालय का एक अभिन्न अंग भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर अपना 75वां स्थापना वर्ष मना रहा है और इसके उपलक्ष्य में अपनी हिंदी गृह पत्रिका हिंदी के प्रचार - प्रसार के दृष्टिकोण से तथा विविध विषयों पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अनुपम स्थान है।

हिंदी भारत और भारत की सामासिक संस्कृति की भाषा रही है। आज यह केवल भारत की भाषा न होकर विश्व के एक बड़े समुदाय की भाषा के रूप में विकसित हो रही है। संविधान द्वारा प्रदत्त राजभाषा होने के साथ - साथ हिंदी देश की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाने का माध्यम भी है। अतः इसके प्रचार - प्रसार के प्रति हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि कार्यालय द्वारा हिंदी गृह पत्रिका के नियमित प्रकाशन से हिंदी में कार्य करने के लिए कार्यालय में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा और हिंदी के प्रयोग को गति मिलेगी। मैं 'खान भारती' पत्रिका से जुड़े समस्त रचनाकारों और संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ और पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।


(रावसाहेब पाटिल दानवे)



व्ही. एल. कान्ता राव, भा.प्र.से.
सचिव

V. L. KANTHA RAO, IAS
Secretary

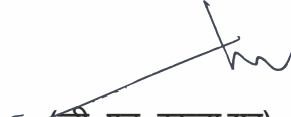


सन्देश

यह जानकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर अपने 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य पर हिंदी गृह पत्रिका 'खान भारती' के विशेषांक का प्रकाशन करने जा रहा है। यह राजभाषा हिंदी के प्रति समर्पित कर्तव्य और सेवाभाव तथा कार्यालय में राजभाषा के प्रयोग में निरंतर अभिवृद्धि का परिचायक है।

भारत अनेक समृद्ध भाषाओं का देश है। हिंदी सभी भाषा - भाषियों तथा जनता व सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का काम करती है। राजभाषा होने के साथ - साथ यह हमारे देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है। ऐसे में हिंदी के प्रचार - प्रसार के प्रति हमारा दायित्व और भी बढ़ जाता है।

मेरी यह कामना है कि 'खान भारती' पत्रिका हिंदी के प्रचार - प्रसार का माध्यम बने और इसकी रचनाएँ उपयोगी सिद्ध हों। इस पत्रिका से जुड़े सभी लेखकों, पाठकों एवं संपादक मंडल को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।


(व्ही. एल. कान्ता राव)
सचिव



संजय लोहिया, आईएएस
अपर सचिव एवं महानियंत्रक (प्रभारी)

SANJAY LOHIYA, IAS
Additional Secretary & Controller General (Incharge)



सन्देश

मेरे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय की हिन्दी गृह पत्रिका 'खान भारती' के विशेषांक का प्रकाशन कार्यालय के 75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर किया जा रहा है। हिन्दी पत्रिका का प्रकाशन राजभाषा के विकास, प्रचार-प्रसार और आगामी प्रयोग की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

प्राचीन काल से ही हिन्दी ने सभी प्रांतीय भाषाओं के साथ मिलकर भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया है तथा यह संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा रही है। संविधान सभा द्वारा हिन्दी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किये जाने के फलस्वरूप हमें यह दायित्व मिला कि सरकारी प्रयोजनों के लिए अधिक - से - अधिक कार्य राजभाषा हिन्दी में किया जाए। अतः सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग करना हमारी जिम्मेदारी मात्र नहीं है, बल्कि यह हमारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय कर्तव्य भी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि गृह पत्रिका 'खान भारती' विभिन्न प्रतिभा संपन्न रचनाकारों को साहित्यिक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करेगी और साथ ही इससे पाठकों का ज्ञानवर्धन भी होगा। मैं इस पत्रिका से जुड़े समस्त रचनाकारों और संपादक मंडल को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा पत्रिका की सफलता एवं उन्नति की कामना करता हूँ।

संजय लोहिया
(संजय लोहिया)

अपर सचिव एवं महानियंत्रक (प्रभारी)



पीयूष नारायण शर्मा
मुख्य खान नियंत्रक का कार्यालय

PEEYUSH NARAYAN SHARMA
Office of the Chief Controller of Mines



सन्देश

75वें स्थापना वर्ष के अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा हिन्दी गृह-पत्रिका 'खान-भारती' के विशेष अंक का प्रकाशन निःसंदेह सराहनीय है। हिन्दी गृह-पत्रिका राजभाषा के संवर्धन, विकास और प्रसार में अपनी विशिष्ट भूमिका निभाती है। उसके माध्यम से विभाग के सदस्यों में छिपी सृजनात्मक प्रतिभा उजागर होती है और हिन्दी में कार्य करने के लिए प्रेरणादायी वातावरण का निर्माण होता है।

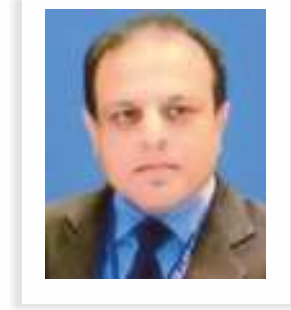
भारत की पुण्य धरा पर अनेक भाषाएँ और संस्कृतियाँ पुष्पित - पल्लवित हुई हैं। विविधताओं से भरे हमारे देश को एकता के सूत्र में पिरोने में हिन्दी का योगदान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हिन्दी भाषा की सरलता और सहजता उसे विशेष बनाती है। बोल-चाल और विपुल साहित्य के साथ-साथ तकनीक के क्षेत्र में हिन्दी का लगातार बढ़ता प्रयोग और नई पीढ़ी में उसकी लोकप्रियता एक उज्ज्वल भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करती है।

मुझे उम्मीद है कि 'खान-भारती' के इस अंक में रोचक रचनाओं और ज्ञानवर्धक जानकारियों का समावेश किया जाएगा। मैं पत्रिका से जुड़े विभाग के समस्त सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूँ तथा 'खान-भारती' के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।

(पी.एन.शर्मा)
मुख्य खान नियंत्रक (एम.डी.आर.)



पंकज कुलश्रेष्ठ
मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी)



सन्देश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा आगामी हिन्दी पखवाड़े में हिन्दी गृह - पत्रिका 'खान-भारती' के विशेषांक का प्रकाशन किया जा रहा है। पत्रिका का प्रकाशन न केवल एक निरंतरता का प्रतीक है, अपितु हिन्दी के प्रति निष्ठा एवं समर्पण का साकार उदाहरण है।

हिन्दी एक समृद्ध भाषिक, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परम्परा की वाहिनी है और उससे करोड़ों भारतवासियों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। हिन्दी भारत की अंतरात्मा है और राष्ट्र की वाणी है। यह अधिकांश देशवासियों की अभिलाषाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम है। संविधान ने हम सब पर राजभाषा हिन्दी के विकास का दायित्व सौंपा है। उस दायित्व के निर्वहन में विभाग की हिन्दी गृह-पत्रिका का भी महत्वपूर्ण योगदान है।

आशा है कि पत्रिका के इस विशेष अंक के प्रकाशन से विभाग के सदस्यों में हिन्दी के प्रति उत्तरोत्तर बढ़ती रुचि में वृद्धि होगी। हिन्दी भाषा में लेखन की सृजनात्मक प्रतिभा को बढ़ावा मिलेगा तथा लेखन व पठन के प्रति रुझान बढ़ेगा।

पत्रिका प्रकाशन से जुड़े विभाग के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

(पंकज कुलश्रेष्ठ)

मुख्य खान नियंत्रक (एम.ई.एस.)



डॉ. योगेश जी. काले

खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी

DR. YOGESH G. KALE

Controller of Mines & Rajbhasha Adhikari



प्रधान संपादक की कलम से...

भारतीय खान ब्यूरो वर्ष 2023 को अपना 75वां स्थापना वर्ष के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा, हिन्दी पखवाड़ा के दौरान गृह-पत्रिका 'खान भारती' के विशेष अंक का प्रकाशन किया जा रहा है जो निःसंदेह गर्व का विषय है। भारतीय खान ब्यूरो के समस्त सदस्य राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन और अनुपालन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उसी सामूहिक सहभागिता का परिणाम है कि हिन्दी गृह - पत्रिका 'खान-भारती' का प्रकाशन नियमित, सुचारु और नवीनतम रूप में हो रहा है।

'खान-भारती' का यह विशेष अंक विश्व में 'हिन्दी के बढ़ते कदम' विषय पर भी केन्द्रित है। विगत वर्षों में वैश्विक स्तर पर हिन्दी ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आज पूरा विश्व हिन्दी की क्षमता और शक्ति को पहचान रहा है। विश्व के बड़े-बड़े निजी संस्थान भी आज हिन्दी में काम-काज को प्राथमिकता दे रहे हैं। विश्व के अधिकांश ई-कॉमर्स संस्थानों ने अपने कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अपनी वेबसाइट हिन्दी में बनाई है। साथ ही हिन्दी अपने व्याकरण, लिपि, एवं उच्चारण की दृष्टि से विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा भी है। अपनी उदारता, व्यापकता और ग्रहणशीलता के कारण हिन्दी भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की पूरक है तथा भारत की एकता को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम रही है।

'खान-भारती' एक ऐसा मंच है जहाँ भारतीय खान ब्यूरो के सदस्य राजभाषा हिन्दी में अपने विचार,




भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
खान मंत्रालय
MINISTRY OF MINES
भारतीय खान ब्यूरो
INDIAN BUREAU OF MINES



75
आज़ादी का
अमृत महोत्सव

भावनाओं और संवेदनाओं को अपनी कहानी, कविता, लेख आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं तथा साथ ही, अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित ज्ञान आदि जानकारियों को भी एक-दूसरे के साथ बाँटते हैं।

'खान-भारती' विशेषांक के प्रकाशन के अवसर पर मैं भारतीय खान ब्यूरो के समस्त सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ तथा अनुरोध करता हूँ कि वे सरकारी काम-काज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करें। साथ ही, इस विशेषांक से जुड़े संपादक मंडल एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई देता हूँ और पत्रिका के सफल प्रकाशन की कामना करता हूँ।


25/07/2023

(डॉ. योगेश जी. काले)
खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी

इन्दिरा भवन, सिविल लाईन्स, नागपुर-440 001
Indira Bhavan, Civil Lines, Nagpur-440001

फोन /फैक्स / Phone / Fax No. 0712 2561824, 2565073 | ई-मेल /E-mail: ccom-mes@ibm.gov.in



संपादकीय

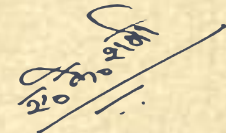


भारतीय खान ब्यूरो के 75वें स्थापना वर्ष के उपलक्ष्य में 'खान भारती' का आगामी अंक विशेषांक के रूप में भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। यह भारतीय खान ब्यूरो द्वारा हिन्दी भाषा को समृद्ध बनाने और उसके बहुआयामी विकास की ओर बढ़ते कदम का परिचायक है। खान भारती में इस बार हिन्दी से जुड़े ऐसे विविध विषयों को समाहित किया गया है जिनसे पाठकों को हिन्दी से सम्बंधित समसामयिक जानकारी अर्जित हो पाए और वे हिन्दी भाषा के उत्तरोत्तर विकास से परिचित हो सकें। पाठकों के हिन्दी के प्रति ज्ञान एवं अभिरुचि को दटोलने की कोशिश भी की गयी है।

भारतीय खान ब्यूरो हिन्दी के उत्थान एवं विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसका प्रमाण है इसके द्वारा राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम को पूरी कर्मठता एवं प्रतिबद्धता के साथ अपने समस्त आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में लागू करना। इसके लिए बहुत से संस्थानगत प्रयासों का सहारा लिया जाता है, जैसे-राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन, नियमित रूप से अपने कार्मिकों को हिन्दी प्रशिक्षण दिलाना, अधिक से अधिक कार्मिकों के लिए हिन्दी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना में प्रतिभागिता सुनिश्चित करवाना, न केवल मुख्यालय स्तर पर अपितु अखिल भारतीय स्तर पर भी हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन करना और मुख्यालय के साथ-साथ सभी आंचलिक एवं क्षेत्रीय कार्यालयों का नियमित राजभाषा कार्यान्वयन सम्बन्धी निरीक्षण करना ताकि सभी कार्मिकों को हिन्दी के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके। इन सब प्रयासों का सर्वप्रमुख लक्ष्य है कि हिन्दी भाषा को सभी कार्मिकों हेतु सुग्राह्य बनाया जा सके और हिन्दी भाषा के प्रयोग में आ रही कठिनाईयों को व्यावाहरिक रूप प्रदान करके उसे सरल तथा सहज बनाया जा सके। हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़े में विभिन्न प्रकार की रोचक हिन्दी प्रतियोगिताएं अयोजित करवाने से हिन्दी के प्रयोग के प्रति कार्मिकों को प्रेरित किया जाता है।

ये सभी भारतीय खान ब्यूरो के ऐसे विभागीय प्रयास हैं जिनसे वह हिन्दी भाषा के विकास के संवैधानिक संकल्प एवं दायित्व को सफलतापूर्वक पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रायः देखा जाता है कि हिन्दी भाषा में तकनीकी आलेखों का अभाव होता है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए खान भारती के विशेषांक में खनन से सम्बंधित विषय भी शामिल किया गया है। प्रस्तुत अंक में हिन्दी भाषा में खनन से जुड़े तकनीकी आलेखों का भी समावेश किया गया है। यह हिन्दी को तकनीकी क्षेत्र में भी प्रयोग में लाने का भारतीय खान ब्यूरो का समुन्नत प्रयास है। पत्रिका को पाठकों के लिए और अधिक रुचिकर बनाने के लिए कुछ कविताएं भी शामिल की गयी हैं। पत्रिका में मुख्यालय द्वारा आयोजित वर्षभर की राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियों की भी फोटोग्राफ सहित एक झलक दी गई है।

वर्ष 2023 का यह विशेषांक निश्चय ही पाठकों को रुचिकर लगेगा और विविध सूचनाप्रद आलेखों को पढ़कर वे अवश्य ही अपनी जानकारी में अभिवृद्धि करेंगे। आपके महत्वपूर्ण सुझावों का हमेशा स्वागत है। अंत में, मैं श्री संजय लोहिया, महानियंत्रक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु सतत सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया। मैं विशेष तौर पर श्रीमान् पियूष नारायण शर्मा, मुख्य खान नियंत्रक महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही मैं अपने राजभाषा अधिकारी डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक महोदय को हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके सक्षम मार्गदर्शन में भारतीय खान ब्यूरो राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर पाया एवं खान भारती पत्रिका को एक स्तरीय कलेक्टर दे पाया। इसके अतिरिक्त मैं संपादक मंडल का भी हार्दिक आभार करना चाहूँगा जिनके सहयोग से हिन्दी अनुभाग राजभाषा को समर्पित इस पत्रिका को प्रकाशित कर पाया।



(अभिनय कुमार शर्मा)
संपादक

अनुक्रमणिका

क्रमांक	रचना का शीर्षक	लेखक	पृष्ठ संख्या
1	भारतीय गैर-कोयला प्रधान खनिज उद्योग: राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अंतर्गत किये गए पहल	डॉ. योगेश गुलाबराव काले	1-6
2	वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते कदम	अभिनय कुमार शर्मा	7-8
3	वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते कदम	पुखराज नेणिवाल	9-10
4	सर्क्युलर इकॉनोमी टेलिनियर इकॉनोमी	अचिंत गोयल	11-13
5	वर्तमान परिदृश्य में भारतीय खनिज उद्योग	गौरव शर्मा	14-17
6	वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी के बढ़ते कदम	नरेश कुमार कटारिया	18-19
7	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	पीयूष शुक्ला	20-21
8	हिंदी के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका	रामसिंह	22
9	विश्व - पटल पर हिंदी	असीम कुमार	23-24
10	आजादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिन्दी	एकता गिरि	25-26
11	हिन्दी के प्रचार - प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका	दिलीप पंवार	27-28
12	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	अनुराग द्विवेदी	29-30
13	हिन्दी के बढ़ते कदम	विनय कुमार सक्सेना	31-32
14	हिंदी के प्रचार - प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका	संजय डोंगरे	33-34
15	विश्व - पटल पर हिन्दी	कृति गुप्ता	35-36
16	सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा का वर्चस्व	रोहन सुहास तिजारे	37
17	वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते कदम	बाबूलाल गुर्जर	38-39
18	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	प्रदीप कुमार सिन्हा	40-41
19	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का योगदान	शिवशंकर	42-43
20	हिन्दी के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका	अंजली त्रिवेदी	44-45
21	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का योगदान	सुरेन्द्र कुमार कुमावत	46-47
22	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	सतीश कुमार चौरे	48-49
23	हिंदी के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका	आर.एस.धोपटे	50-52
24	राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का योगदान	राहुल कौशिक	53-54
25	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	तय्यब हुसैन	55-56
26	हिंदी के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका	डेनियल रायमन	57-58
27	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	शशांक जैन	59-60
28	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	आकाश मित्रवार	61-62
29	आजादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिंदी	अज़मतउल्ला शरीफ	63-64
30	हिन्दी के प्रचार - प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका	सुरेश अरुण पाटिल	65-66
31	अमृत महोत्सव	आर. सी. महतो	67
32	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	वीनू खत्री	68-69
33	वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका	विकास कुमार	70
34	आजादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिंदी	श्रीनाथ राज	71-72
35	गत वर्ष के दौरान हिंदी से संबंधी कार्यों का विवरण		73-79

नोट : पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार लेखक के अपने हैं एवं संगठन से उसका कोई संबंध नहीं है।

भारतीय गैर-कोयला प्रधान खनिज उद्योग: राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 के अंतर्गत किये गए पहल



डॉ. योगेश गुलाबराव काले
खान नियंत्रक तथा राजभाषा अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर

1.0 परिचय

खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वतंत्रता के पश्चात से मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में खनिज उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में भारत लगभग 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें 4 ईंधन, 10 धात्विक, 23 अधात्विक, 3 परमाणु और 55 लघु खनिज (इमारत के पत्थर और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।

1947 में स्वतंत्रता के तुरंत बाद और औद्योगिक नीति संकल्प को अपनाने के साथ, विशेष रूप से औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक खनिजों की खोज तेज कर दी गई। स्टील, सीमेंट, बिजली, अलौह धातु, उर्वरक इत्यादि जैसे मुख्य उद्योगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए और अत्यधिक आवश्यक विदेशी मुद्रा के लिए उच्च निर्यात को ध्यान में रखते हुए, क्रमिक 'पंचवर्षीय योजनाओं' में महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किए गए थे। भारत सरकार ने 1991 में प्रमुख आर्थिक सुधारों की शुरुआत की जिसका उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था को विनियमन करना था।

इसके साथ एक नए युग की शुरुआत हुई जब मार्च 1993 में राष्ट्रीय खनिज नीति घोषित की गई और खनन क्षेत्र को निजी पहल और

निवेश के लिए खोल दिया गया। इसे और बढ़ावा देने के लिए, 1993 की खनिज नीति की जगह नई राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 मार्च 2008 में लागू हुई। गैर-ईंधन और गैर-कोयला खनिजों के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण नीति (एनएमईपी) 2016 में रणनीति और कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए बनाई गई थी, जिसे देश के खनिज संसाधनों की व्यापक खोज सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाएगा। हाल ही में, मौजूदा राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की जगह नई राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 को फरवरी 2019 में अधिक प्रभावी, सार्थक और कार्यान्वयन योग्य नीति घोषित किया गया था जो आगे पारदर्शिता, बेहतर विनियमन और प्रवर्तन, संतुलित सामाजिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ टिकाऊ खनन प्रथाओं को लाती है।

खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के रूप में व्यापक सुधार समय-समय पर नीति निर्देशों को प्रभावी बनाने के लिए किए जाते हैं। 2015, 2020 और 2021 में एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन के माध्यम से प्रमुख सुधार किए गए हैं। सुधार सकारात्मक परिणाम दिखा रहे हैं ताकि "मेक इन इंडिया" उद्देश्यों में परिकल्पना के अनुसार आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।

2.0 भारतीय गैर-कोयला प्रधान खनिज उद्योग का अवलोकन

प्रचुर समृद्ध भंडार के रूप में खनिजों की व्यापक उपलब्धता ने इसे भारत में खनन क्षेत्र, विशेषकर गैर-कोयला खनिज क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए बहुत अनुकूल बना दिया है।

2.1 खनिज संसाधन

स्वतंत्रता के बाद की अवधि में ज्ञात और अख्यते दोनों क्षेत्रों में किए गए ठोस अन्वेषण से खनिजों के बड़े संसाधन स्थापित हुए हैं। भारतीय खनिज उद्योग के पास एक सुस्थापित अन्वेषण संरचना है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिज गवेषण निगम लिमिटेड मुख्य खोजी एजेंसियां हैं, जिनके साथ विभिन्न राज्य भूविज्ञान और खनन निदेशालय ने व्यापक गवेषण किया है। हाल ही में कई निजी उद्यमियों ने खनिज गवेषण क्षेत्र में प्रवेश किया है जिसके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। परिणामस्वरूप, खनिज आधार 34 से बढ़कर 95 खनिज हो गया है।

2.2 खनन पट्टों की संख्या

भारत प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के खनिजों से समृद्ध है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 328.73 मिलियन हेक्टेयर है। इसमें से ईंधन, परमाणु खनिज और सभी लघु खनिजों को छोड़कर खनन पट्टा क्षेत्र लगभग 0.09% है। 31.3.2021 तक खनन पट्टों की स्थिति से पता चलता है कि देश में राज्य सरकारों द्वारा 3,314 खनन पट्टे (कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु खनिज और लघु खनिजों को छोड़कर) दिए गए हैं, जिनमें 38 खनिज शामिल हैं, जिनका कुल पट्टा क्षेत्र लगभग 3,06,398.76 हेक्टेयर है और 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है।

2.3 खनिज उत्पादन एवं मूल्य

2021-22 के दौरान खनिज उत्पादन (परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य 1,90,389 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 23.37% की वृद्धि दर्शाता है। 2021-22 के दौरान धात्विक खनिजों का अनुमानित मूल्य रु. 1,05,092 करोड़ या कुल मूल्य का 55.2% और लघु खनिजों सहित गैर-धात्विक खनिजों का मूल्य रु 85,297 करोड़ या कुल मूल्य का 44.8%.

2019 में विश्व उत्पादन में भारत की रैंकिंग स्टील (कच्चा) में दूसरी थी; क्रोमाइट और एल्यूमीनियम (प्राथमिक) में तीसरा; लौह अयस्क, जस्ता (स्लैब) और सीसा (परिष्कृत) में चौथा; बॉक्साइट में 5वां; मैंगनीज अयस्क में 7वां, तांबे (परिष्कृत) में 13वां, एपेटाइट और रॉक फॉस्फेट में 16वां और मैग्नेसाइट में 17वां।

2.4 खनिज एवं खनिज आधारित उत्पादों में आत्मनिर्भरता

भारत खनिजों में पूरी तरह या बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भर बना हुआ

है, जो प्राथमिक खनिज कच्चे माल का निर्माण करता है, जो उद्योगों को आपूर्ति की जाती है, जैसे कि लोहा और इस्पात, एल्यूमीनियम, सीमेंट, विभिन्न प्रकार के रिफ़ैक्टरीज़, चीनी मिट्टी आधारित सिरेमिक, कांच इत्यादि। भारत बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर में आत्मनिर्भर या आत्मनिर्भर होने के करीब है। भारत में कायनाइट, मैग्नेसाइट, मैंगनीज अयस्क, रॉक फॉस्फेट, सिलिमेनाइट आदि की कमी है, जिनका आयात स्थानीय रूप से उपलब्ध खनिज कच्चे माल के साथ मिश्रण और/या खनिज-आधारित उत्पादों के विशेष गुणों के निर्माण की मांग को पूरा करने के लिए किया जाता था। घरेलू कटिंग और पॉलिशिंग उद्योग द्वारा बिना कटे हीरे, पन्ना और अन्य कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, भारत अपने मूल्यवर्धित पुनः निर्यात के लिए कच्चे बिना कटे पत्थरों के आयात पर निर्भर है। बॉक्साइट, क्रोमाइट, लौह अयस्क और चूना पत्थर खनिज के मामले में भारत शत-प्रतिशत आत्मनिर्भर है।

2.5 विदेश व्यापार

भारत बड़ी संख्या में खनिज और खनिज आधारित उत्पादों का निर्यात करता है। भारत विश्व बाजार में शीट अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट और ग्रेनाइट का भी प्रमुख निर्यातक है। स्वदेशी संसाधनों की कमी के बावजूद, भारत मूल्यवर्धित रूप में हीरे की कटाई, पॉलिशिंग और निर्यात के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा है। निर्यात की महत्वपूर्ण वस्तुओं में कटे और पॉलिश किए गए हीरे, कीमती पत्थर, लौह अयस्क, क्रोमाइट, मैंगनीज अयस्क, रफ और पॉलिश ग्रेनाइट, बैराइट्स, स्टीटाइट, एल्यूमिना और एल्यूमीनियम, लोहा और स्टील आदि धातुएं शामिल हैं। 2020-21 के दौरान भारत से अयस्कों और खनिजों के निर्यात का कुल मूल्य 1,96,653 करोड़ रुपये था। दूसरी ओर, कच्चा हीरा, सोना, कोर्किंग कोयला, तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, टिन, टंगस्टन, रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टस, पोटाश, पेट्रोलियम आदि कुछ महत्वपूर्ण खनिज और धातु हैं, जिनका आयात किया जा रहा है। इसी अवधि के दौरान सभी अयस्कों और खनिजों का आयात बिल लगभग 7,91,320 करोड़ रुपये था। यह तस्वीर निर्यात और आयात के बीच एक उल्लेखनीय असंतुलन को दर्शाती है और मूल्य संवर्धन और मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता पर जोर देने के साथ ऐसे खनिजों की खोज और दोहन की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है।

3.0 राष्ट्रीय खनिज नीति 2019

खनिज और संसाधन क्षेत्र में नीतिगत अंतराल और न्यायिक हस्तक्षेप के एक लंबे चरण की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, भारत के खनिज और संसाधन क्षेत्र को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और संसाधन सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए बदलाव लाने के लिए फरवरी 2019 में राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 (एनएमपी 2019) पेश की गई है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो खनन क्षेत्र को बढ़ावा देंगे जैसे:

- क) आरपी/पीएल धारकों के लिए पहले इनकार के अधिकार का परिचय
- ख) निजी क्षेत्र को अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करना।
- ग) राजस्व हिस्सेदारी के आधार पर समग्र आरपी सह पीएल सह एमएल के लिए अछूते क्षेत्रों में नीलामी
- घ) खनन संस्थाओं के विलय और अधिग्रहण को प्रोत्साहन
- ङ) निजी क्षेत्र के खनन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए खनन पट्टों का हस्तांतरण और समर्पित खनिज गलियारों का निर्माण।
- च) निजी क्षेत्र के लिए खनन के वित्तपोषण को बढ़ावा देने और निजी क्षेत्र द्वारा अन्य देशों में खनिज संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए खनन गतिविधि को उद्योग का दर्जा देना।
- छ) इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि खनिज के लिए दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीति निजी क्षेत्र को बेहतर योजना और व्यवसाय में स्थिरता में मदद करेगी।
- ज) पीएसयू को दिए गए आरक्षित क्षेत्रों, जिनका उपयोग नहीं किया गया है, को तर्कसंगत बनाया जाए और इन क्षेत्रों को नीलामी में रखा जाए, जिससे निजी क्षेत्र को भागीदारी के लिए अधिक अवसर मिलेगा।
- i) नीति में निजी क्षेत्र की मदद के लिए करें, लेवी और रॉयल्टी को विश्व मानकों के साथ सुसंगत बनाने के प्रयास करने का भी उल्लेख है।

राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019 में पेश किए गए बदलावों में मेक इन इंडिया पहल पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। जहां तक खनिजों में विनियमन का सवाल है, ई-गवर्नेंस, आईटी सक्षम प्रणाली, जागरूकता और सूचना अभियान शामिल किए गए हैं। खनिज विकास में राज्य की भूमिका के संबंध में मंजूरी में देरी की स्थिति में उच्च स्तर पर ट्रिगर उत्पन्न करने के प्रावधान के साथ ऑनलाइन

सार्वजनिक पोर्टल रखा गया है। एनएमपी 2019 का लक्ष्य प्रोत्साहनों के माध्यम से निजी निवेश को आकर्षित करना है, जबकि खनन टेनमेंट सिस्टम के तहत खनिज संसाधनों और टेनमेंट का डेटाबेस बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा। नई नीति खनिजों की निकासी और परिवहन के लिए तटीय जलमार्गों और अंतर्देशीय शिपिंग के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करती है और खनिजों के परिवहन की सुविधा के लिए समर्पित खनिज गलियारों को प्रोत्साहित करती है। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों एवं क्षेत्रों के समान विकास हेतु जिला खनिज निधि का उपयोग। एनएमपी 2019 खनिज क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करने और बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक खनन गतिविधि में निवेश के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक दीर्घकालिक निर्यात-आयात नीति का प्रस्ताव करता है। 2019 की नीति अंतर-पीढ़ीगत इक्विटी की अवधारणा को भी पेश करती है जो न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की भलाई से संबंधित है और खनन में सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को संस्थागत बनाने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी निकाय के गठन का भी प्रस्ताव करती है।

4.0 अब तक किये गए पहल

4.1 नियमों में संशोधन

जैसा कि एनएमपी 2008 और एनएमपी 2019 में बताया गया है, पहले से ही विभिन्न उपाय शुरू किए गए हैं। 2015, 2016, 2020 और 2021 में खनिज क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले "खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957" में संशोधन के माध्यम से प्रमुख सुधार किए गए हैं। अधिक पारदर्शिता लाने, विवेक को दूर करने और व्यापार करने में अधिक आसानी लाने के लिए एमएमडीआर अधिनियम को 2015 में संशोधन द्वारा बदल दिया गया था। "खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015" को निम्नलिखित के लिए तंत्र स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है:

- क) खनिज संसाधनों के आवंटन में बेहतर पारदर्शिता;
- ख) सरकार के लिए ऐसे संसाधनों के मूल्य का उचित हिस्सा प्राप्त करना;
- ग) निजी निवेश और नवीनतम तकनीक को आकर्षित करना;
- घ) प्रशासन में देरी को समाप्त करना, ताकि देश के खनिज संसाधनों का शीघ्र और इष्टतम विकास संभव हो सके।

नई व्यवस्था द्वारा, खनिज ब्लॉकों के आवंटन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए खनिज रियायत देने के लिए ई-नीलामी अनिवार्य कर दी गई है। साथ ही सभी नए पट्टे 50 वर्षों के लिए दिए जाएंगे और व्यापार करने में आसानी और विवेकाधिकार को दूर करने के लिए नवीनीकरण और पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाएगा। खनन प्रभावित क्षेत्रों/लोगों के कल्याण के लिए स्थापित खनन पट्टा धारकों के योगदान के माध्यम से जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) की स्थापना का प्रावधान किया गया है। उक्त संशोधन में अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के लिए दंडात्मक प्रावधानों को बेहद सख्त बनाया गया है। इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान। अवैध खनन के मामलों की त्वरित सुनवाई की व्यवस्था की गई है। रॉयल्टी पर 2% उपकर लगाकर राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट (एनएमईटी) के निर्माण का प्रावधान किया गया है। संशोधन के कार्यान्वयन के लिए सभी अपेक्षित अधीनस्थ नियम तैयार और अधिसूचित किए गए। अब सभी कैप्टिव खदानों को संलग्न संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद वर्ष के दौरान उत्पादित खनिजों का 50% तक बेचने की अनुमति मिलती है। भविष्य की सभी नीलामियाँ बिना किसी अंतिम उपयोग प्रतिबंध के होंगी। इसके अलावा धारा 10ए(2)(बी) के तहत लंबित मामलों को नई नीलामी व्यवस्था के तहत लाकर उनका समाधान किया गया। इस संशोधन के माध्यम से 'खनन परिचालन' को 'उत्पादन और प्रेषण' से प्रतिस्थापित किया गया। इसके अलावा सरकारी कंपनियों के लिए आरक्षित गैर-उत्पादक ब्लॉकों के पुनः आवंटन के माध्यम से अब उत्पादन में खरीदा जा सकता है। इसके अलावा बिना किसी शुल्क के सभी खनिज रियायतों के हस्तांतरण की अनुमति दी गई है।

4.2 राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति 2016

अन्वेषण प्रयासों को और अधिक गति देने के लिए सरकार द्वारा 2016 में राष्ट्रीय खनिज गवेषण नीति 2016 (एनएमईपी) (गैर-ईंधन और गैर-कोयला के लिए) लाई गई है। नीति का उद्देश्य निजी एजेंसियों को पट्टा अवधि के दौरान राज्य सरकार को अर्जित राजस्व में निश्चित हिस्सेदारी के अधिकार के साथ पहचाने गए ब्लॉक/क्षेत्रों में गवेषण कार्य करने की अनुमति देना है, हस्तांतरणीय अधिकारों के साथ। नीति में कहा गया है कि इस प्रतिशत/राशि का भुगतान सफल बोलीदाताओं द्वारा संबंधित गवेषण एजेंसी को किया जाएगा

और यह तब निर्धारित किया जाएगा जब सफल गवेषण के आधार पर खनिज ब्लॉकों को ई-नीलामी पर रखा जाएगा। यह नीति विभिन्न प्रकार के खनिजों के लिए गवेषण की मानक लागत की गणना करने की दिशा में आगे बढ़ती है ताकि गवेषण एजेंसियों को मुआवजा दिया जा सके, यदि उन्हें अपने संबंधित क्षेत्रों में कोई खनन योग्य भंडार नहीं मिलता है।

4.3 सतत विकास ढाँचा कार्य

(Sustainable Development Framework)

जैसा कि राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 में परिकल्पना की गई है, सभी खनन गतिविधियों को सतत विकास ढाँचे (एसडीएफ) के मापदंडों के भीतर किया जाना आवश्यक है। एसडीएफ के कार्यान्वयन के एक भाग के रूप में, खान मंत्रालय ने भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से खानों की स्टार रेटिंग मूल्यांकन की एक अवधारणा पेश की है। स्टार रेटिंग योजना के तहत, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय भलाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समावेशी विकास को शामिल करते हुए, खनन पदचिह्नों के मूल्यांकन और खनन गतिविधि को शुरू करने की एक विश्वसनीय प्रणाली विकसित की गई है। इसे दो-स्तरीय प्रणाली के रूप में स्थापित किया गया है, जो आईबीएम पोर्टल के माध्यम से विकसित ऑनलाइन सिस्टम में खदान ऑपरेटर द्वारा भरे जाने वाले स्व-मूल्यांकन टेम्पलेट प्रदान करता है, जिसके बाद आईबीएम के माध्यम से सत्यापन किया जाता है। खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 के नियम 35(2) के अनुसार, खनन पट्टे के प्रत्येक धारक को समय-समय पर आईबीएम अधिसूचित टेम्पलेट्स के अनुसार खनन और संबद्ध गतिविधियों की निगरानी करनी होती है और खनन पट्टा क्षेत्र की डिजिटल छवियों की सॉफ्ट कॉपी (ड्रोन सर्वेक्षण / भू-संदर्भित ऑर्थो-रेक्टिफाइड मल्टीस्पेक्ट्रल उपग्रह छवि से डीईएम और ऑर्थोमोज़ेक छवियाँ) की सॉफ्ट कॉपी के साथ पिछले वित्तीय वर्ष के लिए हर साल 1 जुलाई से पहले ऑनलाइन स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट जमा करने की आवश्यकता होती है।

4.4 जिला खनिज फाउंडेशन (District Mineral Foundation)

डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) का उद्देश्य खनन क्षेत्रों में

स्थानीय लोगों की समावेशी विकास की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। डीएमएफ के लिए धनराशि मौजूदा खनिकों द्वारा रॉयल्टी के 30% और एमएमडीआर संशोधन के बाद खदानों से प्राप्त खनिकों द्वारा 10% के अतिरिक्त योगदान से पूरी की जा रही है। सरकार ने संबंधित जिलों के डीएमएफ द्वारा कार्यान्वित करने के लिए प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) तैयार की है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16.09.2015 को अधिनियम की धारा 20ए के तहत निर्देश जारी किये गये हैं। पीएमकेकेकेवाई ने 60% धनराशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे पेयजल / पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण / स्वास्थ्य देखभाल / शिक्षा / कौशल विकास / महिलाओं, बच्चों, वृद्ध और विकलांग लोगों के कल्याण / स्वच्छता के लिए किया जाना अनिवार्य किया है और शेष 40% धनराशि का उपयोग बुनियादी ढांचे - सड़क और भौतिक बुनियादी ढांचे / सिंचाई / वाटरशेड विकास के लिए किया जा सकता है। पीएमकेकेकेवाई के तहत कार्यान्वित परियोजनाएं एक अनुकूल खनन वातावरण बनाने, प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति में सुधार करने और हितधारकों के लिए जीत-जीत की स्थिति बनाने में मदद करेंगी।

4.5 खनन निगरानी प्रणाली (Mining Surveillance System)

खान मंत्रालय ने, भारतीय खान ब्यूरो के माध्यम से, देश में अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने में राज्य सरकारों की सुविधा के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) और भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी), गांधीनगर के सहयोग से खनन निगरानी प्रणाली (एमएसएस) विकसित की है। एमएसएस एक उपग्रह-आधारित निगरानी प्रणाली है जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को सुविधा प्रदान करके, सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से उत्तरदायी खनिज प्रशासन की व्यवस्था स्थापित करना और अवैध खनन की घटनाओं पर अंकुश लगाना है। खनन पट्टा क्षेत्र की सीमा से 500 मीटर तक के क्षेत्र में उपग्रह इमेजरी पर देखी गई किसी भी असामान्य भूमि उपयोग परिवर्तन गतिविधि को पकड़ लिया जाता है और ट्रिगर के रूप में चिह्नित किया जाता है, जिसमें अवैध खनन भी शामिल हो

सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के साथ सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग दूरदराज के क्षेत्रों तक आसान पहुंच सहित खनन पट्टों की त्वरित, पारदर्शी और आवधिक निगरानी प्रदान करेगा। एमएसएस में खनन अधिकारियों के उपयोग के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल मोबाइल-ऐप भी शामिल है जो अलर्ट प्राप्त करेगा, फ़ील्ड सत्यापन करेगा और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस मोबाइल ऐप का उद्देश्य एक सहभागी निगरानी प्रणाली स्थापित करना भी है जहां नागरिक भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं और असामान्य खनन गतिविधि की रिपोर्ट कर सकते हैं जो एक ट्रिगर के रूप में उत्पन्न होगी। ट्रिगर का स्थल सत्यापन संबंधित राज्यों के खनन विभागों के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा, जो अवैध खनन के मामलों में उचित कार्रवाई भी करेंगे।

4.6 खनन टेनेमेंट प्रणाली (Mining Tenement System)

माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम (एमटीएस) कोयला, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर प्रमुख खनिजों के लिए दी गई प्रत्येक खनन रियायत के संपूर्ण जीवन चक्र विश्लेषण का एक डिजिटल भंडार है। इसमें शासन के विभिन्न स्तरों पर सभी प्रक्रियाओं और अनुमोदनों का स्वचालन शामिल है, जिससे संभावित खनिज वाले क्षेत्रों की पहचान से लेकर खनन गतिविधि बंद होने के बाद तक की सभी गतिविधियों का मानचित्रण किया जाता है, जिससे भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) इंटरफ़ेस के साथ इलेक्ट्रॉनिक डेटा और फ़ाइलों का वास्तविक समय पर स्थानांतरण सक्षम हो जाता है। इस प्रणाली की परिकल्पना मुख्य रूप से कुशल, प्रभावी और पारदर्शी वितरण के लिए भारतीय खान ब्यूरो की कार्यप्रणाली को बदलने के लिए की गई है, जिसमें देश भर के राज्यों के राज्य खनन विभागों को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले विकल्प के अनुसार बोर्ड पर लाने का प्रावधान है। यह ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली जीआईएस में दृश्य ग्राफिक रूप और रजिस्ट्री घटक के रूप में ज्ञात पाठ्य रूप में जानकारी प्रदान करेगी। परियोजना में रखे जाने वाले सूचना डेटा बेस में रियायतों की अवधि, कार्यकाल की सुरक्षा, खनिज रियायत देने के मानदंड, पीएल की हस्तांतरणीयता, क्षेत्रों का आरक्षण, खनिज रियायतों के अनुदान का विवरण, विवाद, वन विवरण, एमओईएफ मंजूरी, बुनियादी ढांचे, कराधान, अवैध

खनन, कैप्टिव खदानें, निर्यात-आयात आदि शामिल हैं। परियोजना का कार्यान्वयन आईबीएम द्वारा पहले ही शुरू कर दिया गया है। परियोजनाओं में चरण-1 के तहत पंजीकरण और ऑनलाइन रिटर्न, खनन योजना, पीएमकेकेवाई और अयस्क लेखा प्रणाली जैसे मॉड्यूल का विकास और संचालन शामिल है। चरण-2 में, रियायतें देना, रियायत प्रबंधन और निरीक्षण, आईबीएम डेटाबेस का परिवर्तन, जीआईएस प्लेटफॉर्म, खानों की संशोधन और स्टार रेटिंग जैसे मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे।

4.7 उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग

भारतीय खान ब्यूरो ने चयनित खानों के समूह में खनन गतिविधियों/परिवर्तनों की निगरानी में उच्च रिज़ॉल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी और डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) का उपयोग करने की व्यवहार्यता प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट "सुदूर दृष्टि" के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। रिमोट सेंसिंग प्रयोगशालाओं की स्थापना के संबंध में, एनआरएससी ने सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और खरीद प्रक्रियाओं के तकनीकी विनिर्देश को अंतिम रूप देने में आईबीएम का मार्गदर्शन किया है। आईबीएम ने लैब के लिए सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खरीद लिए हैं। नागपुर और हैदराबाद में रिमोट सेंसिंग लैब पहले ही स्थापित हो चुकी हैं।

खनिज संरक्षण और विकास नियम 2017 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं, जिससे खनिज रियायत धारकों को आईबीएम को ड्रोन

छवियां और उपग्रह इमेजरी जमा करना अनिवार्य हो गया है। इन छवियों के आधार पर देश में खनन गतिविधियों पर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के दूर से निगरानी करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रस्ताव है। ड्रोन छवियों का उपयोग करके खानों के भौतिक निरीक्षण के बिना खनन योजनाओं को मंजूरी देने की भी परिकल्पना की गई है। देश के खनन क्षेत्रों की भूमि उपयोग की छवियों का एक डेटा बैंक बनाने और उनके व्यवस्थित और वैज्ञानिक खदान बंद करने के लिए प्रभावी ढंग से योजना बनाने का भी प्रस्ताव है। ड्रोन के उपयोग में अपार संभावनाएं हैं जो खनन परियोजना के पूरे जीवन चक्र में कई डेटा और सूचना कैप्चरिंग गतिविधियों को स्वचालित कर सकती हैं जो अंततः टिकाऊ, न्यायसंगत और पारदर्शी संचालन को जन्म दे सकती हैं जिससे खनिक और नियामक दोनों के लिए जीत की स्थिति बन सकती है।

निष्कर्ष :-

भारतीय खनिज उद्योग ने एक लंबा सफर तय किया है। समय बीतने के साथ, समसामयिक आवश्यकताओं के अनुरूप कई सुधार किये गये हैं। हालाँकि, इसके बावजूद, राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में खनन उद्योग की हिस्सेदारी अभी भी पर्याप्त नहीं है। एमएमडीआर 2015 संशोधनों के रूप में प्रमुख सुधारों को प्रभावी करके, एनएमईपी 2016 और एनएमपी 2019 को अपनाने के साथ-साथ पहले से निष्पादित और विचाराधीन परियोजनाओं की कई पहलों के साथ, यह उम्मीद की जाती है कि भारतीय खनिज उद्योग विश्व में अग्रणी खनिज उत्पादक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है।

वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते कदम



अभिनय कुमार शर्मा

संपादक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

वैश्वीकरण अपने प्रभाव को लगातार बढ़ा रहा है और भाषा वैश्वीकरण की चुनौतियों को अथवा विश्व पटल पर कंधे से कंधा मिलाकर चलने में एक निर्णायक भूमिका अदा करती है। भूमंडलीकरण के इस आरंभिक दौर में हिंदी ने स्वयं को राष्ट्र की बिंदी सिद्ध किया है। वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप विकसित हो रहा है और डिजिटल मीडिया इस स्वरूप को विकसित करने में अपनी निर्णायक भूमिका निभा रहा है। वो हिंदी को अफ्रीका, मध्य पूर्व यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एक चित्तार्कषक ढंग से लगातार पहुँचा रहा है। यह उत्साहजनक है कि वर्ष 2022 के आंकड़ों के हिसाब से विश्व के लगभग 44 प्रतिशत लोगों द्वारा (लगभग 615 मिलियन) हिंदी भाषा बोली जाती है। इस तरह से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है।

भूमंडलीय आकाश पर पैर पसारती हिंदी अपने अनेक बहुआयामी स्वरूप प्रदर्शित कर रही है। सिंगापुर में हिंदी कक्षाओं वाले स्कूलों की संख्या बढ़कर 53 हो गयी है। ब्रिटेन में भी 'हिंगलिश' बहुत अधिक प्रचलित है। रूसी लोगों के हृदय में हिंदी के प्रति आकर्षण का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन्होंने रामायण का हिंदी में अनुवाद कराया है और बहुत से रूसी हिंदी लिख-पढ़ रहे हैं। हिंदी भारत में ही नहीं पाकिस्तान में भी बोली जाती है। दोनों देशों के नागरिकों द्वारा हिंदी भाषा को व्यापक एवं सक्षम आधार प्रदान

किया जा रहा है। नेपाल के तो आधे हिस्से की पूरी तराई की भाषा हिंदी है। यहाँ तक कि वहाँ की लिपि भी देवनागरी ही है। चीनवासियों ने हिंदी प्रेम के चलते पीकिंग विश्वविद्यालय में हिंदी की पढ़ाई की समुचित व्यवस्था की है। अफ्रीका महादेश हो या फिजी द्वीप समूह, मॉरीशस आदि में हिंदी की कीर्ति पताका फहरा रही है। फिजी में तो हिंदी वहाँ कि राजभाषा घोषित की गयी है। बहुत सी नौकरी प्रदाता एजेंसीज हिंदी सीखे हुए भारतीयों की अनुवादक के रूप में रिक्तियां निकाल रही हैं। हिंदी की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रही है। इसका सबसे उत्तम उदाहरण गीतांजलि श्री हैं। उनके हिंदी में लिखे गए उपन्यास "रेत समाधी (Tomb of Sand)" के लिए उन्हें वर्ष 2022 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। गीतांजलि श्री हिंदी की पहली ऐसी लेखिका हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ये हिंदी भाषा के लिए गौरव की बात है।

हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय महत्व इसी से लगाया जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में अपना लिया गया है। इन प्रयासों के हिस्से के रूप में, 'हिंदी @ यूएन' परियोजना 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा में संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक पहुँच को बढ़ाना और दुनिया भर में लाखों हिंदी भाषी आबादी के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता फैलाना था। हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषाओं में शामिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि विश्व हिंदी दिवस 2022 के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के विश्व विरासत केंद्र ने 10 जनवरी 2022 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के हिंदी भाषा में विवरण प्रकाशित करने पर सहमति दी है। संयुक्त राष्ट्र में अब हमारे प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भी अभिभाषण दिया गया था।

**"मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारें आरती
भगवान पूरे विश्व में गूँजे हमारी भारती।"**

हिंदी को विदेशों में ले जाने पर जोर मुख्य रूप से उन देशों में भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के लिए था जहां भारतीयों का एक बड़ा अनुपात है। ये मॉरीशस, फिजी, सूरीनाम, गुयाना के साथ-साथ त्रिनिदाद और टोबैगो में पूर्व गिरमिटिया मजदूरों के बच्चे थे। उनके कई पूर्वज हिंदी भाषी थे, इसलिए भारत को इन समुदायों के साथ हिंदी के माध्यम से संबंध स्थापित करने की उम्मीद थी। हिंदी के प्रचार प्रसार को गति देने के लिए भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में 'हिंदी एवं संस्कृत प्रभाग' का गठन किया गया है। यह विदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित करता है। यह अपने विदेश स्थित दूतावासों के माध्यम से हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटी संस्थाओं को हिंदी कक्षाएं आयोजित करने एवं अन्य गतिविधियों के लिए अनुदान देता है। साथ ही ये विदेशों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलनों का भी आयोजन करता है।

आज भारत विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतरराष्ट्रीय

बिरादरी को हिंदी और हिन्दुस्तान दोनों के महत्व को स्वीकार करना ही होगा। जहाँ तक देश के बाहर किये जाने वाले प्रयासों की बात है तो समय - समय पर आयोजित होने वाले विश्व हिंदी सम्मलेनों में हिंदी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए ठोस एवं परिणामजनक नीतियां तैयार की जानी चाहिये। भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस उसी दिशा में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। इसके साथ -साथ किये गए प्रयासों का समय - समय पर मूल्यांकन भी नितांत आवश्यक है। हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए मिलजुलकर ही प्रयास करने होंगे। हिंदी को विश्व की अन्य समस्त महत्वपूर्ण भाषाओं के समकक्ष लाकर खड़ा करने में भारत के प्रत्येक नागरिक को अपना योगदान देना आवश्यक है। क्योंकि अपनी भाषा की यदि प्रगति होगी तो स्वयं की प्रगति होगी और यदि स्वयं की प्रगति होगी तो देश की भी उन्नति होगी। परिणामस्वरूप भाषा का वैश्विक कद बढ़ेगा। जैसा कि हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने भी कहा है -

“

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल ।
बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल ।

”

- भारतेन्दु हरिश्चंद्र

वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते कदम



पुखराज नेणिवाल

क्षेत्रीय खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

हिंदी के नाम व शब्द का सम्बन्ध संस्कृत भाषा के शब्द 'सिंधु' के नाम से जाना जाता है। सिंधु सिंधु नदी को कहते थे। यह शब्द ईरान में जाकर 'हिन्दू' और फिर 'हिन्द' हो गया। बाद में यह शब्द धीरे-धीरे भारत का वाचक बन गया। इस तरह हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली सहस्र बोलियों की द्योतक है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में होता है। मानक हिंदी पर जिन सहस्र बोलियों का प्रभाव है, इस कारण मानक हिंदी की तीन शैलियाँ प्रचलित हैं - ये हैं संस्कृतनिष्ठ शैली, हिंदुस्तानी शैली और उर्दू शैली। संस्कृतनिष्ठ शैली में खड़ी बोली और दक्षिणी हिंदी आती है। हिंदुस्तानी शैली में हिंदवी हिंदुस्तानी रेखा शामिल है। उर्दू शैली में अरबी - फ़ारसी शैली है।

इस प्रकार हिंदी एक महान भाषा है, जिसमें अनेकों रहस्य छिपे हैं जो सदियों के इतिहास की गाथा कहते हैं। हिंदी भाषा कड़े संघर्ष के बाद वर्तमान स्थिति तक पहुँचती है। हिंदी भाषा के विकास में उत्तर भक्तिकाल के प्रमुख कवि सूरदास, तुलसीदास व मीराबाई को बड़े शौक से गाया जाता है। इसकी सरलता के कारण लोग इसे कंठस्थ करते हैं। हिंदी भाषा अपनी सरलता, सुगमता और स्पष्टता के लिए जानी जाती है। दक्षिण भारत के प्रमुख संत वल्लभाचार्य, विठ्ठल, रामानुज, रामानंद आदि ने भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया।

हिंदी एक आधुनिक एवं पूर्णतया वैज्ञानिक भाषा है जिसमें सम्प्रेषण की अद्भुत शक्ति है। माइक्रो-सॉफ्ट के अध्यक्ष 'बिल गेट्स' के अनुसार 'हिंदी' विश्व की अन्य भाषाओं की तुलना में सबसे वैज्ञानिक भाषा है। यही कारण है कि हिंदी भारत की सीमा से बाहर निकलकर विश्व धरातल पर पहुँच चुकी है। विश्व के लगभग 145 विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में हिंदी पढाई जाती है। विदेशों में हिंदी सीखनेवालों की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है। विदेशी छात्रों के इस झुकाव के कारण देश के कई विश्वविद्यालय इन छात्रों को हमारे देश की संस्कृति एवं ज्ञानार्जन के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। चीन, जापान, कोरिया, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली और पोलैंड जैसे देशों में हिंदी सीखने वालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हो रही है।



हिंदी को वैश्विक रूप प्रदान करने में सूचना, प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर, टेलीविजन और साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसका सबसे सटीक उदाहरण है कि जब बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपना व्यापार जब भारत में शुरू करती हैं तो अपने प्रचार-प्रसार के लिए के लिए वे हिंदी का ही सहारा लेती हैं। यह इसी बात को इंगित करता है कि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी का निरंतर विस्तार हो रहा है। हिन्दी वैश्विक परिदृश्य में अपनी जगह बना रही है। आज जब भाषाएं खत्म हो रही हैं, हिन्दी निरंतर फैल रही है। दुनिया भर में इसका विस्तार हो रहा है।

आज का समय भूमण्डलीकरण का है, जिसका असली चेहरा बाजार के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तेजी से फैलती बाजार संस्कृति ने हमारे अस्तित्व, खानपान, पहनावा, भाषा, संस्कृति आदि को प्रभावित किया है। आज दुनिया में लगभग साठ हजार भाषाएं किसी न किसी रूप में बोली और समझी जाती हैं, लेकिन आने वाले समय में नब्बे प्रतिशत से अधिक का अस्तित्व खतरे में है। भाषाओं के इस विलुप्तिकरण के दौर में हिन्दी न केवल अपने को बचाने में सफल रही है, बल्कि उसका उपयोग-अनुप्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। संप्रति हिन्दी को अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है क्योंकि यह अनेक विदेशी भाषाओं को न केवल स्वीकार करती बल्कि विश्व

की समस्त भाषाओं को आत्मसात करने की क्षमता रखती है। विश्व हिन्दी का केन्द्रीय सचिवालय मॉरिशस में बनना और हिन्दी के प्रोद्योगिकी से जोड़ने के लिए किये जाने वाले सतत प्रयास इसे संयुक्त राष्ट्र की भाषाओं में स्थान दिलाने का प्रयास है।

आज के वैश्विक फलक पर हिन्दी स्वयं को एक संपर्क भाषा, प्रचार भाषा, और राजभाषा के साथ साथ वैश्विक भाषा के रूप में स्वयं को स्थापित करती जा रही है। देखा जाय तो विश्व में चीनी भाषा मन्डारिन के बाद हिन्दी का दूसरा स्थान है। जयंती प्रसाद कौटिल्य अपने सर्वेक्षण में तो हिन्दी को प्रथम स्थान पर पहुँचने का बात करते हैं। इस क्रम में अंग्रेजी आज तीसरे पायदान पर है। कम्प्यूटर, मोबाइल और आई-पैड पर हिन्दी की पहुंच ने यह बात सिद्ध कर दी है कि आने वाले समय में इंटरनेट की भाषा अंग्रेजी न होकर हिन्दी होगी।

जापान में आज 26 विदेशी भाषाएँ पढ़ाई जाती हैं जिसमें हिन्दी भी शामिल है। इसी प्रकार अमेरिका की भाषा नीति में दस नई विदेशी भाषाओं को जोड़ा गया है, जिनमें हिन्दी भी शामिल है। हिन्दी शिक्षा के लिये डरबन में हिन्दी भवन का निर्माण किया गया है। जापान और अमेरिका में एफ एम रेडियो स्टेशन जो भारतीय संगीत का प्रसारण करते हुए हिन्दी का प्रचार-प्रसार करने में सतत प्रयासरत है। मॉरिशस में हिन्दी का वर्चस्व है तथा उनका संकल्प हिन्दी को विश्व भाषा बनाने का है। सन् 1996 में वहाँ हिन्दी साहित्य अकादमी की स्थापना हुई और उनकी दो पत्रिकाएँ बसंत और रिमझिम प्रकाशित हो रही हैं। अब तक हुए ग्यारह विश्व हिन्दी सम्मेलनों में से तीन मॉरिशस में आयोजित हुए। हिन्दी के प्रयोग को लेकर इसे छोटा भारत भी कहा जाता है। सूरीनाम में भी हिन्दी का व्यापक प्रचार प्रसार है।

विदेशों से प्रकाशित हिन्दी पत्रिकाओं ने भी हिन्दी को वैश्विक फलक पर ले जाने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं में अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी समिति (संयुक्त राज्य अमीरात), मॉरिशस हिन्दी संस्थान, विश्व हिन्दी सचिवालय, हिन्दी संगठन (मॉरिशस), हिन्दी सोसायटी (सिंगापुर), हिन्दी परिषद (नीदरलैण्ड) आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम के अधिकतर देशों चीन, श्रीलंका, कंबोडिया,

लाओस, थाइलैण्ड, मलेशिया, जावा आदि में रामलीला के माध्यम से राम के चरित्र पर आधारित कक्षाओं का मंचन किया जाता है। वहाँ के स्कूली पाठ्यक्रम में रामलीला को शामिल किया गया है। हिन्दी की रामकथायें भारतीय सभ्यता और संस्कृति का वाहक बन चुकी हैं। रेडियो सीलोन और श्रीलंकाई सिनेमा घरों में चल रही हिन्दी फिल्मों के माध्यम से हिन्दी की उपस्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ इस बात से भली-भाँति अवगत हैं कि भारत उनके उत्पाद का बड़ा बाजार है और यहाँ के अधिकतर उपभोक्ता हिन्दी-भाषी हैं, इसलिए उन्हें अपना उत्पाद बेचने के लिए उसका प्रचार प्रसार हिन्दी में करना पड़ेगा।

आज जब इक्कीसवीं सदी में वैश्वीकरण के दबावों के चलते विश्व की तमाम संस्कृतियाँ एवं भाषाएँ आदान-प्रदान व संवाद की प्रक्रिया से गुजर रही हैं तो हिंदी इस दिशा में विश्व मानवता को निकट लाने के लिए सेतु का कार्य कर सकती है। उसके पास पहले से ही बहुसांस्कृतिक परिवेश में सक्रिय रहने का अनुभव है जिससे वह अपेक्षाकृत ज्यादा रचनात्मक भूमिका निभाने की स्थिति में है। हिंदी सिनेमा अपने संवादों एवं गीतों के कारण विश्व स्तर पर लोकप्रिय हुए हैं। उसने सदा-सर्वदा से विश्वमन को जोड़ा है। हिंदी की मूल प्रकृति लोकतांत्रिक तथा रागात्मक संबंध निर्मित करने की रही है। वह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ही राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिजी, मॉरिशस, गुयाना, त्रिनिदाद तथा सुरिनाम जैसे देशों की सम्पर्क भाषा भी है। वह भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के बीच खाड़ी देशों, मध्य एशियाई देशों, रूस, समूचे यूरोप, कनाडा, अमेरिका तथा मैक्सिको जैसे प्रभावशाली देशों में रागात्मक जुड़ाव तथा विचार-विनिमय का सबल माध्यम है। यदि निकट भविष्य में बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था निर्मित होती है और संयुक्त राष्ट्र संघ का लोकतांत्रिक ढंग से विस्तार करते हुए भारत को स्थायी प्रतिनिधित्व मिलता है तो वह यथाशीघ्र इस शीर्ष विश्व संस्था की भाषा बन जाएगी। सारांश यह है कि हिंदी विश्वभाषा बनने की दिशा में उत्तरोत्तर अग्रसर है।

सर्क्युलर इकाँनोमी टेलिनियर इकाँनोमी



अचिंत गोयल

उप-अयस्क प्रसाधन अधिकारी एवं कार्यालय प्रभारी
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

शहरी खनन लंबे समय तक जीवित रहने वाले उत्पादों, इमारतों बुनियादी ढाँचे और अवशेषों से कच्चे माल को पुनर्प्राप्त करने के उद्देश्य से मानवजनित स्टॉक का अभिन्न प्रबंधन है। शहरी खनन न केवल आज के कचरे का प्रबंधन करने का प्रयास करता है, बल्कि कल के कचरे में निहित मूल्य का अनुमान लगाता है और उसके निष्पादन का मार्ग भी खोजता है। देश में लगभग 600 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता हैं। भारतीय बाजार के 2023 में स्मार्टफोन 10 प्रतिशत बढ़कर 175 मिलियन यूनिट तक पहुँचने का अनुमान है। भारत में 2040 तक स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या 1 बिलियन से अधिक होने का अनुमान है। यह ई-कचरे के एक विशाल ढेर को इंगित करता है जिसका खनन किया जा सकता है। ई-कचरे में जबरदस्त क्षमता है। देश में ई-कचरा संग्रह और प्रबंधन की अपार संभावनाएँ हैं। भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ई-कचरा उत्पादक है। फिर भी इसका केवल 1/5वां हिस्सा सरकार द्वारा अनुमोदित केन्द्रों के माध्यम से पुनर्नवीनीकरण किया जाता है। इस क्रम में आगे चलकर अर्बन माइनिंग में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अपार संभावनाएँ हैं जो फोन रिसाइकल किए जाते हैं, उनमें से गोल्ड और कॉपर जैसे तत्व फिर से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एप्पल ने अनुमान लगाया है

कि एक मीट्रिक टन आइफोन में से सामग्री रिसाइकल की जाए तो धरती से 2000 मीट्रिक टन से मटेरियल कम खनन करना पड़ेगा इसके फायदा ये है कि ई-वेस्ट से विंड एनर्जी टर्बाइन, इलेक्ट्रिक कार बैटरी या सौर पैनल जैसे उपकरण बनते हैं जो धरती को हरा - भरा रखने के लिए अच्छे हैं।

जैसा कि मध्य अमरीकी देश कोस्टारिका ने पर्यावरण पर बढ़ते खतरे और संसाधनों की बचत के लिए खनन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसकी आबादी भले ही भारत के किसी टियर टू सिटी के बराबर है, पर रिसोर्स मैनेजमेंट का इसने रोल मॉडल पेश किया है। पुरानी बैटरियों से सफेद सोना कहा जाने वाला लिथियम निकालने में यह छोटा-सा देश बड़ी आर्थिक महाशक्तियों को पीछे छोड़ चुका है। रेअर अर्थ एलिमेंट और बैटरी मिनरल्स, लिथियम, निकेल, कोबाल्ट और ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक चीन खनन से अधिक जोर पुरानी वस्तुओं से इन्हें हासिल करने पर दे रहा है। जापान परंपरागत माइनिंग एक्टिविटीज़ के बिना नए जमाने के उर्जा खनिज के मामले में आत्मनिर्भर हो चुका है। याद करिए, 2020 का टोक्यो ओलंपिक, जहां पदक विजेताओं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से हासिल गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉज के बने 5000 मेडल दिए गए थे। यह सब इन देशों में अर्बन माइनिंग से संभव हो रहा है।

माइनिंग शब्द का जिक्र होते ही जेहन में महँगी धातुओं के खनन की तस्वीर सामने आती है। अर्बन माइनिंग, शहरी खननबद्ध परंपरागत माइनिंग से ठीक उलटा है। जापान की तोहूकू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिडियो नांज्यो ने पहली बार 1980 में इस शब्द का प्रयोग किया। इसमें कोयले, लौह अयस्क या बौक्साईट के खनन जैसी गतिविधि नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं से पैदा वेस्ट से महँगे खनिज और धातुएं निकाली जाती हैं। इस व्यवस्था में ई-कबाड़ का ढेर दुर्लभ खनिज का स्रोत साबित होता है, जिन्हें शहरी खदान या अरबन माइंस कहते हैं। 2018 के इकोनॉमिक्स सर्वे के मुताबिक शहरी ई-वेस्ट से 6,900 करोड़ रूपए का सोना हासिल किया जा

सकता है। लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, एलुमिनियम, सिल्वर और पैलेडियम जैसी महँगी धातुओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक कबाड़ अच्छा स्रोत है। यूएस इनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए की रिपोर्ट कहती है कि एक मीट्रिक टन मोबाइल से 300 ग्राम सोना निकाल सकते हैं। परंपरागत खनन में सोने के अयस्क से प्रति टन महज दो या तीन ग्राम सोना ही मिलता है। अरबन माइनिंग की यह व्यवस्था किसी सामान के दोबारा उपयोग और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देती है। इससे नए संसाधनों पर दबाव कम होगा और कच्चे माल की कमी पूरी होगी। इसे बढ़ावा देकर हम परंपरागत खनन में लगने वाली लागत, पर्यावरणीय नुकसान और वर्कफोर्स के संकट को दूर कर सकते हैं।

2015 में हुए पेरिस समझौते को लागू करने के दौरान अगले बीस साल में धरती के नीचे छिपे खनिजों की मांग चार गुना अधिक होगी। ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए कॉपर और ई-वाहनों में लिथियम, सोलर पैनल में सिलिकॉन और विंड टरबाइन के लिए जिंक की मांग पूरी करना बड़ी चुनौती है। अरबन माइनिंग के जरिए हम इन महँगी धातुओं को दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। वैसे संसाधनों के बेहतर उपयोग में भारतीयों का दुनिया में कोई सानी नहीं है।

हमारे लिए जुगाड़ टेक्नोलॉजी सिर्फ सोशल मीडिया के मीम्स नहीं। पुरानी वस्तुओं से नए सामान बनाकर उन्हें उपयोग में लेने की सर्कुलरकुलर इकोनॉमिक के सेंकड़ों देसी उपाय हमारे घरों में मिल जाएंगे। जरूरत रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर विरासत से मिले ज्ञान को संस्थागत रूप देने की है। पिछले साल पर्यावरण मंत्रालय द्वारा न्यू बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 लागू किया गया है। इसमें प्रोड्यूसर, डीलर और कंज्यूमर की जिम्मेदारी तय की गई है। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की निगरानी में ईपीआर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉसिबिलिटी का तंत्र खड़ा किया जा रहा है। इससे कंपनियां कितनी बैटरी तैयार कर रही है, रिसाइकलिंग अनुपात क्या है, जैसी जानकारी मिलती है।

बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट के नए नियम अरबन माइनिंग को बढ़ावा देंगे पर इसके लिए हमें कुछ अहम कदम उठाने होंगे। पहला,

ई-वेस्ट एकत्र करने की व्यवस्था मजबूत हो। उपयोग में नहीं लाए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक साजो सामान को कहाँ और कैसे सौंपे इसकी जानकारी सर्वसुलभ हो। दूसरा, हमें ऐसी तकनीक हासिल करनी होगी जो पुरानी वस्तुओं से महँगी धातुएं आसानी से निकाल सके। तीसरा, जरूरी नहीं पुरानी वस्तुओं से हासिल धातुओं की क्वालिटी पहले जैसी हो। ऐसे में इन मिनरल और मेटल को दोबारा कैसे और कहाँ उपयोग में लाया जाए इसके विकल्प तैयार करने होंगे। चौथा, प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग ऐसे की जाए कि उसमें इस्तेमाल खनिज और महँगे एलिमेंट को रिकवर और रीयूज़ किया जा सके। अंत में कंस्ट्रक्शन से लेकर हर उस क्षेत्र को अरबन माइनिंग के दायरे में लाया जाए जहाँ वेस्ट से वेल्थ क्रिएशन के अवसर मौजूद है।

तथ्य यह दावा करते हैं कि वर्तमान में केवल 17 प्रतिशत घरेलू सामान डीकम्पोज़िटिंग और रिसाइकलिंग के माध्यम से इकोनॉमी में वापस आ पाता है बाकि सदा के लिये खो दिया जाता है जिसकी कीमत हमारे स्वास्थ्य, प्लेनेट और इकोनॉमी को भुगतनी पड़ती है।

जिसके लिये 5 रणनीति को अपनाना होगा
Refuse -> Reduce -> Reuse -> Repair -> Recycle

लिनीअर इकोनॉमी : निपटान के बाद बिना किसी मूल्य प्रतिधारण या योगदान के बस लिया, बनाया,वेस्ट में फेक दिया पैटर्न का पालन करता है।

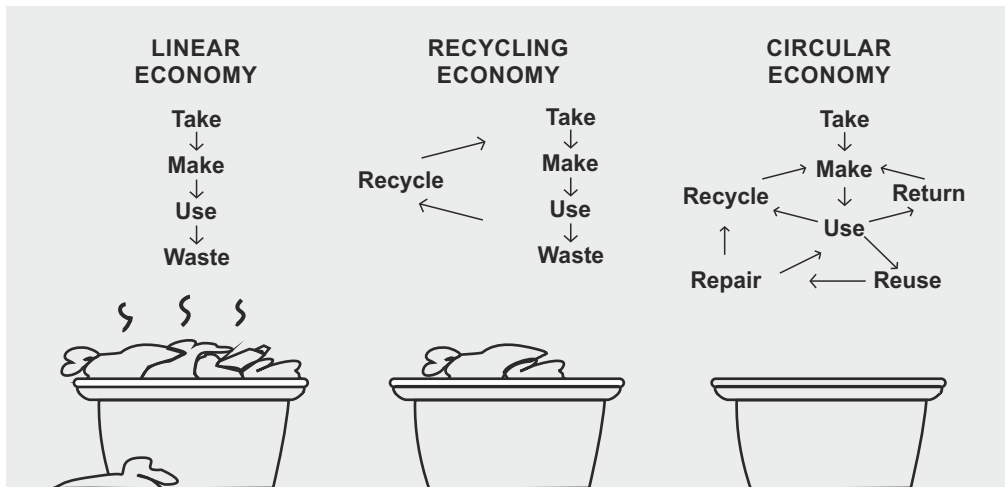
रीसाइक्लिंग इकोनॉमी : उत्पादों को नए उत्पादों में पुनर्चक्रित करके जीवन के अंत से मूल्य पुनःप्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है लेकिन गुणवत्ता और मूल्य हानि में सीमाओं का सामना करता है साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी पुनः चक्रण प्रणाली चरमरा गई है।

सर्क्युलर इकोनॉमी : अपशिष्ट में कमी, उत्पाद साझाकरण, नवीनीकरण और अपसाइक्लिंग जैसी रणनीतियों को शामिल करके सिस्टम में सामग्री के मूल्य को बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया।



Source : www.visualcapital.com

रेखा-चित्र : 1 के माध्यम से स्मार्ट फोन को बनाने में उपयोग में ली जाने वाली सभी क्रिटिकल मेटल्स को दिखलाया गया है



Source : www.visualcapital.com

रेखा-चित्र : 2 के माध्यम से लिनीअर इकॉनोमी, रीसाइक्लिंग इकोनॉमी एवं सर्क्युलर इकोनॉमी के बीच अंतर को दिखलाया गया है।

IT'S OKAY!

To repeat cloths. 🧥

Not to upgrade your phone. 📱

To buy second hand items. 🚗

To live in a simple home. 🏠

It's okay to live a simple life.

Source : www.visualcapital.com

रेखा-चित्र : 3 के माध्यम से सर्क्युलर इकोनॉमी के लिए अपनाये जाने वाले मौलिक सिद्धांतों को दिखलाया गया है।

वर्तमान परिदृश्य में भारतीय खनन उद्योग



गौरव शर्मा
खनिज अर्थशास्त्री
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

1. राष्ट्रीय खनिज परिदृश्य

खनिज सीमित और गैर-नवीकरणीय होने के कारण मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन हैं। वे कई बुनियादी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं और विकास के लिए एक प्रमुख संसाधन हैं। भारत में खनिज

निष्कर्षण का इतिहास हड़प्पा सभ्यता के दिनों का है। प्रचुर मात्रा में खनिजों के समृद्ध भंडार की व्यापक उपलब्धता ने इसे भारत में खनन क्षेत्र की वृद्धि और विकास के लिए बहुत अनुकूल बना दिया है।

देश कई धात्विक और गैर-धात्विक खनिजों के विशाल संसाधनों से संपन्न है। खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। स्वतंत्रता के बाद से, मात्रा और मूल्य दोनों के संदर्भ में खनिज उत्पादन में स्पष्ट वृद्धि हुई है। भारत लगभग 95 खनिजों का उत्पादन करता है, जिसमें ईंधन, धातु, गैर-धातु, परमाणु और लघु खनिज (भवन और अन्य सामग्री सहित) शामिल हैं।

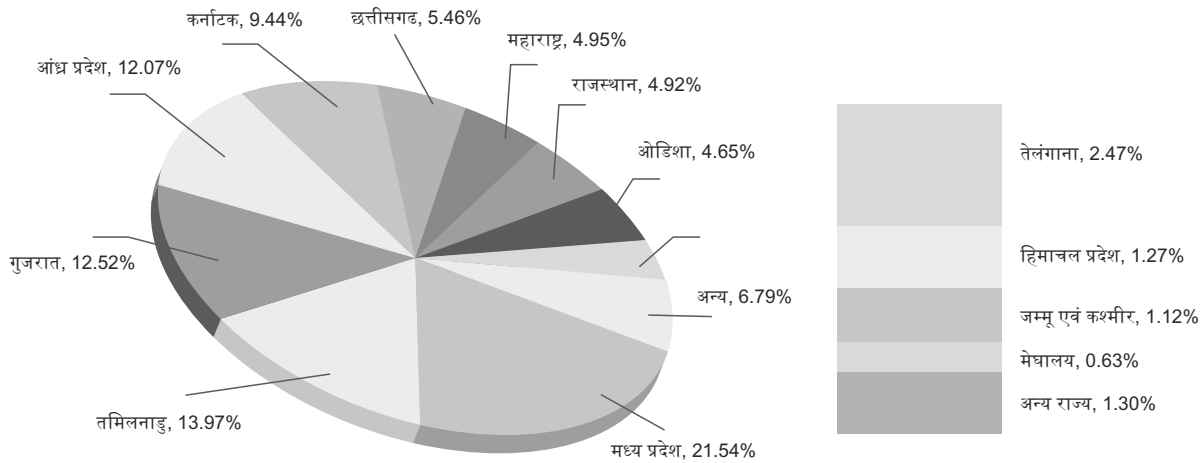
2. खनन पट्टों का वितरण

भारतीय खनन उद्योग की विशेषता बड़ी संख्या में छोटी परिचालन वाली खदानें हैं। इसके अलावा, 2021-22 के दौरान रिपोर्टिंग खदानों की कुल संख्या (परमाणु, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर) पिछले वर्ष की 1350 की तुलना में 1309 थी। खनिजों के धात्विक समूह में खदानों की संख्या 543 थी और खनिजों के गैर-धातु समूह के मामले में यह 766 थी। 31.03.2021 तक खनन पट्टों का राज्य-वार और खनिज-वार विवरण और पिछले तीन वर्षों के दौरान रिपोर्टिंग खदानों की संख्या नीचे दी गई है:

राज्य	No. of Leases	राज्य	No. of Leases
मध्य प्रदेश	714	ओडिशा	154
तमिलनाडु	463	झारखंड	122
गुजरात	415	तेलंगाना	82
आंध्र प्रदेश	400	हिमाचल प्रदेश	42
कर्नाटक	313	जम्मू एवं कश्मीर	37
छत्तीसगढ़	181	मेघालय	21
महाराष्ट्र	164	अन्य राज्य	43
राजस्थान	163		

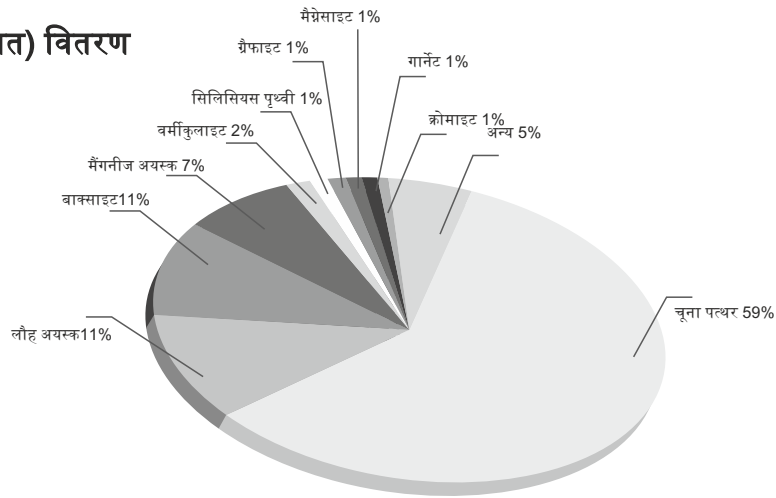
स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो

खनन पट्टों का राज्यवार (प्रतिशत) वितरण

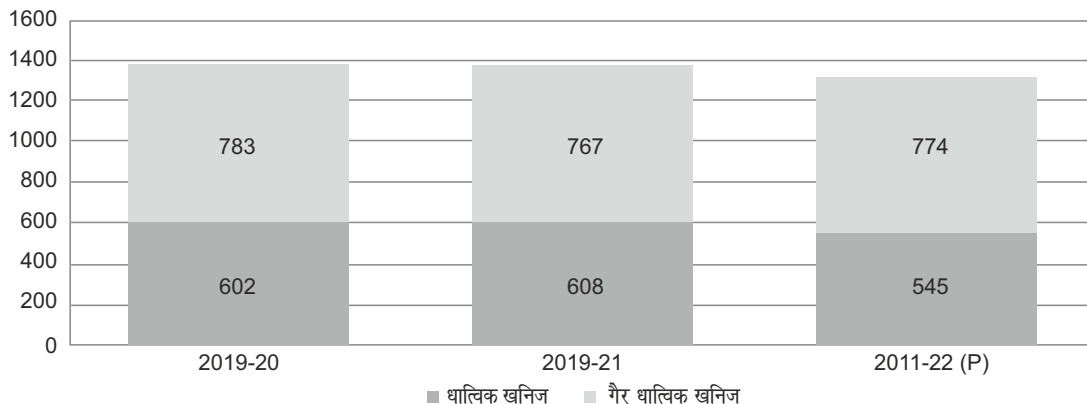


वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल रिपोर्टिंग खदानों (परमाणु, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर) में प्रमुख राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में 263, गुजरात में 143, कर्नाटक में 132, ओडिशा में 128, छत्तीसगढ़ में 112, आंध्र प्रदेश में 108, राजस्थान में 90, तमिलनाडु में 86, महाराष्ट्र में 73, झारखंड में 44 और तेलंगाना में 39 खदानें सम्मिलित हैं।

खनन पट्टों का खनिजवार (प्रतिशत) वितरण



वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान रिपोर्टिंग खदानों की संख्या



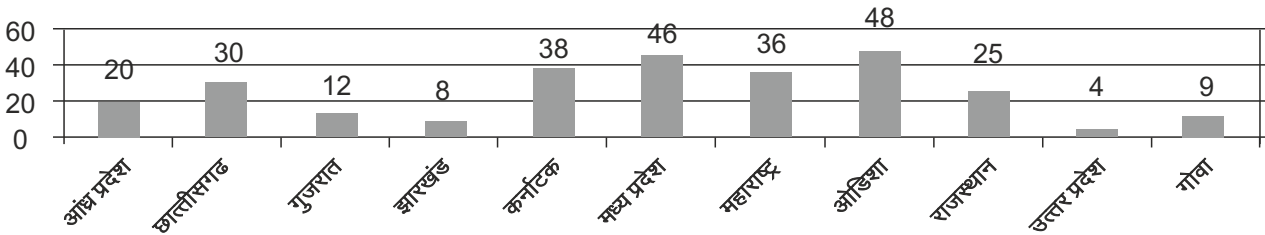
3. खनन एवं उत्खनन क्षेत्र से सकल मूल्य वर्धित (जीवीए)

वर्ष 2021-22 में खनन और उत्खनन क्षेत्र का जीवीए (मौजूदा कीमतों पर) लगभग 2.40% हिस्सा था। वर्ष 2021-22 के लिए जीवीए में खनन और उत्खनन क्षेत्र का योगदान (स्थिर कीमतों पर) रुपये 327984 करोड़ अनुमानित है जो इससे पिछले वर्ष की तुलना में 11.55% की वृद्धि का संकेत दे रहा है।

4. खनन पट्टों की नीलामी का परिदृश्य

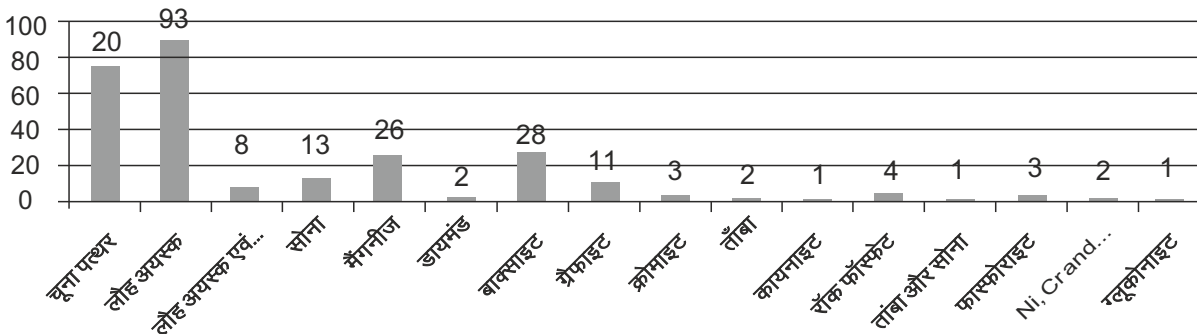
खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम, 1957) एक कानूनी ढांचा है जो भारत में खानों और खनिजों के विकास और विनियमन को नियंत्रित करता है। 12.01.2015 से प्रभावी, एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2015 ने एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में संशोधन किया। संशोधन की मुख्य विशेषता पिछली "पहले आओ-पहले पाओ" पद्धति की जगह, नीलामी के माध्यम से खनिज रियायतें देने का प्रावधान शामिल करना था। इस संशोधन का उद्देश्य सभी स्तरों पर खनिज रियायतें देने में पारदर्शिता बढ़ाना और किसी भी विवेकाधीन शक्तियों को समाप्त करना था। इसके अतिरिक्त, नीलामी पद्धति राज्य सरकार को नीलामी खदानों से प्राप्त राजस्व की गारंटी देती है। नीलामी प्रणाली में दो प्रकार की रियायतें शामिल हैं, अर्थात् खनन पट्टे (एमएल) और समग्र लाइसेंस (सीएल), जिसमें पूर्वेक्षण लाइसेंस के साथ-साथ खनन पट्टे भी शामिल हैं। 14.07.2023 तक नीलाम किए गए ब्लॉकों की संख्या (राज्य-वार और खनिज-वार) की वर्तमान स्थिति, जिसमें कम मूल्य वाले खनिज, मध्यम मूल्य वाले खनिज, उच्च मूल्य वाले खनिज, महत्वपूर्ण खनिज और कीमती धातुएं और पत्थर शामिल हैं, नीचे दी गई है:

नीलाम किये गये ब्लॉक (राज्यवार)



नोट:- ओडिशा में 2019-20 में नीलाम किए गए 2 लौह अयस्क ब्लॉक जब्त कर लिए गए। सितंबर, २०२१ में इनकी पुनः नीलामी की गई। इसलिए, कुल 278 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गई, लेकिन वास्तविक रूप से, शुद्ध आंकड़ा 276 है।

नीलाम किये गये ब्लॉक (खनिजवार)



5. उत्पादन परिदृश्य

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, देश में खनिज उत्पादन (परमाणु, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर) का कुल मूल्य 132748 करोड़ था जो पिछले वर्ष की तुलना में 63% की वृद्धि दर्शाता है। यह मुख्य रूप से बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा सांद्र, लौह अयस्क, सोना, सीसा और जस्ता अयस्क, मैंगनीज अयस्क, सीसा, जिंक, टिन, कायनाइट, गार्नेट (अपघर्षक), चूना पत्थर, मैग्नेसाइट, फॉस्फोराइट आदि के उत्पादन में वृद्धि के कारण था। हालांकि, 2021-22 के दौरान हीरा, मार्ल, चांदी, सिलिमेनाइट और वोलास्टोनाइट आदि खनिजों का उत्पादन कम हो गया।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य-वार परिदृश्य के संबंध में, ओडिशा से खनिज उत्पादन का मूल्य (परमाणु, ईंधन और लघु खनिजों को छोड़कर) सबसे अधिक 58551 करोड़ था जोकि धात्विक और गैर-धातु खनिज उत्पादन के कुल मूल्य का 44.1% था, इसके बाद महत्व के क्रम में छत्तीसगढ़ 23023 करोड़ या 17.3%, राजस्थान 18724 करोड़ या 14.1%, कर्नाटक 17572 करोड़ या 13.2% था। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के दौरान खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में इन राज्यों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। अन्य राज्यों ने शेष 10517 करोड़ या खनिज उत्पादन के कुल मूल्य का लगभग 11% साझा किया।

“

राष्ट्रीयता का भाषा और साहित्य के साथ बहुत ही
घनिष्ठ और गहरा संबंध है।

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

”

वैश्विक परिदृश्य में हिन्दी के बढ़ते कदम



नरेश कुमार कटारिया

उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी
भारतीय खान ब्यूरो, गोवा

हिन्दी, भारत की राजभाषा है और विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली 10 भाषाओं में से एक है। हिन्दी को अपनी मातृभाषा के रूप में बोलने वाले लोगों की संख्या में भी वृद्धि हुई है और यह भारतीय प्रवासियों की भी प्रमुख भाषा है। वैश्विक मंच पर हिन्दी के बढ़ते कदम निम्नलिखित कारणों से देखे जा सकते हैं :-

1. भारतीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना : भारत पाँचवी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा है और इसके साथ ही भारतीय कंपनियां वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रही हैं। इससे हिन्दी का महत्व बढ़ता है, क्योंकि व्यापारियों को भारतीय बाजार में सुगमतापूर्वक संचार करने के लिए हिन्दी की जरूरत होती है।

2. भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा : भारत एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी है और अपनी आर्थिक वृद्धि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तेजी से उन्नति कर रहा है। भारत के विदेशी राजनयिक और व्यापारिक संबंधों का मापदंड भी बढ़ा है, जिससे हिन्दी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा मिलता है। भारत अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए हिन्दी की प्रभावशाली भूमिका को महत्व दे रहा है। इसके लिए भारत सरकार और विभिन्न

स्थानीय संगठन हिन्दी के प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रहे हैं।

3. जनसंख्या: भारत विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है और एक तरह से कहें तो हिन्दी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा है। इसलिए, भारतीय जनसंख्या के बढ़ने साथ ही हिन्दी के प्रयोग में भी वृद्धि हो रही है।

4. भारतीय प्रवासी : विश्व भर में रहने वाले भारतीय प्रवासियों (दियास्पोरा) की संख्या में वृद्धि होने के साथ हिन्दी के उपयोग और महत्व में भी वृद्धि हुई है। भारतीय प्रवासी विभिन्न देशों में निवास करके अपनी भाषा और संस्कृति को बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं और इसका हिस्सा हिन्दी भी है। इसके साथ ही, विभिन्न भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समारोहों और फ़िल्मों में भी हिन्दी का प्रयोग होता है, जिससे हिन्दी की प्रतिष्ठा, महत्व और प्रचार-प्रसार बढ़ता है।

5. विदेशी छात्रों की भारत में शिक्षा: भारत में विदेशी छात्रों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है जो कि भारतीय शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उच्च शिक्षा और विभिन्न विषयों में अध्ययन करने के लिए भारत आते हैं। और इनमें से अधिकतर छात्र हिंदी सीखने के लिए उत्सुक होते हैं। हिन्दी भाषा का अध्ययन करके, विदेशी छात्र भारतीय सांस्कृतिक विस्तार का भाग बनते हैं। हिन्दी के माध्यम से वे देश की भाषा, संगीत, काव्य और अन्य साहित्यिक विधाओं आदि का भी अध्ययन कर सकते हैं। यह उन्हें भारतीय संस्कृति और मान्यताओं के प्रति अधिक समझदार बनाता है।

6. विदेशी नागरिकों की रुचि: विदेशी नागरिकों की रुचि में हिन्दी के प्रति भी वृद्धि हुई है। हिन्दी भाषा की सरलता और सुंदरता ने विदेशी नागरिकों को आकर्षित किया है। बहुत से विदेशी नागरिक भारत यात्रा करते हैं और यहां अपने व्यापारिक और पर्यटन कार्यों को बढ़ाने के लिए हिन्दी का प्रयोग करना चाहते हैं। यहां हिंदी भाषा का ज्ञान उन्हें भारतीय नागरिकों के साथ संवाद स्थापित करने और उनसे अधिक नजदीकी बनने में मदद करता है। विदेशी नागरिकों के

बीच हिन्दी के प्रचार-प्रसार ने उन्हें भारतीय संस्कृति और जीवनशैली के अधिक समझ के दरवाजे खोले हैं।

7. वैश्विक संचार क्षेत्र में महत्ता: वैश्विक संचार के क्षेत्र में भी हिन्दी की महत्ता बढ़ी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के विकास ने भाषा के आपसी संपर्क को सुगम बना दिया है और हिन्दी को वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से प्रदर्शित करने का एक माध्यम प्रदान किया है। हिन्दी के बढ़ते डिजिटल प्रभाव ने विश्व में भारतीय साहित्य, कला, संगीत और फिल्मों की पहुंच को बढ़ाया है। हिन्दी भाषा के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक विरासत को विदेशों में प्रस्तुत किया जा रहा है और विदेशी नागरिकों को यह अवसर मिल रहा है कि वे भारत की प्रगाढ़ और विविधात्मक संस्कृति को अधिक समझें और अनुभव करें।

8. व्यापारिक मौकों में वृद्धि और नौकरी के अवसर: भारत आर्थिक मामलों में वृद्धि कर रहा है और इससे हिन्दी भाषा को

व्यापारिक मौकों में अधिक महत्व मिल रहा है। विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार बढ़ रहा है। विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए हिन्दी भाषा के प्रयोग को महत्व देती हैं। हिन्दी के प्रयोग से विदेशी कंपनियों को भारतीय बाजार में फायदा मिलता है इसके आलावा हिन्दी जानने वालों को करियर में विभिन्न मौके मिलते हैं जैसे कि भारत सरकार और निजी संगठनों, अखबारों, पत्रिकाओं, प्रकाशनों, टीवी चैनलों आदि।

इन सभी कारणों से हिन्दी की गति वैश्विक स्तर पर बढ़ रही है और इसका महत्व विश्व में बढ़ता जा रहा है। हिन्दी का प्रचार प्रसार, अर्थव्यवस्था, विदेशी नागरिकों की रुचि, डिजिटल प्रभाव और भारतीय प्रवासियों के संघर्षों के परिणामस्वरूप हो रहा है। इस प्रकार हिन्दी भाषा विश्व में अपनी महत्ता बढ़ा रही है एवं सामरिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक और वैचारिक क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

“ भारतवर्ष में सभी विद्याएँ सम्मिलित परिवार के समान पारस्परिक सद्भाव लेकर रहती आई हैं।
- रवींद्रनाथ ठाकुर। ”

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



पियूष शुक्ला

आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, हैदराबाद

भारत अनेक विविधताओं को अपने एकत्व में जोड़े हुए अनेकों संभावनाओं को साकार करने में हमेशा से ही उत्कृष्ट रहा है। आज भारत वैश्विक पटल पर हर क्षेत्र को अपनी गहन क्षमता से प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में विश्व के सामने कई चुनौतियां जैसे कोविड-19 महामारी, रूस-युक्रेन युद्ध आदि आईं, जिनमें भारत ने एक अहम भूमिका निभाई है। रूस-युक्रेन युद्ध में भारत के रूस के प्रति झुकाव को यूरोपीय देशों एवं अमेरिका ने भी स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया है। ऐसा सिर्फ मोदी सरकार की विदेश नीति का पूर्व की सरकारों में जिस तरह नीतिगत अपंगता थी, वह अपंगता न होने का कारण हुआ है। फिर भी रूस के प्रति झुकाव होने के बावजूद भारत का पक्ष काफी हद तक निरपेक्ष है। कोविड-19 महामारी के काल में भारत ने बहुत सारे देशों की भांति वैक्सीन को केवल अपने देशों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि पूरे विश्व में वैक्सीन का वितरण कर अपनी प्रतिबद्धताओं को बखूबी निभाया है, जो यह दर्शाता है कि भारत किस तरह से विश्व में एक नयी महाशक्ति बनकर उभर रहा है। वर्तमान में यूएनएफपीए की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट के मुताबिक भारत जुलाई 2023 तक 1.4286 बिलियन जनसंख्या के साथ दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, जो कि भारत को वैश्विक मुद्दों पर अपना पक्ष रखने में मजबूती प्रदान करता है। भारत को जो आज विश्व की लगभग 17.75 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थाई

सदस्य बनाए जाने का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। वहीं यदि हम ग्लोबल साउथ की बात करें तो अधिकतम जनसंख्या होने के कारण भारत उसका भी प्रतिनिधित्व कर सकता है।

आज भारतीय मूल के कई नागरिक विश्व की बड़ी-बड़ी कंपनियों में नीति निर्धारक हैं। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा जनसंख्या में आता है, जिसके कारण भारत विनिर्माण क्षेत्र में एकाधिकार स्थापित कर सकता है। इसके अलावा वर्तमान में भारत सेवा प्रदाता के रूप में एक अहम भूमिका निभा रहा है। आज भारत वैश्विक स्तर पर आतंकवाद को समाप्त करने में सबसे अधिक योगदान दे रहा है। पूरे विश्व में आतंकवाद को सींचने वाला पाकिस्तान जो कश्मीर से अफगानिस्तान तक आतंकवादियों को पनाह देता है, को भारत ने विश्व पटल पर अगल-थगल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने कई बार विश्व को पाकिस्तान की मदद न करने के लिए चेतावनी दी, मगर अमेरिका जैसे विकसित देशों ने कई मिलियन डालर उस पर निवेश किए, जो सीधा आतंकवादियों का वित्तपोषण था और जिसका खामियाजा पूरा विश्व आज आतंकवादी हमलों के रूप में झेल रहा है।

अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभुत्व बढ़ाने में भी इन्हीं विकसित देशों के अपने निजी स्वार्थ थे, जो आगे चलकर अफगानिस्तान में लोकतंत्र की मृत्यु का कारण बना। इन सबको समाप्त करने में भारत आज एक अग्रिम भूमिका निभा रहा है। भारत की वैश्विक परिदृश्य में भूमिका के दो मापदंड हैं- पहला तो भारत की अर्थव्यवस्था और दूसरा भारत की सैन्य शक्ति। वैश्विक पटल पर भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और बेहतर करने की जरूरत है आज भारत दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो कि 3.1 ट्रिलियन डालर की है तथा प्रति व्यक्ति आय लगभग 98000 रुपए है जो कि वैश्विक औसत से काफी कम है।

अतः इस दिशा में भारत सरकार को अपनी कराधान नीतियों को बदलने की आवश्यकता है। यदि करें का और अधिक युक्तिकरण होता है तो यह अर्थव्यवस्था को उबार सकता है और भारत 8-10 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ सकता है। अब यदि हम भारत की वैश्विक

भूमिका को धार देने वाले दूसरे पक्ष सैन्य शक्ति की बात करते हैं तो इसमें भी भारत को अभी बहुत कुछ करना है। भारत अपनी कुल जीडीपी का केवल 1.6 प्रतिशत ही रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है जिसका एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन में ही खर्च हो जाता है जिस वजह से अनुसंधान और विकास में उपयुक्त निवेश नहीं हो पाता है। इसलिए प्रमुख शक्तियों के लिए व्यवहार्य भागीदार के रूप में योग्य नहीं है। सैन्य शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुद्रा है। और चीन और पाकिस्तान के दो मोर्चे की चुनौती को देखते हुए भारत को अपने सैन्य ढांचे को तेज गति से विकसित करने की आवश्यकता है। ये दो ऐसे बिन्दु हैं जिन पर ध्यान देकर ही भारत वैश्विक परिदृश्य में अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। वैश्विक पटल पर यदि किसी घटना ने सबसे अधिक प्रभाव डाला है, तो वह द्वितीय विश्व युद्ध है। इस घटना के बाद एक निश्चित शक्ति संचरना उभरी जिसके केंद्र में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका था। उस समय वैश्विक व्यवस्था निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर अमेरिका की आर्थिक और सैन्य नीतियों पर निर्भर थी। लेकिन वर्तमान काल में चीन, जर्मनी, जापान, भारत, रूस जैसे देश मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं और इन देशों की सैन्य शक्ति भी अब तीव्र गति से विकसित हो रही

है जो एक बहुध्रुवीय विश्व की स्थापना की ओर अग्रसर है। लेकिन फिर भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि आज भी अमेरिका की प्रौद्योगिकी और विज्ञान के क्षेत्र में तकनीकी क्षमता अन्य देशों से आगे है। इस प्रकार की विश्व की यह नई व्यवस्था शीत युद्ध की कुटनीतियों का अनुकरण करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यह फिर भी उस विचारधारा से काफी अगल है। आज अमेरिका-चीन का व्यापार युद्ध इस बात का स्वच्छ प्रमाण है कि कैसे अमेरिका की दिग्गज कंपनियां चीन से बाहर निकलकर वियतनाम, इंडोनेशिया, कोरिया और भारत में अपनी इकाइयां खोल रही हैं। इन्हीं सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए इन अनिश्चितताओं के महासागर को सावधानी से पार करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न तो कोई स्थायी मित्र होता है और न ही कोई स्थायी शत्रु होता है। यदि कुछ स्थायी होता है तो वह केवल राष्ट्र के हित होते हैं और भारत को अपने राष्ट्रीय हितों को समझते हुए अपनी अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति और एक आकर्षक मध्यम वर्ग के बाजार के बल पर दुनिया भर में शांति, समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाने की बेहतरीन क्षमता है।

“

संप्रति जितनी भाषाएं भारत में प्रचलित हैं
उनमें से हिन्दी भाषा प्रायः सर्वत्र व्यवहृत होती है।

- केशवचंद्र सेन

”

हिंदी के प्रचार- प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका



रामसिंह

उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

सामाजिक माध्यम या सोशल मीडिया से आशय पारस्परिक संबंध के लिए अंतर्जाल या अन्य माध्यमों द्वारा निर्मित आभासी समूहों से है। यह व्यक्तियों और समुदायों को साझा, सहभागी बनाने का माध्यम है।

वह समाज में रहकर एक - दूसरे के साथ विचार - विनिमय करते हुए अपना एवं अपने समाज का विकास करता है। किसी भी समाज के निर्माण में संचार की विशेष भूमिका है। मानव की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं के स्थानांतरण की प्रक्रिया में संचार का विशेष योगदान है। आदिकाल से मानव संचार के लिए नए - नए तरीके खोजने हेतु प्रयासरत रहा है।

वर्ष 1999 में इंटरनेट पर पहला कदम रखा। इन 15-16 वर्षों के कालखंड में इंटरनेट के कारण विभिन्न वेबसाइट, ब्लॉग, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अधिकांश जनसमुदाय तक हिंदी भाषा को पहुँचाने का कार्य हो रहा है। इंटरनेट पर दिन व दिन हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की गति तेज हो रही है।

मीडिया की भाषा साहित्यिक भाषा की तरह अलंकरण का बोझ लेकर नहीं चलती, न ही वह अकादमिक भाषा की तरह बौद्धिकता का बोझ ढोती है, लेकिन कागज और होठों के बीच की दूरी कम करने के चक्कर में मीडिया का भाषा प्रयोग नवाचार भी करता है। यदि

भाषा कृत्रिम होगी तो कोई भरोसा नहीं कि पाठक उस खबर को भी नकली, गढ़ी गई नहीं मानेगा।

मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनियाभर में आज भारतीय फिल्मों व टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाते हैं। इससे भी दुनिया में हिंदी का प्रचार - प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया इंटरनेट व मोबाइल के कारण आज युवा पीढ़ी इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कर रही है। कोशिश यह होनी चाहिये कि हिंदी में ही सोचकर हिंदी में लिखें। हिंदी में लिखते समय शब्दों के लिये अटकिये मत, किसी भी शैली के लिये रुकिये नहीं और अशुद्धियों से घबरायें नहीं। कोशिश करें कि मौलिक रूप से हिंदी लेखन करें। अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद का सहारा बहुत कम लेना चाहिये क्योंकि दोनों भाषाओं की शैली अलग - अलग है।

हिंदी को केन्द्रीय हिंदी संस्थान (केएचएस) आगरा, केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), नई दिल्ली द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। इन साहित्य संस्थाओं के अतिरिक्त प्रयाग महिला विद्यापीठ, हिन्दी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद, हिंदुस्तानी अकादमी, प्रयाग, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, पूना, हिंदी विद्यापीठ, मुंबई, हिंदुस्तानी प्रचार सभा, वर्धा, मैसूर हिंदी प्रचार परिषद्, बेंगलोर, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पूना, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् इत्यादि संस्थाओं द्वारा हिंदी प्रचार प्रसार में कार्य किया जाता है।

“ देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता
स्वयं सिद्ध है।
- महावीर प्रसाद द्विवेदी ”

विश्व -पटल पर हिंदी



असीम कुमार

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आज जब हम विश्व -पटल पर हिंदी की बात करते हैं , तो हिंदी को अत्यंत ही सुखद स्थिति में पाते हैं। आज हिंदी करवट ले रही दुनिया की जरूरत बन गई है। यूरोपीय देशों के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व को यह प्रतीत होने लगा है कि हिंदी के बगैर उनका काम नहीं चल सकता है तथा विश्व की मंडी और बाजार को इसके बिना जीता भी नहीं जा सकता है। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति हिन्दीभाषी है और विश्व बिरादरी को इस बात का एहसास है कि हिंदी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी संपर्क - भाषा एवं राजभाषा है तथा इसी भाषा के माध्यम से भारत जैसे बहुभाषी देश में कारोबार किया जा सकता है।

साथ ही, विश्व -पटल पर हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाने पर यह ज्ञात होता है कि जब 14 अक्टूबर, 1977 को भारत के तत्कालीन विदेश मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र -संघ को हिंदी में सम्बोधित किया ,तो हिंदी को एक विश्व -मंच प्राप्त हुआ। इसी प्रकार, न्यूयॉर्क में हुए आठवें विश्व हिंदी सम्मलेन के पश्चात संभवतः पहली बार हिंदी को एक भाषाई उद्योग के रूप में देखने का विनम्र प्रयास किया गया। साथ ही यह उम्मीद भी बंधी कि संयुक्त राष्ट्र -संघ द्वारा स्वीकृत विश्व भाषाओं में हिंदी का शुमार शीघ्र ही हो जायेगा। संयुक्त राष्ट्र -संघ के परिसर में आठवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन वास्तव में हिंदी के लिए एक कूटनीतिक अभियान था। हिंदी आज विश्व के हर कोने में पहुँच चुकी है। आज लगभग 150

विदेशी विश्व विद्यालय किसी न किसी रूप में हिंदी के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। भारत में भी कुछ विश्वविद्यालय विदेशी छात्रों के लिए हिंदी के पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इनमें भी बड़ी संख्या में विदेशी छात्र आ रहे हैं। इधर कुछ वर्षों में हिंदी सीखने हेतु चीन के विद्यार्थियों का भी रुझान बढ़ा है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में यूनिकोड के माध्यम से देवनागरी फोंट्स ने हिंदी उद्योग को काफी गति दी है। विदेशों में रहने वाले भारतीयों एवं हिंदी सीखने वाले विदेशियों के बीच हिंदी फ़िल्मी गाने एवं हिंदी भजनों के रेडियो कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय हैं। इलेक्ट्रॉनिक और साइबर जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों से हिंदी सिनेमा को पूरे विश्व में, विशेषकर उत्तरी अमेरिका और राष्ट्रमंडल के देशों में फैलने का मौका मिला। विदेशों में बसे भारतीय परिवारों के लिए हिंदी फ़िल्में मनोरंजन और भारत की सामासिक संस्कृति से जुड़े रहने का एक बहुत सशक्त मंच है। हिन्दीतर भारतीय फ़िल्में और हॉलीवुड की अरबों रुपयों के बजट वाली फ़िल्में भी हिंदी में डब हो कर वैश्विक स्तर पर दिखाई जा रही हैं।

टेलीविजन के आने से, वैश्विक स्तर पर, हिंदी को तो जैसे औद्योगिक पंख लग गए। आज सैकड़ों की संख्या में हिंदी चैनल समूचे विश्व में, हिंदी में तरह-तरह की मनोरंजक, सूचनात्मक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा अन्य विषयों पर सामग्री हर आयु -वर्ग के दर्शकों के लिए आकर्षक ढंग से पेश कर रहे हैं। रेडियो और टेलीविजन के कारण आज पूरा विश्व एक खेल का मैदान बन गया है। खेल के प्रकार और दर्शक वर्ग को ध्यान में रख कर कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मैच, जैसे क्रिकेट, हॉकी आदि का आँखों -देखा हाल हिंदी में भी सुनाया और दिखाया जाता है। चूँकि हिंदी का दर्शक वर्ग काफी बड़ा है, अतः इन कार्यक्रमों के साथ - साथ हिंदी विज्ञापन भी चलते रहते हैं, जिनके द्वारा करोड़ों रुपये का व्यवसाय होता है।

विश्व ग्राम के रूप में वैश्विक- नागरिक कई सन्दर्भों में अपरिहार्य रूप से एक-दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं। चूँकि हिंदी विश्व की सबसे बड़ी भाषाओं में एक होने के साथ - साथ भारत की सबसे बड़ी संपर्क भाषा है और विशाल जनसंख्या और अपनी प्राचीन संस्कृति के कारण विश्वग्राम का एक बहुत बड़ा बाजार है, अतः अनुवाद के क्षेत्र

में भी हिंदी का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। आर्थिक स्तर पर भी इसके सुपरिणाम सामने आ रहे हैं। अब यह एक सुखद स्थिति उत्पन्न हुई है, जहाँ हमारे वरिष्ठ राजनयिक विदेशी राजनयिकों से दुभाषिये की सेवाएं लेते हुए हिंदी माध्यम से संवाद कर रहे हैं। विदेशों से कई हिंदी पत्रिकाओं का प्रकाशन हो रहा है। जन-संचार माध्यमों, जन-संपर्क, इंटरनेट, मोबाईल-संदेशों, विज्ञापन-लेखन जैसे कई क्षेत्रों में हिंदी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैश्विक-स्तर पर हिंदी का प्रचार-प्रसार दिनों-दिन बढ़ता जा रहा है। प्रवासी भारतीयों ने विदेशों में हिंदी की शान को बढ़ाया है। विश्व हिंदी सम्मलेन के आयोजन ने हिंदी की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

ऐसे सम्मेलनों से हिंदी भाषा की गरिमा एवं उसके योगदान की चर्चा को विस्तार मिला है। अब समय आ गया है कि हिंदी की उस शक्ति को पहचाना जाये, जिसके कारण विदेशों में राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण हो रहा है तथा हिंदी के कदम विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। हालाँकि, कुछ प्रश्न भी मन में उठते हैं। श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के लोग हिंदी बखूबी बोलते और समझते हैं। अतः हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हिंदी को संयुक्त राष्ट्र-संघ की आधिकारिक भाषा बनाने के पहले इसे दक्षेस देशों की आधिकारिक भाषा बनाई जाये। आज यदि राष्ट्रमंडल के देश अंग्रेजी भाषा में अपनी कार्यवाही कर सकते हैं, तो फिर दक्षेस देश हिंदी भाषा में अपना काम-काज क्यों नहीं कर सकते?

“

हिन्दी उन सभी गुणों से अलंकृत है
जिनके बल पर वह विश्व की साहित्यिक भाषाओं की
अगली श्रेणी में सभासीन हो सकती है।

”

- मैथिलीशरण गुप्त

आजादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिन्दी



एकता गिरि

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, कोलकाता

आजादी का अमृत महोत्सव यानि कि देश की स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे होने का उत्सव। 15 अगस्त 2022 को जब देश की स्वतंत्रता के पचहत्तर वर्ष पूरे हुये तब से लगभग पचहत्तर सप्ताह पहले इस महोत्सव की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के उसी साबरमती आश्रम से की जहाँ से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नमक के ऊपर लगे कर के विरोध में दांडी मार्च की शुरुआत की थी। वर्तमान में इस महोत्सव की समय – सीमा बढा कर 15 अगस्त 2023 कर दी गई है।

दो सौ साल गुलामी की जंजीरों में जकडे भारत की आजादी के पचहत्तर वर्ष बीतने के पश्चात् आज देश उस स्थान पर खडा है जहाँ से अतीत और भविष्य दोनों पर ही दृष्टि डालना आवश्यक है। अतीत पर इसलिये क्योंकि अतीत से ही भारत देश के गौरवमयी इतिहास की जड़ें निकलती हैं और भविष्य में इसलिये क्योंकि भविष्य ही हमारे आज के कर्मों का परिणाम है। आज के हमारे प्रयास ही भविष्य में देश को उस मुकाम पर पहुँचायेंगे जिस मुकाम पर देश को देखने का सपना हर भारतवासी की आँखों में है। इसी सपने को साकार करने की दृष्टि से आजादी के अमृत महोत्सव के पांच स्तम्भ निर्धारित किये गये हैं जो इस प्रकार हैं –

1. स्वतंत्रता संग्राम
2. 75 पर विचार
3. 75 पर उपलब्धियाँ

4. 75 पर कदम

5. 75 पर संकल्प

इन पांच स्तम्भों पर विचार करने से पूर्व हमें यह समझना होगा कि कोई भी संस्था, कोई भी समाज और कोई भी देश तब तक अस्तित्व हीन हैं जब तक उसमें लोग न शामिल हों। कागज पर किसी संस्था, समाज अथवा देश का गठन हो सकता है, इनकी रूपरेखा खींची जा सकती है लेकिन इन्हें वास्तविक अर्थ देने के लिये इनमें लोगों का समावेश होना आवश्यक है और जिस समाज, जिस देश में जनता की भागीदारी जितनी अधिक होगी, वह समाज, वह देश उतना ही अधिक विकास करेगा। इसी धारणा के मददेनजर आजादी के अमृत महोत्सव को जन महोत्सव का रूप प्रदान किया गया है और जिस महोत्सव में जनता की भागीदारी होगी वहाँ भाषा स्वतः ही समाविष्ट होगी क्योंकि अपनी बात दूसरे तक पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम भाषा ही है।

हमारे देश में जहाँ बाईस भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में स्थान दिया गया है वहीं उनमें से एक भाषा हिन्दी को राजभाषा का और संपर्क भाषा का भी दर्जा प्राप्त है। जाहिर सी बात है कि देश के पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक अगर किसी एक भाषा को जानने वाले लोग बहुतायत में हैं तो वह भाषा हिन्दी ही है और इसी कारण यह संपर्क भाषा बनी हुई है। स्वतंत्रता के लिये चले लम्बे संघर्ष में हिन्दी जहाँ आजादी के परवानों की गूँज बनी थी वहीं आज देश जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो हिन्दी इस महोत्सव का हाथ थामे आगे बढ रही है।

आजादी के अमृत महोत्सव के पांच स्तम्भों के साथ यदि हम हिन्दी की चर्चा करें तो हम पायेंगे कि पहला स्तम्भ स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानियों के 'इन्कलाब जिन्दाबाद' में हिन्दी थी। 'करो या मरो' में हिन्दी थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा' में हिन्दी थी और अंग्रेजों भारत छोड़ो' में भी हिन्दी ही थी। अमृत महोत्सव में आज जब स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों पर प्रकाश डाला जा रहा है तो निश्चित ही इन नायकों के साथ हिन्दी भी इनकी पृष्ठभूमि से निकल कर बाहर आ रही है।

दूसरे स्तम्भ 75 पर विचार में यदि हम पिछले पचहत्तर वर्षों में हिन्दी की स्थिति पर विचार करें तो हम पायेंगे कि इन पचहत्तर वर्षों में हिन्दी की दिशा में बहुत प्रयास किये गये हैं। सरकारी कार्यालयों में हिन्दीतर भाषियों के लिये हिन्दी के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना इसी प्रकार का प्रयास है जिसकी हृदय से प्रशंसा की जानी चाहिये। इसी प्रकार सिने जगत के प्रयासों को भी कमतर नहीं आंका जा सकता है। आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार पत्र इन सभी ने अपने-अपने स्तर पर हिन्दी के विकास में अपना योगदान दिया है और पिछले पचहत्तर वर्षों से अपनी भूमिका अनवरत् निभाये चले जा रहे हैं।

75 पर उपलब्धियों के नाम पर हमारे पास आज ऐसी तकनीकें हैं जिनसे हम बोल कर हिन्दी टंकित कर सकते हैं। कहीं भी, किसी भी वक्त बिना किसी कड़ी मेहनत के हिन्दी में अनुवाद कर सकते हैं। जिन्हें हिन्दी नहीं आती वे 'लीला हिन्दी प्रवाह' मोबाईल एप के द्वारा अपनी मातृभाषाओं से घर बैठे निःशुल्क हिन्दी सीख सकते हैं। देश भर में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने के लिये राजभाषा विभाग द्वारा देश भर में अब तक 527 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया जा चुका है और विदेशों में लंदन, सिंगापुर, फिजी, दुबई और पोर्ट लुई में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। निश्चित ही ये प्रयास हमारी बड़ी उपलब्धियां हैं।

75 पर कदम में हमें ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता है जिससे हिन्दी बोलते, लिखते समय हमें हीनता का अनुभव न हो और ये कदम जनता द्वारा उठाये जाने चाहिये। अंग्रेजी जानने वाला व्यक्ति ही पढा – लिखा है इस मानसिकता को अब छोड़ना होगा क्योंकि भले ही अंग्रेजी एक भाषा हो लेकिन गुलामी की गंध अब भी उसमें बरकरार है और इस गंध से पीछा छुड़ाकर ही हम भाषाई गुलामी से मुक्ति पा सकते हैं। इसलिये देश जब आजादी के अमृत महोत्सव को जन महोत्सव के रूप में मना रहा है तो जनता का भी दायित्व है कि

इस महोत्सव को संपूर्ण हृदय से अपनाये और बढ़चढ़ कर इसमें अपनी सक्रिय भागीदारी सक्रिय करे।

75 पर संकल्प में हमें ऐसे संकल्प लेने चाहिये जो देश के अमृत काल (आजादी के 75वें साल से सौ साल के बीच के पच्चीस वर्ष की अवधि) में देश को उन ऊँचाईयों पर ले जा सकें जहाँ पर देश का सर्वांगीण विकास हुआ हो। जहाँ अपना राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत के साथ – साथ अपनी राष्ट्रभाषा भी हो। जहाँ न्यायालयों की भाषा ऐसी हो जिसे देश का साधारण वर्ग भी समझ सके। निश्चित ही ये कार्य स्वतः होने वाले नहीं हैं। इन्हें पूरा करने के लिये दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प की आवश्यकता है और साथ ही जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। जनता के सहयोग के बिना किसी भी लक्ष्य तक पहुंचना असंभव है क्योंकि अंततः जनता ही देश की तरक्की और विकास की परिचायक है।

जिस प्रकार आजादी के अमृत महोत्सव को जन महोत्सव का रूप दिया गया है उसी प्रकार 14 सितम्बर 2024 को जब हम राजभाषा का अमृत महोत्सव मनायेंगे तब इस महोत्सव को भी जन साधारण से जोड़ा जाना उचित होगा क्योंकि भाषाई स्तर के सभी वैमनस्य भुलाकर एक मंच पर यदि सभी भाषा – भाषियों को लाना है तो जनता का सहयोग अपेक्षित ही है। जन साधारण को यह समझना होगा कि अपनी – अपनी भाषा का झंडा लिये यदि वे आगे बढ़ना चाहेंगे तो बढ़ेंगे तो अवश्य लेकिन देश एक राष्ट्रभाषा के मामले में पीछे रह जायेगा।

अपनी – अपनी भाषा के मोह में हमने पचहत्तर साल तो बिना एक राष्ट्रभाषा के बिता दिये लेकिन अब आगे के अमृत काल में ऐसा नहीं होने देना है। अब हमारी भी एक राष्ट्रभाषा होगी और जिस पर गर्व करते हुये हम कहेंगे कि हाँ....., हमारी मातृभाषा तमिल, तेलगू, बांग्ला, कन्नड या मराठी है और हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है।

हिन्दी के प्रचार- प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका



दिलीप पंवार

निजी सचिव
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

भारत के अधिकांश भूभाग में हिन्दी पढ़ी और बोली जाती है। हिन्दी वह भाषा है जिसे देश के अधिकांश नागरिक समझते हैं और बोल सकते हैं। परन्तु उन्हें लिखने में परेशानी का अनुभव होता है। लिखने में परेशानी के कारण वे अपने लेखन से संबंधित कार्य अन्य भाषा में करते हैं। परन्तु वर्तमान में मोबाइल एवं कम्प्यूटर के उपयोग के कारण ऐसे लोगों की परेशानी भी दूर हो गई है। अतः वे बोलते हैं और मोबाइल / कम्प्यूटर में टाइप होकर मसौदा बन जाता है।

सोशल मीडिया के जरिए भी हिन्दी के प्रचार - प्रसार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आजकल फेसबुक, वाट्सअप, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब इत्यादि के द्वारा अपनी बात गुप में कम समय में अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचायी जा सकती है।

आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी किसी भी प्रकार का संदेश समूह में डाल देता है और वह कुछ ही क्षणों में वायरल होकर सम्पूर्ण देश - विदेश में पहुँच जाता है। कम्प्यूटर / मोबाइल आने से पूर्व व्यक्ति अपनी बात केवल लेखन के माध्यम से ही एक दूसरे के पास पहुँचा सकता था ऐसी स्थिति में हिन्दी भाषा में कोई भी जानकारी दूसरे व्यक्ति के पास पहुँचाने के लिए उसे हिन्दी भाषा का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक था। अगर किसी व्यक्ति को हिन्दी लिखने में परेशानी होती तो वह पत्र अंग्रेजी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में लिखकर अपने विचारों का आदान - प्रदान करता था।

परन्तु मोबाइल / कम्प्यूटर के इस युग में सोशल मीडिया के माध्यम से अगर किसी व्यक्ति को हिन्दी नहीं भी आती है तो वह हिन्दी भाषा में बोलकर अपनी बात / संदेश को कम्प्यूटर पर संदेश बनाकर भेज सकता है / वीडियो बनाकर डाल सकता है और उसकी बात / संदेश क्षणभर में ही देश के कोने - कोने तक पहुँच जाता है। इस प्रकार सोशल मीडिया के आने से हिन्दी के प्रचार प्रसार में काफी वृद्धि हुई है।

सोशल मीडिया वह प्लेटफार्म है जहाँ से कई जनोपयोगी जानकारी भी प्राप्त होती है। अगर वह अंग्रेजी में प्राप्त होती है तो उसे देश के अधिकांश लोग नहीं समझते हैं परन्तु वह हिन्दी में होती है तो उसे आसानी से देश की अधिकांश जनता समझती है। इस कारण समाज के लोग हिन्दी में अपनी बात / जानकारी को जन-जन तक पहुँचाने के लिए हिन्दी भाषा का उपयोग सोशल मीडिया के जरिए करते हैं जिससे जन सामान्य को जनोपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। इसके कारण देश के अधिकांश लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं। हिन्दी में सोशल मीडिया के जरिए जनोपयोगी जानकारी प्राप्त होने के कारण भी हिन्दी के प्रचार प्रसार में अत्यधिक वृद्धि हो रही है।

आज हम देखते हैं कि कम्पनियां, व्यापार, नेटवर्किंग मार्केटिंग करने वाले अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने उत्पाद की जानकारी जन जन तक पहुँचाने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लेती है वह उसके लिए भी उसे जानकारी हिन्दी भाषा में ही देनी होती है। अतः व्यापार बढ़ाने के लिए भी सोशल मीडिया में हिन्दी भाषा सहायक है जिसके कारण भी हिन्दी भाषा का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो रहा है।

इसी प्रकार समाज हित / नागरिकों के मौलिक अधिकारों के लिए भी सोशल मीडिया में हिन्दी में संदेश / वीडियो / वाट्सअप मैसेज डाले जाते हैं जिससे अधिकांश लोगों के लिए यह अत्यधिक उपयोगी होता है। इस प्रकार समाज हित / नागरिकों के मौलिक अधिकारों इत्यादि की जानकारी प्राप्त करने में भी सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण साधन है और इसकी जानकारी हिन्दी में होने से भी हिन्दी के प्रचार प्रसार में काफी वृद्धि हुई है।

सोशल मीडिया के मार्फत संस्कार आधारित शिक्षा / नैतिक मूल्यों का उन्नयन / माता - पिता के प्रति बच्चों का दायित्व / समाज के उत्थान के लिए क्या कार्य करने चाहिए की जानकारी भी हिन्दी भाषा में प्रकाशित होती है। इसके कारण भी हिन्दी का काफी प्रचार प्रसार हो रहा है। यहाँ तक कि हिन्दी फ़िल्में भी सोशल मीडिया पर वायरल की जाती हैं जिसके कारण भी हिन्दी का अत्यधिक प्रचार प्रसार हो रहा है।

अतः सही अर्थों में कहा जाए तो सोशल मीडिया हिन्दी के प्रचार - प्रसार के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हिन्दी के प्रचार - प्रसार के लिए सरकार द्वारा भी कई प्रकार के प्रोत्साहन पर खर्च किया जाता है। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है जहाँ न्यूनतम खर्च में समाज हित / देश हित में हिन्दी भाषा का प्रचार - प्रसार हो रहा है।

“

आज का लेखक विचारों और भावों के इतिहास की वह कड़ी है
जिसके पीछे शताब्दियों की कड़ियाँ जुड़ी हैं।

- माखनलाल चतुर्वेदी।

”

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



अनुराग द्विवेदी

वरिष्ठ तकनीकी सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भारत विश्व के विशाल राष्ट्रों में से एक है जो गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत, समृद्ध मानव सभ्यता एवं विविधता का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही भारत की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति इसे वैश्विक भू-राजनीति में विशिष्ट स्थान प्रदान करती है। तीन दशक पूर्व किये गए आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण के उपरांत भारत की आर्थिक यात्रा अनुकरणीय रही है एवं आज यह विश्व की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। जब कोरोना संकट से वैश्विक अर्थव्यवस्था त्रस्त थी, भारत ने अग्रणी भूमिका निभाते हुए विश्व को आशा की किरण दिखाई। एक वृहद मध्यमवर्ग, युवा एवं कुशल कार्यबल, नवाचार एवं उद्यमशीलता, भारतीय बाज़ार की क्षमता और उपभोक्ता आधार और वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की क्षमता जैसे कारकों की बदौलत भारत आज वैश्विक निवेशकों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का चहेता एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख आकर्षण और आपूर्ति एवं व्यापार शृंखला की महत्वपूर्ण कड़ी बन चुका है। आज यह अनेक प्रभावशाली आर्थिक मंचों के सदस्य के रूप में वैश्विक आर्थिक नीतियों और विकास कार्यों के न्यायसंगत निर्माण एवं निष्पादन में एक सक्रिय अग्रणी है।

वैश्विक भू - राजनीति में भारत की सकारात्मक भागीदारी वैश्विक शांति के लक्ष्य में परिलक्षित है। भारत का विभिन्न बहुपक्षीय साझेदारियों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संगठन, विश्व

स्वास्थ्य संगठन, विश्व वन्यजीव संरक्षण संगठन, विश्व पर्यावरण संगठन, क्लाइमेट पहल, आइ2 -यू2 समूह, बिस्टेक, जी-20, ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, भारत - अफ्रीका साझेदारी जैसे अनेक प्रभावशाली आर्थिक मंचों के सदस्य के रूप में वैश्विक आर्थिक नीतियों और विकास कार्यों के न्यायसंगत निर्माण एवं निष्पादन में एक सक्रिय अग्रणी है एवं इनके माध्यम से सुरक्षा (हिंद-प्रशांत क्षेत्र), स्वास्थ्य (वैक्सीन कूटनीति), वैश्विक अर्थव्यवस्था, गरीबी एवं भूखमरी उन्मूलन, पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा, वैश्विक-दक्षिण की समस्याओं को वैश्विक पटल पर रखना, आदि के माध्यम से एक स्थिर एवं सुरक्षित विश्व की परिकल्पना को साकार करने के लिये प्रयासरत है।

विगत कुछ वर्षों में भारत ने द्विपक्षीय दौरों, व्यापार समझौतों और क्षेत्रीय एवं बहुपक्षीय संगठनों के माध्यम से विभिन्न राष्ट्रों के साथ गहरे राजनयिक संबंध स्थापित किए और अपनी बढ़ती "सॉफ्ट पावर" के माध्यम से खुद को विश्व पटल पर एक अगुवा के रूप में स्थापित किया है। भारतीय शान्ति सेना "ब्लू हेलमेट्स" के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपनी सेवाएं दे रही हैं एवं "अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन" जैसी पहल में सक्रिय भागीदारी भारत की स्वच्छ ऊर्जा एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

भारत की बढ़ती मृदु शक्ति ने भारत के वैश्विक प्रभाव में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बॉलीवुड सहित अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों और संगीत, योग, भारतीय शास्त्रीय संगीत, भारतीय दर्शन, नृत्य, आयुर्वेद, धर्म, भाषा, वास्तुकला और साहित्य और पाककला एवं व्यंजनों ने वैश्विक जनमानस को आकर्षित किया है। आज दुनिया में रह रहे प्रवासी भारतीयों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपने सकारात्मक योगदान से भारत की छवि को निखारा - संवारा है।

स्वतंत्रता के बाद से भारत निरंतर तकनीकी प्रगति के पथ पर अग्रसर है परंतु विगत दशकों में भारत ने इस क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाई है और आज विश्व के अग्रणी राष्ट्रों की पंक्ति में आ पहुंचा है। भारत, आज, सूचना-प्रौद्योगिकी सेवाओं, सॉफ्टवेयर निर्माण,

भौतिक और साइबर प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिक्स, अनुसंधान और विकास, व्यापार समाधान आदि क्षेत्रों में वैश्विक शक्ति बन कर उभरा है एवं भारतीय उद्यमियों ने खासकर सिलिकन वैली और स्टार्ट-अप आयाम में सफलता एवं नवाचार के नए कीर्तिमान अर्जित किए हैं। 'डिजिटल इंडिया' अभियान, 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' एवं "इंडिया स्टैक" पूरे विश्व के लिए अनुकरणीय हैं।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने नए मील के पत्थर स्थापित किए हैं। चंद्रमा और मंगल पर सफल मिशन भेजना हो अथवा धरती की कक्षा में एक साथ अनेक उपग्रहों को प्रक्षेपित और स्थापित करना हो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान ने कमतर लागत पर उच्च कोटि की गुणवत्ता के साथ सफलता का परचम लहराया और विश्व को अंतरिक्ष अन्वेषण, उपग्रह संचार, और रिमोट सेंसिंग के क्षेत्रों अग्रणी बन कर नई दिशा दिखाई है। चंद्रयान-3 और गगनयान मिशनों के साथ भारत इस दिशा में एक लंबी छलांग की तैयारी में है। इन उपलब्धियों ने भारत को तकनीकी रूप से एक विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित किया है।

भारत ने अपने कार्बन पदचिह्न को घटाने, धारणीय विकास, मरूस्थलीकरण की रोकथाम और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण स्वनिर्धारित कदम उठाए हैं जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और हाइड्रो ऊर्जा, 2030 तक 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य, आदि। भारत की वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन विमर्श में समतामूलक एवं समावेशी उपायों के अन्वेषण में सक्रिय भूमिका रही है। पर्यावरण संरक्षण में भारत अग्रणी देशों में से एक है और वन्यजीवों के संरक्षण और पारिस्थितिकी के मामलों में पेरिस समझौते की रूपरेखा तय करने में भारत की निर्णायक भूमिका रही जिसमें पूर्वोत्सर्जन आधारित विभेदित ज़िम्मेदारियों की आवश्यकता पर बल दिया गया। पर्यावरण संरक्षण में भारत अग्रणी देशों में से एक है और वन्यजीवों की संरक्षा और पारिस्थितिकी के मामले में अच्छी प्रगति कर रहा है। अपशिष्ट प्रबंधन, जल वितरण और वन्यजीव संरक्षण, रामसार सम्मेलन आदि उपरोक्त पहलों के माध्यम से भारत ने जलवायु परिवर्तन मुद्दे पर विश्व को नेतृत्व प्रदान किया है।

भारत के आर्थिक विकास, राजनयिक संबंधों, तकनीकी एवं

प्रौद्योगिकी प्रगति एवं वैश्विक चुनौतियों को सुलझाने की हमारी इच्छाशक्ति एवं प्रतिबद्धता के फलस्वरूप वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका एक नेतृत्वकर्ता एवं प्रणेता के रूप में निरंतर मज़बूत हो रही है। यद्यपि गरीबी, चिकित्सा, आधारभूत ढाँचे के विकास सरीखी चुनौतियाँ समूचे विश्व के सामने विकराल मुंह खोले खड़ी हैं किंतु विश्व के विशालतम जनतंत्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय पटल पर इन विषयों को सरकार एवं समाज की तरफ से वैश्विक नीतियों को दिशा देने में आज भारत की सक्रिय एवं सकारात्मक भूमिका की प्रखर ध्वनि को सम्मान एवं नेतृत्व प्राप्त हुआ है। हाल के दशकों में वैश्विक परिदृश्य में भारत का उदय एक अग्रणी एवं बहुमुखी शक्ति के रूप में हो रहा है जो कई महती प्रयासों पर आधारित है जैसे कि विश्व भू-राजनीति, पर्यावरण एवं नवीकरणीय ऊर्जा, जीवाणु ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, सुपरकंप्यूटिंग, खाद्य सुरक्षा, सूचन एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और वैश्विक न्याय, विश्व शांति एवं सौहार्द, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, मानव संसाधन, अंतरिक्ष, अर्थव्यवस्था, आत्मनिर्भरता, आदि। भारत, जिसने विश्व को वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा से परिचित कराया, विकास के पथ पर नित नए परचम लहराते हुए अपनी भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर है एवं वैश्विक पटल पर भारत की नेतृत्वकर्ता एवं विश्वगुरुकी भूमिका अपरिहार्य है।

अंत में जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां जैसे भारत के उदय को चरितार्थ कर रही हों:

“ हिमाद्रि तुंग शृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती,
स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती
अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़- प्रतिज्ञ सोच लो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो, बड़े चलो।
असंख्य कीर्ति-रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दाह-सी,
सपूत मातृभूमि के- रुको न शूर साहसी
अराति सैन्य सिंधु में, सुवाड़वाग्नि से जलो,
प्रवीर हो जयी बनो – बड़े चलो, बड़े चलो। ”

हिन्दी के बढ़ते कदम



विनय कुमार सक्सेना

वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

“ जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य के
गौरव का अनुभव नहीं है, वह उन्नत नहीं हो सकता। ”

-डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

“ हिन्दी भारतीय संस्कृति की आत्मा है ”

डॉ. कमलापति त्रिपाठी

किसी राष्ट्र के लिए उसकी भाषा का क्या महत्व है तथा हिन्दी का भारतीय संस्कृति में क्या स्थान है, इसे इंगित करती उक्त पंक्तियां हिन्दी के महत्व एवं महिमा को मंडित करती हैं। भारतीय भाषाओं के मध्य यदि हिन्दी को देखें तो इसका इतिहास अति प्राचीन नहीं है, किन्तु पिछले एक हजार वर्ष में हिन्दी ने अपनी यात्रा को अनवरत जारी रखा। यद्यपि इसका स्वरूप भिन्न-भिन्न रहा, किन्तु हिन्दी निरंतर परिलक्षित होती रही। कभी वह चंदबरदाई रचित 'पृथ्वीराज रासो' में झांकती नजर आती है तो कभी तुलसीदास जी की रचनाओं में अपनी झलक दिखलाती है। अमीर खुसरो, मीरा बाई, सूरदास की गोद में खेरी एवं बड़ी होती हिन्दी भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं में अपना यौवन बिखेरती सी लगती है। भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में 'वंदे मातरम्', 'जय हिन्द', 'स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है', 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' जैसे नारों में हुंकार भरती नजर आती है। स्वतंत्रता के पश्चात् हिन्दी जन-जन की भाषा बन संविधान में

अंकित होकर राजभाषा का दर्जा ग्रहण करती है। हिन्दी की इस समय यात्रा पर विहंगम दृष्टि डाली जाए तो हिन्दी के बढ़ते कदम की छाप स्पष्ट नजर आती है।

हिन्दी की वर्तमान स्थिति

वर्तमान में हिन्दी के स्वरूप पर दृष्टि डाली जाए तो विश्व में बोली जाने वाली संख्या के आधार पर चीन की मंडारिन भाषा के बाद दूसरे क्रम की भाषा के रूप में इसकी पहचान बनी है, जो इसके बढ़ते कदम की परिचायक है। यद्यपि हिन्दी ने अपनी जन्मभूमि में काफी संघर्ष किया है और अंग्रेजी के अंधमोह के चलते अपने उच्च स्थान को पाने में आज भी संघर्षरत है, किन्तु शनैः शनैः व्यवसाय की भाषा बनती हिन्दी ने पुनः अपने कदमों को तेजी से आगे बढ़ाया है। वर्तमान में हिन्दी न केवल भारत में अपितु विश्व के अनेक देशों जैसे मॉरिशस, त्रिनिदाद, सूरीनाम, स्पेन, हंगरी, फिजी, पोलैंड, अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, यूक्रेन, टर्की, ईरान, वियतनाम, मलेशिया आदि देशों के साथ ही अन्य विकसित देशों में भी फल-फूल रही है।

हिन्दी के बढ़ते कदम में आने वाली बाधाएं

हिन्दी ने जब-जब कदम तेजी से बढ़ाने का प्रयास किया तो कई बाधाएं उसके समक्ष आ खड़ी हुईं, जो निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट हैं-

1. अंग्रेजी के अंधमोह में हिन्दी के प्रति उपेक्षा का भाव।
2. वैज्ञानिक भाषा के रूप में उपयोग में न लाया जाना।
3. तकनीकी विषयों हेतु तकनीकी शब्दावली का अभाव होना।
4. उच्च शिक्षा का सशक्त माध्यम के रूप में स्वीकार न होना।
5. हिन्दी को लेकर राजनैतिक इच्छाशक्ति का अभाव।
6. सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में संवाहक भाषा के रूप में उचित स्थान न पाना।
7. भारत में अभी भी कई क्षेत्र जैसे न्यायालय, संसद आदि में हिन्दी का पूर्ण रूपेण प्रयोग न होना।

हिन्दी के बढ़ते कदम को गति देने के उपाय

हिन्दी के बढ़ते कदमों को गतिमान करने के लिए जो कारगर उपाय

हो सकते हैं, वे इन बिन्दुओं में समाहित हैं-

1. हिन्दी को एक भाषा न मानकर राष्ट्र गौरव से जोड़ना होगा और उसे उतना ही सम्मान देना होगा, जितना राष्ट्रगान या राष्ट्रीय ध्वज के प्रति हम व्यक्त करते हैं।
2. हिन्दी को सशक्त वैज्ञानिक/तकनीकी शब्दावली से श्रृंगारित करना होगा।
3. उच्च शिक्षा विशेषकर इंजीनियरिंग, चिकित्सा क्षेत्र, प्रबंधन क्षेत्र में हिन्दी भाषा में अध्ययन की सुविधा खोजनी होगी।
4. सूचना-प्रौद्योगिकी में भी हिन्दी सशक्त भाषा के रूप में सामने आ सकती है, यदि उसके अनुरूप इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए।
5. हिन्दी के प्रयोग को लेकर राजनैतिक इच्छाशक्ति का होना अपरिहार्य है।
6. जनहित से जुड़े हर क्षेत्र में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देना होगा।
7. हिन्दी को विश्व भाषा के रूप में स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग तथा उसके महत्व को मनवाते हुए उसका उच्च स्थान सुनिश्चित करना होगा।

सूचना-प्रौद्योगिकी के पंख पाकर हिन्दी की उड़ान

सूचना-प्रौद्योगिकी के युग में अनेक भारतीय कम्प्यूटर निर्माता कम्प्यूटर के हिन्दीकरण के लिए प्रयत्नरत हैं। उनके अथक परिश्रम से आज बाजार में हिन्दी में कार्य करने के लिए कई सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। यद्यपि सूचना-प्रौद्योगिकी के लिए भाषा का प्रश्न गौण है, किन्तु हिन्दी पढ़ने-पढ़ाने की जिम्मेदारी सूचना-प्रौद्योगिकी के द्वारा सफल की जा सकती है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जिस भाषा में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के संप्रेषण की जीवंत क्षमता नहीं होगी, वह अपनी शक्ति व उपयोगिता कायम नहीं रख सकती।

जनभाषा से राजभाषा और राजभाषा से विश्व भाषा की ओर हिन्दी

हिन्दी की समय यात्रा में हिन्दी को सबसे अधिक प्रश्रय जनभाषा के रूप में ही प्राप्त हुआ। स्वतंत्रता के पश्चात इसी जनभावना का

सम्मान करते हुए राष्ट्र निर्माताओं ने हिन्दी को संविधान में 14 सितंबर, 1949 को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। राजनैतिक इच्छाशक्ति के बल पर हिन्दी विश्वभाषा बनने की ओर कदम बढ़ाने लगी है। वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जिस तरह विश्व पटल पर अपने विचार बेबाकी से हिन्दी भाषा में रखे हैं, वह इस ओर संकेत करता है कि हिन्दी अपने कदमों से संसार नापने चल पड़ी है।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि हिन्दी अपने भूतकाल से निरंतर आगे बढ़ती, वर्तमान में अपने पदचिह्नों को छोड़ती, उज्ज्वल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है और विश्वभाषा की दावेदारी भी प्रस्तुत कर रही है, किन्तु यहां हमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों को विस्मृत नहीं करना चाहिए जो हिन्दी की वास्तविकता एवं व्यथा को प्रस्तुत करती हैं-

“ बनने चली विश्वभाषा जो अपने घर में दासी,
अंग्रेजी को सिंहासन पर रखकर दुनिया हांसी।

हिन्दी वाले हैं चपरासी

सारे अफसर अंग्रेजीमय

बंगाली हो या मद्रासी।

कह 'कैदी कविराय' विश्व की चिंता छोड़ो

पहले अपने घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। ”

अपने ही घर में हिन्दी को सबसे बड़ी चुनौती विदेशी भाषा अंग्रेजी से मिलती है, उक्त पंक्तियां यद्यपि उस समय हिन्दी की स्थिति पर एक सशक्त व्यंग्य था, परन्तु हिन्दी को अति उत्साह की नहीं अपितु एक राजनैतिक इच्छाशक्ति एवं जन-जन की संकल्पशक्ति की आवश्यकता है, जो उसके बढ़ते कदम को विराम न लगने दे।

हिंदी के प्रचार – प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका



संजय डोंगरे

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, हिंमना, नागपुर

भारत में भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा 14 सितम्बर 1949 को दिया गया। तबसे हर 14 सितम्बर को सरकारी कार्यालय में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

तबसे अब तक राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी को स्वीकार करने में मुख्य रूप से रेडियो, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ, सिनेमा टेलीविज़न, इंटरनेट एवं मोबाइल आदि की मुख्य भूमिका रही है। आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो द्वारा हिंदी समाचार, शिक्षा, सामाजिक, संगीत, मनोरंजन आदि स्तरों पर अपने प्रसारण के माध्यम से हिंदी को देश के कोने-कोने में पहुँचा दिया है। इसमें हिंदी कार्यक्रम और फ़िल्मी गानों का विशेष स्थान रहा है जिसने हिंदी को देशभर में लोगो की जबान पर ला दिया है। पहले यह कार्य आकाशवाणी करती थी अब निजी एफ. एम. चैनल कर रहे हैं। रेडियो में मनोरंजन के अलावा समाचार, खेल समाचार, क्रिकेट का आँखों देखा हाल, किसानों तथा मजदूरों और बाल व महिला कार्यक्रमों ने हिंदी की महत्ता बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

इसके बाद आता है समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ जिसके माध्यम से हम सभी लोग एक कड़ी में जुड़ते हैं, समाचार - पत्र एवं पत्रिकाएँ जैसे तो कई प्रादेशिक भाषाओं में छपते हैं, परन्तु संपूर्ण देश में हिंदी समाचार - पत्रों की ज्यादा खपत होती है। उक्त पत्र में सामाजिक, व्यापारिक, आर्थिक राजनितिक, शैक्षणिक तथा अन्य सामान्य

विषयों पर लेख छपे होते हैं, उक्त समाचार - पत्र एवं पत्रिकाओं में हमें रोज नई-नई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है तथा देश विदेश में क्या चल रहा है, वह ज्ञात होता है। समाचार एवं पत्रिकाओं में विभिन्न कंपनियों द्वारा हिंदी भाषा में विज्ञापन देने की होड़ लगी रहती है, इससे पता चलता है कि हिंदी भाषा कितनी महत्वपूर्ण है। अब वह समय दूर नहीं कि हिंदी भाषा पूर्ण रूप से भारत की एकमात्र संपर्क भाषा बन जाएगी। आजादी के पहले अंग्रेजी में ही छपती थी किन्तु शिक्षा एवं साक्षरता के कारण उक्त अवधारणा बदलने लगी तथा हिंदी और अन्य भाषा में अखबार पढ़नेवालों की संख्या बढ़ने लगी, उसी प्रकार हिंदी समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ उच्च शिक्षित लोगों का ही नहीं बल्कि कम पढ़े-लिखे लोगों का भी शौक बन गया है। भले ही गंभीर विषयों पर हिंदी पत्रिकाएँ कम निकलती हैं, परन्तु सामान्य - ज्ञान, फिल्म, फैशन, महिलाओं पर सम्बंधित विषयों पर साहित्य, पर्यटन, विज्ञान जैसे विषयों पर बहुत अच्छी पत्रिकाएँ हिंदी में निकलती हैं।

मीडिया का सबसे प्रभावशाली माध्यम यानि हिंदी सिनेमा या फिल्म क्षेत्र जिसके बदौलत कितने ही लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है वैसे भी उस वक्त सिनेमा ही एकमात्र मनोरंजन का साधन था तथा कुछ फ़िल्में विभिन्न भाषा में भी बनते थे, परन्तु हिंदी भाषा में अनेक सिनेमा बनने के बाद वह काफी प्रचलित हो गए थे, आज कितने फ़िल्मी कलाकार बढ़िया जीवन - यापन कर रहे हैं, निर्देशक, निर्माता, लेखक, संगीतकार तथा जुनियर कलाकार इन हिंदी सिनेमा के बदौलत अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हिंदी भाषा में उक्त फिल्मों या सिनेमा के कारण उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक शहरों में हिंदी भाषा का निरंतर प्रचार - प्रसार हुआ है तथा सभी ने इसे स्वीकार किया है, सोशल मीडिया के रूप में सिनेमा ने हिंदी भाषा को एक अलग ही रूप प्रदान किया है।

सोशल मीडिया का सबसे सुन्दर रूप टेलीविज़न माना गया है। टेलीविज़न श्रव्य के साथ साथ दृश्य भी दिखलाता है, इसलिए यह अधिक रोचक तथा अच्छा लगता है। वर्ष 1980 से 1990 के दशक में मनोरंजन एवं समाचारों के प्रसारण के जरिये हिंदी को लोकप्रिय

बनाने में काफी योगदान किया है। वर्ष 1990 के दशक के बाद निजी चैनलों के पदार्पण के पश्चात यह प्रक्रिया और तेज हो गयी, रेडियों की तरह टेलीविज़न ने भी मनोरंजन कार्यक्रमों में पारिवारिक सीरियलों का तथा फिल्मों का भरपूर उपयोग किया है। टेलीविज़न में फीचर फिल्मों, वृत्तचित्रों तथा फ़िल्मी गीतों, विभिन्न हास्य सीरियल के प्रसारणों से हिंदी भाषा को देश के कोने - कोने तक पहुँचाने के सिलसिले को आगे बढ़ाया है।

टेलीविज़न में दिखाए जाने वाले या प्रसारित किये जाने वाले सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक विषयों को लेकर बनाये गए हिंदी धारावाहिक घर - घर में देखे जाने लगे, उक्त धारावाहिक न केवल हिंदी प्रचार - प्रसार के वाहक बने बल्कि राष्ट्रीय एकता के सूत्र बन गए। इस कारण पूरे देश में टेलीविज़न कार्यक्रमों की लोकप्रियता की बदौलत देश के अहिन्दी भाषी लोग हिंदी समझने और बोलने लगे।

विश्व में या देश में वैश्विकरण के कारण जनसंचार माध्यमों का दायरा व्यापक एवं विस्तृत हो गया है। नए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में इंटरनेट एवं मोबाइल अधिकांश लोगों द्वारा बोली एवं उपयोग में

लायी जाने वाली हिंदी को अनेक लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहा है, मीडिया में इंटरनेट ने भारत में पाँव पसारने शुरू किये तो यह आशा व्यक्त की गयी कि कंप्यूटर के कारण देश में अंग्रेजी का बोलबाला हो जायेगा, किन्तु यह धारणा गलत साबित हो गयी और आज हिंदी वेबसाइट और ब्लॉग न केवल धड़ल्ले से चल रहा है बल्कि देश के साथ - साथ विदेशों के लोग भी इनपर सूचनाओं का आदान - प्रदान तथा चैटिंग कर रहे हैं, इसी कारण सभी सरकारी या गैर - सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस का व्यापक रूप से उपयोग हो रहा है। इंटरनेट के साथ - साथ मोबाइल फ़ोन का भी उपयोग हो रहा है। हम मोबाइल फ़ोन से व्हाट्सपप एंड फेसबुक के द्वारा जानकरियां एक - दूसरे को देते हैं तथा विभिन्न जानकारी हम तुरंत प्राप्त करते हैं। पहले यह सब अंग्रेजी में होता था पर अब यह जानकारी हिंदी में आदान प्रदान की जाती है।

आजकल खासकर विभिन्न फॉण्ट तथा यूनिकोड फॉण्ट आने के बाद लोगों के लिए हिंदी में पढ़ना - लिखना और आसान हो गया है तथा आज की युवा पीढ़ी मोबाइल फ़ोन के अधीन हो चुकी है। हिंदी में जितनी सृजन और अभिव्यक्ति की स्वंत्रता है, उतनी किसी भाषा में नहीं हो सकती है।

“ आप जिस तरह बोलते हैं, बातचीत करते हैं,
उसी तरह लिखा भी कीजिए।
भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए। ”

- महावीर प्रसाद द्विवेदी

विश्व पटल पर हिन्दी



कृति गुप्ता
आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

विश्व में भाषाओं के अपने नक्शे हुआ करते हैं, हर भाषा का अपना एक भूगोल होता है, उसका अपना मानचित्र होता है। ये भाषाएं किसी सरकारी प्रतिबंध अथवा प्रश्रय द्वारा संचालित नहीं होतीं। भारत जैसे बहुभाषी देश में जहां भाषा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हो, जहां सदियों से यह कहावत है कि – “कोस-कोस पर पानी बदले, चार कोस पर वाणी”, वहाँ जाहिर है कि किसी भी भाषा विशेष को स्थापित करने में उस भाषा के अंदर सर्वसमावेशी, सर्वग्राह्यता, सहजता जैसे गुण होने अनिवार्य हैं। विश्व में मानचित्र पर दृष्टि डालें तो हिन्दी की जन्मस्थली भारत है, इसका बोध होता है। हिन्दी के संदर्भ में अध्ययन किया जाए तो यह इंडो-यूरोपियन वंश के आर्य परिवार की भाषा है, वर्तमान में विश्व में बोली जाने वाली संख्या के आधार पर मंडारिन भाषा के बाद दूसरे क्रमांक पर आती है।

विश्व पटल पर हिन्दी : एक दृष्टिकोण

अपने जन्म स्थान भारत से दूर विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ हिन्दी ने अपनी उड़ान न भरी हो। विश्व पटल पर यदि हम दृष्टि डालें तो अधिकांश भाषाएं साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की देन रही हैं, किन्तु हिन्दी का विश्व पटल पर स्थान बनाने का आधार जनभावनाओं का स्वीकार्य भाव है। विश्व पटल पर जहां एक ओर भाषाओं को जबरदस्ती थोपने का इतिहास रहा है, वहीं हिन्दी भाषा का एक भी ऐसा उदाहरण नहीं मिलता, जहां इसके चाहने

वालों ने कभी कोई भाषाई साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास किया हो। हिन्दी सदैव से सौहार्द की भाषा रही है और यह भारतीय संस्कृति की ध्वजावाहक बनकर विश्व के प्रत्येक कोने में पहुंची है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भारतीय संस्कृति की “वसुधैव कुटुम्बकम्” की अवधारणा को हिन्दी ने विश्व पटल पर स्थापित किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी

विश्व पटल पर भारत को हिन्दी के परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ में गत वर्ष बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जून, 2022 को बहुभाषावाद के आधार पर भारत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए हिन्दी भाषा को अपनी भाषाओं में समाहित कर लिया। इसका तात्पर्य यह है कि अब संयुक्त राष्ट्र अपने संचार और संदेशों के प्रसार के लिए हिन्दी भाषा का भी उपयोग करेगा। संयुक्त राष्ट्र के इस प्रस्ताव से संपूर्ण विश्व को उसके कार्यों की जानकारी हिन्दी में उपलब्ध होगी। संयुक्त राष्ट्र के इस कदम से हिन्दी को वैश्विक प्रसार एक ऊर्जामय गति मिलेगी। अब विश्व पटल पर हिन्दी अधिक स्वीकार्यता और ताकत के साथ नजर आएगी। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में अब तक सिर्फ 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, हिन्दी इसमें सातवीं आधिकारिक भाषा बनने की राह में उक्त प्रस्ताव के द्वारा गतिमान हो चुकी है।

विश्व में हिन्दी

वर्तमान में पूरे विश्व में लगभग 25 देशों की करीब एक अरब आबादी ऐसी है, जो हिन्दी बोल या समझ सकती है। भारत के अलावा नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, थाइलैंड, चीन, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मॉरीशस, यमन, युगांडा, त्रिनिदाद, सूरीनाम, स्पेन, हंगरी, रूस, फिजी, पोलैंड, अफगानिस्तान, उजबेकिस्तान, फ्रांस, इटली, यूक्रेन, नीदरलैंड, टर्की, ईरान, वियतनाम, मलेशिया, मंगोलिया जैसे कई देशों में हिन्दी भाषा का चलन है। इनमें से अनेक देशों में हिन्दी पीठ स्थापित की है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा मॉरीशस में हिन्दी

भाषा के प्रसार हेतु विश्व हिन्दी सचिवालय भी कार्यरत है।

हिन्दी को विश्व पटल पर स्थापित करने में भारतीय संस्थाओं का योगदान

हिन्दी को विश्व पटल पर स्थापित करने में भारत की तीन बड़ी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वे संस्थाएं हैं :-

1. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा।
2. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली।
3. महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा पिछले छह दशकों से विश्व पटल पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व के अनेक देशों के छात्र यहां हिन्दी भाषा में दक्षता प्राप्त कर रहे हैं। प्रतिवर्ष चालीस से पचास देशों के छात्र यहां आकर हिन्दी भाषा के साथ-साथ भारतीय संस्कृति के वैशिष्ट्य को समझते हैं। इस संस्था के हिन्दी अध्यापक विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों के आमंत्रण पर वहां हिन्दी भाषा के अध्यापन में योगदान कर रहे हैं।

भारतीय विदेश मंत्रालय के अधीन भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नई दिल्ली अपने सांस्कृतिक केन्द्रों के साथ विश्व के विभिन्न देशों में कार्यरत है, जिनके माध्यम से भारतीय संस्कृति का प्रसार तो होता ही है, हिन्दी भाषा के प्रसार में भी इस संस्था की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संस्था ने अनेक देशों में हिन्दी पीठ स्थापित की है।

महात्मा गाँधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)

विदेशी छात्रों के लिए हिन्दी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा हिन्दी भाषा में अपने देश की भाषा के साथ तुलनात्मक शोध को बढ़ावा देने में अग्रसर है। विदेशी हिन्दी विशेषज्ञों के लिए विभिन्न संगोष्ठियां आयोजित कर विश्व पटल पर हिन्दी को स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उक्त संस्थाओं के महत्वपूर्ण योगदान के अतिरिक्त हिन्दी के प्रचार-प्रसार और प्रोत्साहन में भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन राजभाषा विभाग अपने दायित्व को बखूबी निभा रहा है वहीं दूसरी ओर हिन्दी को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए भारतीय विदेश मंत्रालय की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मंत्रालय द्वारा हर वर्ष विश्व हिन्दी सम्मेलन, प्रवासी भारतीय दिवस जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

हिन्दी की जन्मस्थान भारत से विश्व पटल तक की यात्रा उसमें समाहित गुणों के आधार पर ही संभव हो रही है, जहाँ एक ओर भारतीय भाषाओं का दायरा मुख्य रूप से उनके संबंधित राज्यों तक ही सिमटा है, वहीं विश्व पटल पर हिन्दी की स्वीकार्यता बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण उसका अपेक्षाकृत सरल और सर्वग्राही होना है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंग्रेजी ने पहले ही हिन्दी को कमजोर बनाने में अहम भूमिका निभाई है, इसीलिए अब हिन्दी की स्थिति को मजबूत करने एवं विश्व पटल पर स्थापित करने वाली कोशिशों को सकारात्मक रूप में लेकर आगे बढ़ना होगा तथा गंभीरतापूर्वक इस वास्तविकता को ध्यान में रखना होगा कि हिन्दी न केवल भारत की राजभाषा है, बल्कि यह लोकभाषा, मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा के साथ-साथ विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है और उसे “वसुधैव कुटुम्बकम्” की भांति सारी भाषाओं के साथ “भाषा कुटुम्बकम्” को चरितार्थ करना है।

सोशल मीडिया पर हिंदी भाषा का वर्चस्व



रोहन सुहास तिजारे
वरिष्ठ प्रयोगशाला परिचर
भारतीय खान ब्यूरो, हिंगना, नागपुर

सोशल मीडिया के इस युग दौर में,
व्हाट्सप्प और फेसबुक रूपी माध्यमो द्वारा !
हिंदी भाषा को मानो कि जैसे,
एक नई दिशा मिल गई हो !!

शहर हो या गाँव हो,
वृद्ध हो या युवा वर्ग हो !
मातृभाषा को माने जैसे,
एक नई प्रज्वलित हुई क्रांति मिल गई हो !!

जहाँ अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व के कारण,
हिंदी भाषा के बहुत कठनाई के इस सोशल मीडिया के युग दौर में !
हिंदी के प्रचार और प्रसार द्वारा हिंदी को मानो जैसे,
एक नई विश्वरूपी उड़ान मिल गई हो !!

इंटरनेट के भारत में कदम रखने बाद मानो
देश मे आशंका थी कि अंग्रेजी का बोलबाला हो जाएगा !
परंतु निरंतर हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के कारण मानो जैसे हिंदी को
एक नया जीवन मिल गया हो !!

21 वी सदी के सोशल मीडिया के दौर में,
अंग्रेजी भाषा के मायाजाल से निकलकर !!
देश को हिंदी भाषा की मानो जैसे,
एक नई देशव्यापी बुनियाद मिल गई हो !!

सोशल मीडिया के अनंतरूपी जीवनकाल में,
हिंदी में कार्य करने की !
युवाओं को माने जैसे,
एक नई ऊर्जा मिल गई हो !

विश्वस्तर पर देश के हित में,
हिंदी को अपनाकर !!
देश को माने प्रगति के पथ पर चलने की जैसे
एक नई प्रेरणा मिल गई हो !!

रोजमर्रा की जीवनशैली में,
अंग्रेजी के बढ़ते हुए कठनाईयों के !!
इस दौर की लहर में,
एक नई हिंदीरूपी राह मिल गई हो !!

आर्थिक और सामाजिक स्तर पर,
अग्रेसर होते हुए हिंदी भाषा को मानो !
सोशल मीडिया के रूप में कायमस्वरूपी,
एक नया आधार मिल गया हो !!

सोशल मीडिया के इस व्यापक रूपी
और सुचारू माध्यम द्वारा
मानो जैसे हिंदी को
एक नई पहचान मिल गई हो !! ■



वैश्विक परिदृश्य में हिंदी के बढ़ते कदम



बाबू लाल गुर्जर

अवर श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

सृष्टि के निर्माण काल से ही भाषा का संबंध मानव समाज से रहा है। मानव जीवन में भाषा एक अभिन्न अंग है, जिसके बिना मानव गूंगा है। इस विश्व में कई महाद्वीप, राष्ट्र, प्रांत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन “चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वाणीध्वीस कोस पर पगडी बदले, तीस कोस पर धानी” आज भी चरितार्थ हो रहा है। विदेशों से व्यापार करने के लिए आवश्यकतानुसार भाषा अपनाती पड़ती है। उपभोक्ता वस्तुओं की बिक्री और उनके प्रचार के लिए अपनाये जाने वाले साधनों में स्थानीय भाषा का उपयोग होता है। भारत में इस कार्य के लिए अधिकतर हिंदी का उपयोग हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना माल बेचने के लिए हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं अपना रही हैं।

हिंदी विश्वभाषा की ओर- सकारात्मक प्रवृत्तियां

हिंदी एक विश्वभाषा है, क्योंकि वह एक देश की राष्ट्रभाषा होने के साथ-साथ अन्य देशों में भी पर्याप्त संख्या में लोगों द्वारा लिखी, बोली और समझी जाती है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रति सकारात्मक प्रवृत्तियां इस प्रकार दिखाई दे रही हैं:-

- भौगोलिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि इसके बोलने-समझने वाले संसार के सब महाद्वीपों में फैले हैं।

- जनतांत्रिक आधार पर हिंदी विश्व भाषा है क्योंकि उसके बोलनेसमझने वालों की संख्या संसार में तीसरी है।

- विश्व के १३२ देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग दो करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं।

- एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं से अधिक एशिया की प्रतिनिधि भाषा है।

- हिंदी स्वयं में अपने भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत छिपाए हुए हैं। आर्य, द्रविड़, आदिवासी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, जापानी सारे संसार की भाषाओं के शब्द इसकी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री एवं वसुधैव कुटुंबकम वाली प्रवृत्ति को उजागर करते हैं।

- प्रवासी भारतीय (एनआरआई) वैश्वीकरण का सबसे प्रत्यक्ष वाहक लगते हैं और आडियो-वीडियो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसके बीच हिंदी एक जीवंत कड़ी बन रही है।

- देश-विदेश में प्रकाशित होने वाले पत्र - पत्रिकाओं ने हिंदी को विश्व भाषा बनाया है। इनके द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य का प्रसार विदेशों में हुआ है।

विश्वभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष समस्या

विश्वभाषा के रूप में हिंदी के समक्ष अन्य अनेक समस्याएं हैं जैसे- विदेशों से जिस अनुपात में भारतीय हिंदू संस्कृति का हास और पश्चिमी भोगवादी सभ्यता का विकास होता चला जा रहा है, उसी मात्रा में हिंदी का प्रचलन काफी कम होता जा रहा है। भारत से प्रवजन, पलायन करने वाले युवा बुद्धिजीवियों और श्रमिकों पर यह भाषा टिकी हुई है किंतु वे बड़ी तेजी से अंग्रेजियत के रंग में रंगते जा रहे हैं। उनकी अगली पीढ़ी हिंदी से अपरिचित सी है। जब इसे संविधान में भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया तो ऐसा माना जाने लगा कि इसे देर-सवेर संयुक्त राष्ट्र संघ एवं संसार की अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं-संस्थानों में भी स्थान मिलेगा और

अंतर्राष्ट्रीय संपर्क की भाषा के रूप में इसे भी मान्यता प्राप्त होगी लेकिन ऐसा नहीं हो सका है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार के निमित्त अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, यथासंभव अनुदान भी दिया गया किंतु जिस लक्ष्य को लेकर उसकी स्थापना की गई थी वह अपनी लक्ष्य सिद्धि तक नहीं पहुँच सका है। भारत विश्व बाजार की टेक्नोलॉजी से जुड़ तो रहा है पर केवल अंग्रेजी के माध्यम से। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की इन आधुनिक संचार साधनों में उपस्थिति काफी कम है।

निर्यात के क्षेत्रों में दस्तावेजों आदि के लिए प्रयुक्त मानक फार्म आदि मात्र दिखावा बनकर रह गए हैं, उनका उपयोग बहुत ही कम हो रहा है। ऐसे में विश्व बाजार से जुड़े कानूनी दाव-पेंचों, विश्व व्यापार संगठन के समझौतों, उनके संबद्ध दस्तावेजों और उस समस्त प्रक्रिया में हिंदी के प्रयोग की कल्पना करना कठिन है।

हिंदी को विश्व भाषा बनाने के लिए सुझाव

10 जनवरी को विश्व के लगभग 180 देशों में विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में जब हम विदेश में हिंदी की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य विदेश में हिंदी भाषा के अधिक से अधिक प्रसार के साथ ही विविध क्षेत्रों में हिंदी के उपयोग से है। उसके प्रसार और उपयोग में कई कठिनाइयां हैं, जिनके समाधान की आवश्यकता है। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं -

वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी की भूमिका सार्थक हो तथा उसका प्रयोग बढ़ सके इसके लिए पहली आवश्यकता हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि के मानकीकरण की है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने जो लिपि का मानकीकरण किया उसका उपयोग निदेशालय के अलावा कहीं नहीं होता। यहां तक कि सरकारी प्रकाशनों में भी नहीं, निजी प्रकाशकों की बात तो छोड़ ही दीजिए। यही स्थिति हिंदी भाषा की भी है। हिंदी देश की संविधान स्वीकृत राजभाषा है किंतु उसके मानकीकरण की बात प्रशासकीय स्तर पर कोई नहीं सोचता।

विदेशी हिंदी प्रशिक्षकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम हो, जिनमें उनकी समस्याओं पर विचार हो और योजनाबद्ध तरीके से अपेक्षित लक्ष्य के लिए विशिष्ट पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाएं। सूचना क्रांति के युग में हिंदी को भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में अपनी भूमिका का महत्व बताना होगा। अतः इसे कंप्यूटर की भी भाषा बनाना होगा। हिंदी में ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करने होंगे जिनसे वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और भी आसानी तथा सहजता से संभव हो सके। हिंदी के सामने कई चुनौतियां हैं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम वास्तविक स्थिति और अपनी कमियां समझें, हमें लक्ष्य का स्पष्ट ज्ञान हो, लक्ष्य प्राप्ति की सार्थक योजनाएं बनें, ईमानदारी तथा दृढ़ता से योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए तथा समय-समय पर प्रगति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। हिंदी को विश्व में अपना स्थान बनाए रखने के लिए मिलकर प्रयास करने की जरूरत है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



प्रदीप कुमार सिन्हा

उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

आज पूरे देश में भारत की भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। जो कि हर क्षेत्र में भारत सभी देशों से धीरे-धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। आज यह विश्व की एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर सामने आया है।

प्रस्तावना:

विश्व इतिहास के पन्नों पर भारत एक ऐसा देश रहा है, जिसका सौंदर्य, संस्कृति, विविधता और धरोहर दुनियाभर में चर्चित है। भारत ने हजारों वर्षों तक अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोया है और विभिन्न कला, साहित्य, विज्ञान, धर्म, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। विश्व के भीतर भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को नजरअंदाज करना असंभव है। आज हम इस लेख के माध्यम से देखेंगे कि वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका कैसे निभा रही है।

1. अर्थव्यवस्था में बढ़ती भूमिका : विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है, जो आधुनिक युग में एक तेजी से बढ़ती हुई देश के रूप में उभर रही है। भारत एक विशाल बाजार है और आने वाले दशकों में आकर्षक निवेश संरचना के रूप में विकसित हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय सेक्टर, तकनीकी उन्नति, औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचे में सुधार विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के माध्यम से भारत की बढ़ती भूमिका को पुष्टि करते हैं।

2. सांस्कृतिक धरोहर: भारत एक विविधता से भरा हुआ राष्ट्र है जो विभिन्न संस्कृतियों, जातियों, धर्मों और भाषाओं के समृद्ध संगम को प्रस्तुत करता है। यहां के ऐतिहासिक भवन, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और गिरजाघर दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। भारतीय संस्कृति में गहन अध्ययन के लिए विश्व भर में लोग आते हैं जिससे भारत की सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति: भारत वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यहां के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी रूप से विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत तकनीकी उपकरणों और अनुसंधान के लिए प्रशंसा प्राप्त की है। भारतीय वैज्ञानिक सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहकर विश्व के उद्दीपन के लिए संशोधन कर रहे हैं।

4. विदेश नीतियों में भूमिका: भारत विदेश नीतियों में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ तालमेल, सहयोग, विश्वास और भरोसे के बारे में जाना जाता है। भारत विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों में अपनी भूमिका को और मजबूत कर रहा है और समस्याओं के समाधान में सहयोग कर रहा है। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, विज्ञानिक उन्नति और सांस्कृतिक धरोहर के साथ विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है।

5. सुरक्षा और रक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका: भारत विश्व में अपने मजबूत सुरक्षा और रक्षा नीतियों के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने सैन्य और रक्षा बलों के द्वारा अपनी सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करता है। भारत अपने संबंधित राष्ट्रों के साथ बांध को मजबूत करने के लिए अपनी विदेशी नीतियों में भी एक अहम भूमिका निभाता है।

6. पर्यावरण और स्वच्छता में योगदान: भारत विश्व भर में पर्यावरण और स्वच्छता को संरक्षित रखने में भी अपना योगदान दे रहा है। यह प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जल संरचना और

वातावरण संरक्षण के लिए अपने संबंधित योजनाओं के माध्यम से प्रसिद्ध है। स्वच्छता अभियान और पर्यावरण संरक्षण में भारत अपने अध्यात्मिकता के साथ प्रेरित करता है।

7. विश्व के साथ वैज्ञानिक और शैक्षिक सहयोग: भारत विश्व भर में वैज्ञानिक और शैक्षिक क्षेत्र में भी सहयोग और पारस्परिक अभिवृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। यहां के विश्वविद्यालय और शोध संस्थान ने विदेशी छात्रों को अपने उच्चतम स्तर के शिक्षा प्रदान करने के लिए विख्यात हैं। भारत के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का अध्ययन करने के लिए विदेशी छात्र यहां पहुँचते हैं, जो

विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों के लिए एक विकसित योजना देते हैं।

समाप्ति: वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत विश्व के भीतर एक महत्वपूर्ण राष्ट्र बन रहा है। इसकी अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक धरोहर, वैज्ञानिक उन्नति और विदेशी नीतियों में भूमिका को देखते हुए भारत अपने नए युग की ओर अग्रसर है। यह समृद्धि, विकास और समृद्धि के माध्यम से विश्व के सभी लोगों को मिले और एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है।

“

इस विशाल प्रदेश के हर भाग में शिक्षित-अशिक्षित,
नागरिक और ग्रामीण सभी हिन्दी को समझते हैं।

- राहुल सांकृत्यायन

”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का योगदान



शिवशंकर
भंडार लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

विश्व के इतिहास पर दृष्टि डालें तो गुलामी से आजादी के बाद दुनिया के प्रायः सभी देशों ने अपनी भाषा में अपनी प्रगति का मार्ग चुना। इजराइल ने तो अपनी मृतप्राय हो चुकी हिब्रू भाषा को अपनी राष्ट्रभाषा बनाया और आज वह भाषा पूरी दुनिया में तकनीक की प्रमुख भाषाओं में शामिल है। आज हिब्रू का अनुवाद अन्य भाषाओं में लोग करने को मजबूर होते हैं। रूस ने रशियन, चीन ने चीनी और जापान ने जापानी भाषा को अपनी शिक्षा-दीक्षा तथा राजकाज की भाषा बनाया। हमारे छोटे से पड़ोसी देश नेपाल ने भी अपनी भाषा नेपाली ही बनाई। भारत इसका अपवाद रहा है।

किसी भी भाषा के लुप्त होने या उसके संकटग्रस्त श्रेणी में आ जाने के परिणाम बहुत दूरगामी होते हैं। भाषा का एक-एक शब्द महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक शब्द अपने पीछे संस्कृति की एक लंबी परंपरा को लेकर चलता है। इसलिए भाषा लुप्त होते ही संस्कृति पर खतरा मंडराने लगता है। संस्कृति और उस भाषा के संचित ज्ञान को बचाने के लिए भाषा के संरक्षण की बहुत आवश्यकता है। भारत की नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा गया है कि दुर्भाग्य से भारतीय भाषाओं को समुचित ध्यान और देखभाल नहीं मिल पाया है, जिसके तहत देश ने विगत 50 वर्षों में 220 भाषाओं को खो दिया है। युनेस्को ने 197 भारतीय भाषाओं को लुप्तप्राय घोषित कर दिया है। देश में इन समृद्ध भाषाओं-संस्कृति की

अभिव्यक्ति को संरक्षित या उन्हें रिकार्ड करने के लिए कोई ठोस नीति अभी तक नहीं बनी थी। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भारतीय भाषाओं विशेषकर मातृभाषाओं या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का माध्यम और उसके आगे यथासंभव भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है।

वर्ष 2020 में लागू की गयी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अन्य महत्वपूर्ण नीतियों के साथ ही भाषाओं विशेषकर मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। अब तक लागू की गयी तीनों ही राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को सुझाया गया है। इसके साथ ही अंग्रेजी व संस्कृत के अध्ययन पर बल दिया गया है। इससे पता चलता है कि शिक्षा नीति के द्वारा देश की भाषा नीति को भी निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं। तृतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के बारे में बाकी दोनों शिक्षा नीतियों की तुलना में बहुत अधिक विस्तार से चर्चा की गयी है। इसके अध्याय-4 और अध्याय-22 दोनों में ही शिक्षा के माध्यम के रूप में भाषा, भाषा का संरक्षण व संवर्द्धन और अनुवाद के लिए नीति निर्धारित की गयी है। अध्याय-4 में मातृभाषा और स्थानीय भाषा को प्राथमिक शिक्षा का माध्यम और आगे के लिए यथासंभव भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया जाना निर्धारित किया गया है। मातृ भाषा या स्थानीय भाषाओं में शिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा-मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। अध्याय-22 में समस्त भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्द्धन करने की बात कहते हुए शिक्षा प्रणाली में बहुभाषिकता को समय की आवश्यकता बतायी गयी है।

ग्रेड-5 तक अनिवार्य रूप से शिक्षा का माध्यम घर की भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। आगे यह भी कहा गया है कि यह बेहतर होगा कि ग्रेड-8 और उससे आगे तक भी शिक्षा का

माध्यम घर की भाषाधमातृभाषास्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा हो। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। यदि निजी स्कूल इस नीति को मानेंगे तभी इसके अपेक्षित परिणाम सामने आयेंगे। इसमें इस बात को स्पष्ट तौर पर रेखांकित किया गया है कि किसी भाषा को सीखने के लिए इसे शिक्षा का माध्यम होने की आवश्यकता नहीं है।

नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा की राष्ट्रीय स्तर पर अनिवार्यता की संस्तुति का जिस तरह से विरोध हुआ है उसे देखकर लगता है कि यह बहुत पुरानी परम्परा नहीं है और सूर्य के प्रकाश में आंख मूंदकर अंधेरे का आभास करने जैसा है। दक्षिण में हिंदी विरोध आजादी के बाद गढ़ा गया यह राजनीतिक मुद्दा है जिसकी प्रस्तावना पादरी रोबर्ट कोल्डवेल ने लिखी थी।

पादरी रोबर्ट कोल्डवेल की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए आधुनिक भाषा-ज्ञान के प्रवर्तकों ने शोधार्थि का स्वांग रचकर यह साबित कर दिया गया कि उत्तर भारत की भाषाओं का यूनानी, ईरानी, जर्मन और लातीनी भाषाओं से सम्बन्ध तो है लेकिन विध्यांचल के दक्षिण में प्रचलित “उन भाषाओं” से इनका कोई संबंध नहीं, जिसकी व्याकरणिक व्यवस्था में उत्तर से जाकर ऋषि अगस्त्य ने योगदान दिया था। दरअसल, यहीं से भाषा आधारित राजनीति शुरू हुई और पादरी कोल्डवेल फिर याद किए गए। कोल्डवेल का महिमामंडन शुरू हुआ, मरीना बीच के पास उनकी मूर्ति स्थापित हुई। दक्षिण में सक्रिय मिशनरियां इसकी प्रायोजक रहीं। देखते- देखते भाषाई आधार पर कथित “आर्य और द्रविड” के बीच दीवार मोटी और ऊंची होती गई। भारत में उत्तर और दक्षिण दो भारत हो गए, जिनके शास्त्र और संस्कृति एक ही है उनमें विभेद हो गया। उससे पहले देश में ऐसी स्थिति कहीं नहीं थी।

भारतीय नवजागरण के अग्रदूत के रूप में प्रसिद्ध, आधुनिक काल के कवि भारतेन्दु हरिश्चंद्र ने निज भाषा का महत्व बताते हुए लिखा भी

हैं कि श्रिज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटन न हिय के सूलश। इस के साथ भारत की निज भाषा से भारतेन्दु जी का तात्पर्य हिंदी सहित भारतीय भाषाओं से रहा है। वे आगे लिखते भी हैं कि अंग्रेजी पढ़के जदपि, सब गुण होत प्रवीन। पै निज भाषा ज्ञान के, रहत हीन के हीन। श्रु यानी अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में प्राप्त शिक्षा से आप प्रवीण तो हो जाओगे किंतु सांस्कृतिक एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण से हीन ही रहोगे। उसी काल में भारतेन्दु जी ने मातृभाषा में शिक्षा की अवधारणा को भी साकार करने का अनुग्रह किया है। इसी कविता में वे फिर लिखते हैं कि और एक अति लाभ यह, या में प्रगट लखात, निज भाषा में कीजिए, जो विद्या की बात। मातृभाषा से बच्चों का परिचय घर और परिवेश से ही शुरू हो जाता है। इस भाषा में बातचीत करने और चीजों को समझने-समझाने की क्षमता के साथ बच्चे विद्यालय में दाखिल होते हैं। अगर उनकी इस क्षमता का इस्तेमाल पढ़ाई के माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव करके किया जाए तो इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं।

हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं विख्यात वैज्ञानिक डॉ. अब्दुल कलाम से नागपुर के धर्मपेठ महाविद्यालय के एक कार्यक्रम में व्याख्यान के बाद एक छात्र ने प्रश्न किया कि आप सफल वैज्ञानिक कैसे बने तब डॉ. कलाम का उत्तर था कि मैंने 12वीं तक विज्ञान, गणित सहित सम्पूर्ण शिक्षा मातृभाषा तमिल में ली है। इस नीति में भी गणित, विज्ञान के पाठ्यक्रम द्विभाषा में उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। इस शिक्षा नीति में ई-लर्निंग यानी आनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने की बात है। केन्द्रीय स्तर पर भारतीय भाषाओं में सॉफ्टवेयर तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। विद्यालयीन शिक्षा के लिए ई-सामग्री सभी राज्यों के साथ-साथ एनसीईआरटी, सीआईईटी, सीबीएसई, एनआईओएस और अन्य निकायों व संस्थानों द्वारा भी सभी क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की प्रतिबद्धता दर्शायी गई है।

हिन्दी के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका



अंजली त्रिवेदी

उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

“ सागर मिलती धाराएं हिन्दी में सबका संगम है,
शब्द, नाद, लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है,
गंगा-कावेरी की धारा साथ मिलाती हिन्दी है,
पूरब-पश्चिम, कमल-पंखुड़ी सेतु बनाती हिन्दी है। ”

भाषा समाज की रचना का मुख्य आधार है और समाज की प्रगति में भाषा ही मुख्य आधार होती है, हिन्दी भारत देश को अखण्ड भारत बना कर एक सूत्र में बांधने का काम कर रही है, साथ ही अपनी सरहदों से बाहर जाकर भी अपना जश्र मनाती है विश्व के लगभग 150 से अधिक देशों में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, कोई भी भारतीय विदेशों में भारत और हिन्दी के माध्यम से जाना जाता है, और हिन्दी के लिये सेतु का काम कर रहा है हमारा सोशल मीडिया। हिंदी उच्छल जलधि तरंग की तरह अवरिल बहती ही जा रही है। नये स्वरूप, नये रंग और नए ढंग में सोशल मीडिया ने इसको नया मुकाम दे दिया है। विभिन्न जन सहभागिता के वृहद कार्य को प्रभावित करने के लिये आम जनता की भाषा में समन्वय और संप्रेषण के लिये सोशल मीडिया बहुत वृहद भूमिका अदा कर रहा है। इसके विभिन्न माध्यम जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर इंस्टाग्राम, टेलिग्राम और गूगल इत्यादि ने विश्व और भारत में हिन्दी जानने और नहीं जानने वालों के मध्य के दायरे को निश्चित रूप से कम किया है इसका जीवंत उदाहरण है, पिछले दिनों एक विदेशी अहिन्दी भाषी देश की एक महिला का हिन्दी में रील बनाना और उसका फेसबुक पर वायरल होना। इस

प्रकार के और भी कई उदाहरण होंगे जिनका सरोकार किसी न किसी रूप में आप पाठकों को भी हुआ होगा।

सोशल मीडिया ने भाषा की बाध्यता को खत्म कर दिया है। कोई भी भाषा को हिन्दी अनुवाद Google Translator से पूछिये। भारत देश में जिनकी अंग्रेजी कमजोर है, उनको तो जैसे Google Translator के रूप में संजीवनी मिल गई हो। वो प्रत्येक पत्र, प्रत्येक शब्द, का भारतीय भाषा हिन्दी में गूगल अनुवाद कर आगे बढ़ते जा रहे हैं व अंग्रेजी रूप के बैरियर को तोड़ कर हिन्दी को गति दे रहे हैं। कम्प्यूटर में यूनिकोड आने से हिन्दी को जैसे प्रवाह मिल गया हो और वो गंगा की तरह बहते बहते मानो पद्मा (गंगा को बांग्लादेश में पुकारा जाने वाला नाम) बनने को अग्रसर हो गयी हो, अर्थात् विस्तारित हो गयी हो।

सोशल मीडिया से प्राप्त बधाई सन्देश हो या कोई जरूरी सूचना, यू-ट्यूब पर हिन्दी जगत के सभी विडियो रुपी जानकारी में हिन्दी समाहित है। इसका कारण देवनागरी लिपि की बनावट कई अन्य भाषाओं की लिपि से मिलती-जुलती है शायद यही कारण है कि आजकल हिन्दी भाषा के विज्ञापनों की संख्या में तेजी से वृद्धि दिखाई देती है। आज हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, होटलों और मॉल्स में जो साइन बोर्ड्स होते हैं, वे द्विभाषी होने लगे हैं। ज्यादातर इनमें हिंदी और अंग्रेजी अथवा स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता है।

सोशल मीडिया का कोई दायरा नहीं है। यह अथाह है, इसी कारण से हिन्दी की लोकप्रियता का असर ऐसा हो रहा है कि एशिया के अधिकतर देश यथा चीन, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, जावा, आदि में श्रीराम के चरित्र पर आधारित कथाओं का मंचन किया जाता है तथा वहाँ के स्कूली पाठ्यक्रम में रामलीला का शामिल किया गया है, हिन्दी की रामकथाएं भारतीय संस्कृति का संवाहक बन चुकी हैं। यह सब सोशल मीडिया के कारण ही सम्भव हो सका है।

आज का समय तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् Artificial Intelligence (AI) का हो चला है। Chat GPT से तो हम सब वाकिफ हो गये हैं। मानव मस्तिष्क जो सोचने का काम करता है वह AI सोचकर उसका

निष्कर्ष आपके सामने रिपोर्ट के रूप में, प्रजन्टेशन के रूप में या जैसे आप चाहें उस रूप में आपको प्रस्तुत करने को तैयार हैं। आप सोचिये और देखिये कि तकनीक, जहां कम्प्यूटर में हिन्दी में टाइप करना भी कठिन समझा जाता था, वहां विश्व स्तर की Artificial Intelligence(AI) हिन्दी में कमाण्ड ले रही है और हिन्दी में उत्तर दे रही है। यह सब सोशल मीडिया के हिन्दी के प्रचार और हिन्दी के प्रति बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही सम्भव हुआ है। AI के कारण ही सही यहां मैं कहना चाहूँगी कि-

“ मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारें आरती,
समूचे विश्व में गूजें सदैव हमारी भारती । ”

हिन्दी भारत वशियों के साथ-साथ हमारे पड़ोसी मुल्को के लोगों के लिये भी विदेशी सम्पर्क की भाषा है, सोशल मीडिया को हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कितना योगदान रहा है कि इसका अंदाजा इस बात

से भी लगाया जा सकता है कि आज अमेरिका के अनेक हिन्दी सीखने वाले विद्यालयों में लोकप्रिय हिन्दी फिल्मों के गानों एवं संवादों के माध्यम से हिन्दी सिखाई जा रही है। हमारे भारत देश के एक राज्य की खूबसूरती के बारे में कहा गया है कि:-

“ गर फिरदौस बरू ए जमी अस्त,
हर्मिअस्तों हर्मिअस्तों हर्मिअस्त ”

तो इस पत्रिका के सम्माननीय पाठकों ऊपर की पंक्तियां हमारे भारत देश के किस राज्य के लिये कही गयी है। इसके लिये आप सोशल मीडिया /गूगल अनुवादक/ ऑनलाइन मित्र मण्डली/ फेसबुक /व्हाट्सअप/ ट्विटर/इंस्टाग्राम टेलिग्राम आदि किसी भी प्लेटफॉर्म से जान सकते हैं वो भी कुछ सेकेण्ड में। बाकी भारत की हिन्दी को पहचान दिलाने में अहम भूमिका अदा करने के लिए सोशल मीडिया का डोमो अरिगातो।

“ जीवन के छोटे से छोटे खेल में हिंदी अपना
दायित्व निभाने में समर्थ है।
- पुरुषोत्तमदास टंडन। ”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का योगदान



सुरेन्द्र कुमार कुमावत

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

सम्प्रेषण के लिए सबसे अच्छा माध्यम है तो वह केवल स्थानीय भाषा या मातृभाषा है। मातृभाषा में शक्ति, संस्कार और संस्कृति है। जो हमें क्षमता प्रदान करती है जिससे हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मातृभाषा संप्रेषण का सहज और सरल माध्यम है। पत्रकारिता एवं हिंदी का आंदोलन मातृभाषा में हुआ, इसलिए सफल रहा। मातृभाषा प्रेम और समन्वय को स्थापित करता है। बोलियों और मातृ भाषाओं को हिंदी को सींचने और समृद्ध करने वाला है। इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में भाषाओं के योगदान एवं विकास के लिए क्रान्ति की आवश्यकता है जिसको नयी शिक्षा नीति 2020 में शामिल किया गया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सभी भारतीय भाषाओं विशेषकर मातृभाषाओं या स्थानीय भाषाओं को प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का माध्यम और उसके आगे यथासंभव भारतीय भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की बात कही गयी है। भारतीय भाषाओं के संरक्षण के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। इस कार्य के लिए अनेक अकादमी व संस्थान भी खोले जाने की घोषणा की गयी है। इन नीति में भारत की सभी भाषाओं के साथ संतुलन बनाने की कोशिश की गयी है। इस नीति में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर के विकसित देशों में अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं में शिक्षित होना कोई बाधा नहीं है और इसका भरपूर लाभ उन्हें मिलता है, जबकि भारत में अभी भी यह बहुत मुश्किल

कार्य है। शिक्षा नीति, भारतीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, संस्कृत, मातृभाषा, स्थानीय भाषा, लुप्त प्राय भाषा।

मानव के सम्यक विकास, मन की कल्पना को मूर्त रूप प्रदान करने, स्वस्थ समाज और समृद्धिशाली व शक्तिसंपन्न राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा का महत्त्व निर्विवाद रूप से सर्वाधिक है। भारत में बहुत पुराने समय से ही शिक्षा की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। भारत की महान ज्ञान परंपरा और शिक्षा व्यवस्था ने आर्यभट्ट, वाराहमिहिर, चरक, सुश्रुत, पाणिनि, नागार्जुन, गौतम, मैत्रेयी, गार्गी जैसे अनेक महान विद्वानों को जन्म दिया है। इन विद्वानों ने अपनी भाषा में खगोल विज्ञान, गणित, चिकित्सा विज्ञान, व्याकरण, दर्शन, योग, अभियांत्रिकी, वास्तुकला, भवन निर्माण आदि में विश्व को मौलिक योगदान दिया है।

समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में बहुत क्षरण होता गया जिस देश में कभी तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे विश्वस्तरीय शिक्षा संस्थान हुआ करते थे, आज उसके विश्वविद्यालय दुनिया भर में शीर्ष 300 में स्थान बनाने के लिए संघर्षरत हैं। इसके अनेक ऐतिहासिक व राजनीतिक कारण रहे हैं। गुलाम भारत में यहाँ की गौरवशाली शिक्षा प्रणाली को नष्ट किया गया। प्राचीन शिक्षा प्रणाली नष्ट होने से ज्ञान के सभी क्षेत्रों में क्षरण होना शुरू हो गया। स्वतंत्र भारत में राष्ट्र निर्माण के लिए स्पष्ट और सुविचारित शिक्षा नीति की आवश्यकता महसूस की गयी। इसके लिए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1968 में तैयार की गयी। इस नीति में तमाम प्रावधानों के साथ ही 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा, क्षेत्रीय भाषाओं के अध्ययन पर बल, त्रिभाषा सूत्र का निर्माण, संस्कृत के अध्ययन की जरूरत प्रमुख बिंदुओं में से थे।

वर्ष 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गयी। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों, महिलाओं, अनुसूचित जातियों व जनजातियों को पढाई के लिए प्रोत्साहन, छात्रवृत्तियों में वृद्धि, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि प्रमुख बिंदुओं में से थे। अंग्रेजी व अन्य विदेशी भाषाओं के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने पर बल दिया गया था। साथ ही हिंदी को संपर्क भाषा के तौर पर विकसित

करने की आवश्यकता जताई गई थी। वर्ष 2020 में लागू की गयी नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी अन्य महत्वपूर्ण नीतियों के साथ ही भाषाओं विशेषकर मातृभाषा और स्थानीय भाषा में शिक्षा पर बहुत बल दिया गया है। अब तक लागू की गयी तीनों ही राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में शिक्षा माध्यम के रूप में मातृभाषा या स्थानीय भाषा को सुझाया गया है। इसके साथ ही अंग्रेजी व संस्कृत के अध्ययन पर बल दिया गया है। इससे पता चलता है कि शिक्षा नीति के द्वारा देश की भाषा नीति को भी निर्धारित करने के प्रयास किए गए हैं।

मातृभाषा या स्थानीय भाषाओं में शिक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेजी से सीखते हैं। शिक्षा का माध्यम घर की भाषा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि यह बेहतर होगा कि शिक्षा का माध्यम घर की भाषा मातृभाषा स्थानीय भाषा क्षेत्रीय भाषा हो। सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल इसकी अनुपालना करेंगे। यदि निजी स्कूल इस नीति को मानेंगे तभी इसके अपेक्षित परिणाम सामने आयेंगे। विषय की मूल अवधारणा अपनी भाषा में समझ में आ जाए तो उच्चतर शिक्षा में किसी भी भाषा में अध्ययन सहज हो सकता है।

संस्कृत की महत्ता के बारे में लिखा गया है कि संस्कृत का शास्त्रीय साहित्य इतना विशाल है कि सारे ग्रीक और लैटिन साहित्य को भी यदि मिलाकर इसकी तुलना की जाए तो भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता है। भाषा और संस्कृति का आपस में गहरा रिश्ता है। हमारी संस्कृति हमारी भाषाओं में निहित है। भारत में भाषा शिक्षण को बहुत गंभीरता से कभी नहीं लिया गया है। इस नीति में उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों की कमी पर चिंता जाहिर करते हुए उच्चतर योग्यता के भाषा शिक्षकों के एक बड़े कैडर को विकसित करने की जरूरत बतायी गयी है। इससे भविष्य में बहुत बड़े स्तर पर भाषा शिक्षकों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे और बहुभाषी पाठ्यक्रमों के निर्माण में बहुत मदद मिलेगी। शिक्षा का माध्यम और शिक्षा में भारतीय भाषाओं को समुचित स्थान न मिल पाने एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है।

भाषा को संरक्षित और प्रोत्साहित करने का कार्य भाषायी डिजिटलीकरण के बिना अधूरा है। इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय

शिक्षा नीति में डिजिटलीकरण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इस नीति में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि भारतीय भाषाओं और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफॉर्म, पोर्टल, विकीपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। यह कार्य व्यापक तौर पर जनभागीदारी के माध्यम से किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा, कला और संस्कृति के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति की स्थापना की बात कही गयी है। प्रोत्साहन स्वरूप भारतीय भाषाओं में रचे जानी वाली उत्कृष्ट कविता व गद्य के लिए पुरस्कार स्थापित किए जाएंगे।

भारतीय भाषाओं की उन्नति और प्रगति तभी संभव है, जब उसे प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार से जोड़ा जाएगा। भारतीय भाषाओं को रोजगार की दृष्टि से अभी भी अंग्रेजी वाला स्थान प्राप्त नहीं है। इस बात को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समझा गया है और बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को रोजगार के मानदंडों की अर्हता में शामिल किया जाएगा। भारतीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बढ़ाने में यह बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भारतीय भाषाओं के लिए भी एक नीति निर्धारित की गयी है। विविध तरीकों से भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहित, संरक्षित और संवर्धित करना इसके प्रमुख उद्देश्यों में से है। सभी महत्वपूर्ण भारतीय भाषाओं के लिए अकादमी, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, भाषा संस्थान, शास्त्रीय भाषाओं के लिए विश्वविद्यालयों में विभाग तथा पालि, प्राकृत व फारसी के लिए राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना, संस्कृत के अध्ययन का विस्तार, लुप्त प्राय भाषाओं के संरक्षण के लिए नीति, छात्रवृत्ति व पुरस्कारों की स्थापना, रोजगार के मानदंडों में भारतीय भाषाओं में प्रवीणता को अर्हता के रूप में शामिल किया है।

इसके लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है क्योंकि बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिल सकता है कहा भी गया है कि “उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः”॥ अर्थात् कोई भी काम कड़ी मेहनत के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है सिर्फ सोचने भर से कार्य नहीं होते हैं, उनके लिए प्रयत्न भी करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण नहीं आते।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



सतीश कुमार चौरे

भण्डार अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

विश्व में भारत की प्रगतिशील भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामी रही है और दुनिया को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लोकतंत्र, अर्थशास्त्र, आध्यात्मिकता, संस्कृति और वैश्विक नेतृत्व सहित विभिन्न क्षेत्रों में इसके योगदान ने दुनिया भर में शांति, समृद्धि और समझ को बढ़ावा देने में मदद की है। आज हम जानते हैं कि भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और आध्यात्मिकता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, भारत ने गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्राचीन भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई के मान की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि भारतीय खगोलशास्त्री वराहमिहिर विषुवों के अग्रगमन की घटना का वर्णन करने वाले पहले व्यक्ति थे। चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद का उपयोग हजारों वर्षों से विभिन्न रोगों और बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता रहा है।

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत ने सॉफ्टवेयर विकास, दूरसंचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारतीय आईटी उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा है और भारतीय कंपनियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन-लर्निंग और जैव प्रौद्योगिकी जैसी तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अपने योगदान के अलावा, भारत ने आध्यात्मिकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश में हिंदू धर्म,

बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म जैसी आध्यात्मिक परंपराओं का एक समृद्ध इतिहास है, जिसका दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इन आध्यात्मिक परंपराओं ने लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित किया है और दुनिया भर के लोगों के मूल्यों और विश्वासों को आकार देने में मदद की है। भारत ने विभिन्न तरीकों से दुनिया में एक प्रगतिशील भूमिका निभाई है।

भारत ने दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने वाले कुछ तरीकों में शामिल है:-

लोकतंत्र : भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस क्षेत्र के अन्य देशों के लिए एक मॉडल रहा है। भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली की समावेशिता, विविधता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए प्रशंसा की गई है।

आर्थिक विकास: भारत हाल के वर्षों में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक रहा है, और इसने प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और सेवाओं जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत के आर्थिक विकास ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की है और देश के समग्र कल्याण में योगदान दिया है।

वैश्विक मुद्दों में सक्रिय नेतृत्व : भारत वैश्विक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है और उसने जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार और निरस्त्रीकरण जैसे क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका निभाई है। भारत विकासशील देशों के अधिकारों का मुखर हिमायती भी रहा है और उसने इस क्षेत्र और दुनिया में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में काम किया है।

सांस्कृतिक विरासत : भारत की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जिसमें संगीत, नृत्य, कला, साहित्य और व्यंजन शामिल हैं। भारतीय संस्कृति को दुनिया भर के लोगों द्वारा सराहा गया है और इसने सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समझ को बढ़ावा देने में मदद की है।

आध्यात्मिकता: भारत अपनी समृद्ध आध्यात्मिक परंपराओं के लिए जाना जाता है, जिसका दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। हिंदू धर्म,

बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म कुछ ऐसी आध्यात्मिक परंपराएं हैं जो भारत में उत्पन्न हुई हैं और लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित किया है। भारत ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों में भी अग्रणी भूमिका निभाई है और वैश्विक मुद्दों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत ने वैश्विक मंच पर अपने नेतृत्व का प्रदर्शन करने के कुछ तरीकों में शामिल है:-

G-20 मंच : भारत G-20 का सदस्य है, जो दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक मंच है। भारत ने वैश्विक आर्थिक विकास, सतत विकास और वित्तीय स्थिरता की वकालत करने के लिए G-20 में अपनी स्थिति का उपयोग किया है।

जलवायु परिवर्तन : भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। भारत अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कई नवीकरणीय ऊर्जा पहलों का विकास किया है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन में सक्रिय भूमिका : भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है और इसकी स्थापना के बाद से संगठन में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत चार बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है और विकासशील देशों के अधिकारों और अंतरराष्ट्रीय शांति और

सुरक्षा के लिए एक मजबूत वकील रहा है।

परमाणु अप्रसार : भारत परमाणु अप्रसार का प्रबल पक्षधर रहा है और इस क्षेत्र में वैश्विक दक्षिण में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत भी निरस्त्रीकरण का मुखर समर्थक रहा है और उसने दुनिया भर में परमाणु हथियारों में कमी का आह्वान किया है।

मुक्त व्यापार : भारत मुक्त व्यापार का प्रबल पक्षधर रहा है और उसने अन्य देशों के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। भारत इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने में भी सक्रिय रहा है, जिसमें दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) आदि शामिल हैं।

इस तरह विश्व में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका महत्वपूर्ण और बहुआयामी रही है। जलवायु परिवर्तन, अप्रसार, व्यापार और बहुपक्षवाद जैसे क्षेत्रों में इसके योगदान ने दुनिया भर में शांति, समृद्धि और समझ को बढ़ावा देने में मदद की है। कुल मिलाकर, भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसकी प्रगतिशील भूमिका आज भी महसूस की जा रही है।

“

हिन्दी द्वारा सारे भारत को
एक सूत्र में पिरोया जा सकता है।

- स्वामी दयानंद

”

हिंदी के प्रचार-प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका



आर.एस.धोपटे

प्रेसमेन
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

जैसे की आप सभी को ज्ञात है कि हिंदी को हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा का महत्त्व मिला हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के संशोधन कर अलग-अलग समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता रहा है। ताकि लोग हिंदी को आसानी से समझें और उसका उपयोग दैनिक जीवन में कर सकें।

हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जो कि हिंदी भाषा की एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें हर ध्वनि के लिए अलग-अलग वर्ण या चिन्ह है। देश-विदेश में मीडिया और सोशल मीडिया का उपयोग तेजी से बढ़ा है। इसके फलस्वरूप हिंदी भाषा के प्रचार में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

जनसंचार के माध्यम के रूप में हिंदी का प्रयोग कोई नई बात नहीं है, परन्तु स्वतन्त्रता के बाद हिंदी भाषा का प्रयोग राजभाषा तथा कार्यात्मक हिंदी के रूप में निरन्तर विकासमान है। जनसामान्य को उपयोगी सूचनाएं एवं खबरे देने के लिए सदियों से सरकार एवं व्यापारी वर्ग इसी भाषा का प्रयोग करते हैं। आधुनिक जनसंचार के प्रमुख माध्यम आकाशवाणी, दूरदर्शन, फिल्में, समाचार-पत्र, पत्रिकाएं एवं इंटरनेट हैं। संचार के सभी माध्यमों में हिंदी ने मजबूत पकड़ बना ली है। चाहे वह हिंदी के समाचार पत्र हो, रेडियो हो, दूरदर्शन हो, हिंदी सिनेमा हो, विज्ञापन हो या ओ टी टी (ओवर द टॉप) हो सर्वत्र हिंदी छापी हुई है। संचार माध्यमों ने हिंदी के

वैश्विक रूप को गढ़ने में पर्याप्त योगदान दिया है। हिंदी के वैश्विक रूप को संचार माध्यमों में भी देखा जा सकता है। भाषाएं संस्कृति की वाहक होती हैं और संचार माध्यमों पर प्रसारित कार्यक्रमों से समाज के बदलते सच को हिंदी के बहाने ही उजागर किया गया। विदेशों में तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ आदि के सार्वजनिक मंचों पर अब भारत के राजनैतिक नेता एवं भारतीय प्रतिनिधि अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करने लगे हैं। इसी सन्दर्भ में उल्लेखनीय है कि हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस एक थीम के साथ मनाया जाता है। इस साल 2023 में विश्व हिंदी दिवस की थीम है - 'हिंदी को जनमत की भाषा बनाना, बगैर उनकी मातृभाषा के महत्त्व को भूले। विश्व में हिंदी भाषा के प्रचार - प्रसार के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इसे मनाया जाता है। इसके लिए निबंध प्रतियोगिताओं सहित कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का विवरण हिंदी में जारी करने का निर्णय लिया है। और डिजिटल दुनिया में हिंदी की मांग अंग्रेजी की तुलना में पाँच गुना ज्यादा बढ़ती जा रही है। अंग्रेजी की तुलना में हिंदी 5 गुना तेजी से बढ़ रही है। देश में जहाँ हिंदी सामग्री की डिजिटल मीडिया में खपत 94 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। और जिसके फलस्वरूप भारतीय युवाओं के स्मार्टफोन के उपयोग में औसतन 32 एप होते हैं, जिसमें 8-9 हिंदी के होते हैं। भारतीय युवा यूट्यूब पर 93 फीसद हिंदी वीडियो देखते हैं। सितम्बर 2021 में आए एक समाचार के अनुसार "कू" सामाजिक नेटवर्किंग सेवा है। जिसका स्वामित्व बेंगलूर स्थित बॉम्बीनेट टेक्नोलॉजीज के पास है। इसकी सह-स्थापना उद्यमियों अप्रमेय राधाकृष्ण और मयंक बिदावतका ने की थी। "कू" हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ माइक्रोब्लॉगिंग साइट बन गया है। "कू" एक (माइक्रो-ब्लॉगिंग) प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग विभिन्न विषयों पर अपना मत प्रकट करने के लिए किया जा सकता है।

हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है; यह ज्यादातर भारत की जनसंख्या द्वारा बोली जाती है जबकि शेष जनसंख्या अपने आप में सहज है। क्षेत्रीय भाषा चाहे वे किसी भी राज्य से हों। क्षेत्रीय भाषा के लिए अच्छा है सामान्य एक व्यक्ति से व्यक्ति संचार भाषा का प्रयोग

हिन्दी भाषा के माध्यम के रूप में किया जाता है। वही फेस बुक, व्हाट्सअप, ट्यूटर, इंस्टाग्राम, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पोटोकास्ट, ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की तरह, अमेज़न प्राइम, पत्रिका हो या सिनेमा आदि में हिंदी का प्रयोग बढ़ा है।

पहले के समय में केवल दो प्रकार के मीडिया फेस थे, जैसे की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी के दौर में इंटरनेट के उपयोग में वृद्धि हुई है जिसके फलस्वरूप सामान्य जन ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया द्वारा हर व्यक्ति अपने शब्दों एवं विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है और साथ ही व्हाट्सअप के उपयोग से एक से अधिक यूजर के समूह बनाकर उसमें विभिन्न प्रकार की वार्ता अपने हिंदी भाषा की विभिन्न रचना के व्हाट्सअप के विभिन्न समूहों में भेज सकते हैं और साथ ही यूट्यूब भी एक ऐसा माध्यम है जो देश-विदेश तक फैला है, और फेसबुक के माध्यम से हिंदी के प्रचार - प्रसार को गति प्राप्त हुई है। और लेखक, कवि, साहित्यकार, सम्पादक और प्रकाशक इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

हिन्दी भाषा को ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में भाषा परिवर्तन के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रारंभ में यह था अमेज़न, जिसने लगभग 100 मिलियन को संबोधित करते हुए हिंदी भाषा में शॉपिंग ऐप ग्राहकों के लिए लॉन्च किया, उसके बाद अन्य ऑनलाइन शॉपिंग ऐप जैसे फ्लिप कार्ट, जबांग और अमेज़न का नंबर आता है। अमेज़न ने अपना विस्तार करने के लिए 4 सितंबर 2018 को अपना हिंदी भाषा का शॉपिंग ऐप लॉन्च किया है। और भारत में महानगरीय शहरों से परे ग्राहकों के लिए। अमेज़न पहला ऑनलाइन शॉपिंग ऐप था। भारत में ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में भाषा की बाधा को तोड़कर। स्नेप डील ने स्थानीय भाषा पेश की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और संगीत सीडी, और कई अन्य उत्पाद और सेवाएं ऑनलाइन की है। सोशल मीडिया मिश्रित संस्कृति हिंदी भाषा का उपयोग सोशल मीडिया अनुप्रयोगों जैसे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आदि में दिया है। हमें हिंदी भाषा में लिखी गई कई पोस्ट और लोग भी मिल सकते हैं।

हिंदी से संबंधित अपने संदेशों को संप्रेषित करने के लिए अंग्रेजी फोंट का उपयोग बढ़ रहा है। वॉयस असिस्टेंट गूगल सहायक एलेक्सा को

अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपयोगकर्ता क्वेरी पर कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को बातचीत करने के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी साझा करने और वेब सामग्री बनाने की अनुमति देते हैं। सोशल मीडिया के कई रूप हैं, जिनमें ब्लॉग, माइक्रो-ब्लॉग, विकी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फोटो-शेयरिंग साइट्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, वीडियो-शेयरिंग साइट्स, पॉडकास्ट, विजेट्स, वर्चुअल वर्ल्ड और बहुत कुछ शामिल हैं।

आइए हम जानते हैं हिंदी भाषा के इस्तेमाल से कुछ सोशल मीडिया के फायदे:

(i) सोशल मीडिया शिक्षा में मदद करता है:- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग तकनीकी तरीके से असाइनमेंट या प्रोजेक्ट को पूरा करने की रणनीति के रूप में किया जा सकता है। और उन्हें ऑनलाइन शिक्षा, इंटरैक्टिव तरीके से सीखने की क्षमता प्रदान करती हैं।

(ii) शैक्षिक उद्देश्यों के लिए उपयोगी :- सोशल मीडिया आपको बड़े दर्शकों तक पहुंचने और अपना ब्रांड बनाने और हिंदी के प्रचार प्रसार करने की अनुमति देता है। आप इस ऑडियंस के साथ प्रासंगिक जानकारी या सामग्री साझा कर सकते हैं, जो तब मददगार होता है जब आप चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पर आपका अनुसरण करें। यह आपके व्यवसाय या उत्पाद को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है, जिससे आपको बिक्री बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(iii) नए लोगों से जुड़ें :- जब आप सोशल मीडिया में हिंदी का उपयोग करते हैं, तो आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो आपकी रुचियों और मूल्यों को साझा करते हैं। यह संबंध बनाने में मदद कर सकता है। जिससे आगे चलकर व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं।

(iv) उपयोग करने के लिए निःशुल्क :- सोशल मीडिया फ्री है! जब तक आपके पास किसी प्रदाता (जैसे फेसबुक) के साथ एक स्थापित खाता है, तब तक कोई शुल्क या सदस्यता शामिल नहीं है। यदि नहीं, तो कुछ लागतें आरंभ करने या इसे बनाए रखने से जुड़ी हो सकती हैं, मैनेजमेंट ने कहा है, “चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो या व्हाट्सअप हो, मैं संवाद करने के लिए अक्सर हिंदी का इस्तेमाल करता

हैं। अपनी भावनाओं को अपनी भाषा में व्यक्त करना न केवल सुविधाजनक है बल्कि आजकल इसे कूल भी माना जाता है।

(v) हिंदी के प्रचार में सोशल मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान :- सोशल मीडिया ने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दुनियाभर में भारतीय फिल्मों टेलीविजन कार्यक्रम देखे जाते हैं। इससे भी दुनिया में हिंदी का प्रचार-प्रसार हुआ है। सोशल मीडिया, इंटरनेट मोबाईल के कारण युवा पीढ़ी इस भाषा का सबसे अधिक प्रयोग कर रही है।

(vi) हिंदी के विकास में इंटरनेट की महत्वपूर्ण योगदान :- हमारे भारत देश में 15 अगस्त 1995 में इंटरनेट शुरू किया गया था। इस 20-22 वर्षों के कालखंड में इंटरनेट के कारण विभिन्न वेबसाइट्स,

ब्लॉग्स, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से अधिकांश जनसमुदाय तक हिंदी भाषा को पहुंचाने का कार्य हो रहा है। इंटरनेट पर अब हर दिन हिंदी के प्रचार एवं प्रसार की गति तेज हो रही है। और साथ ही खेल जगत का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी भाषा में रनिंग कमेंट्री प्रसारित किया जाता है। इस प्रकार हिंदी भाषा का सोशल मीडिया का प्रचार-प्रसार सबसे रोचक तथ्य हैं। कि सोशल मीडिया के लिए अंग्रेजी भाषा को तर्कसंगत माना जाता है, परंतु हिंदी में बिना किसी व्यवधान के इस विदेशी आई टी टूल पर बहुत प्रभावशाली रूप से अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया है। इस प्रकार सोशल मीडिया हिंदी की प्रचार-प्रसार की प्रगति में एक पर्याय बन गया है।

“

समस्त आर्यावर्त या ठेठ हिंदुस्तान की राष्ट्र तथा
शिष्ट भाषा हिन्दी या हिन्दुस्तानी है।

-सर जार्ज ग्रियर्सन

”

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं का योगदान



राहुल कौशिक

उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को नये और सुधारित मानकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास है। इस नीति में भारतीय भाषाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है जो देश की पहचान, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बनाने में मदद करता है। भारत एक विविध देश है जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा तमिल, तेलगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम जैसी भारतीय भाषाएं भी मौजूद हैं। ये भाषाएं हमारी पहचान को मजबूत करती हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण विषय के रूप में मान्यता दी गई है। इससे छात्रों को वो लाभ प्राप्त होते हैं जो अपनी मातृभाषा में पढ़ाई करना चाहते हैं। इससे उन्हें अपनी भाषा को मान्यता प्राप्त होती है और अपनी भाषा में स्वतंत्र रूप से सोचने और व्यक्त करने का अवसर मिलता है। इससे छात्रों की भाषा क्षमता और भाषा संचार कौशल विकसित होते हैं। इसके साथ ही, छात्रों की संवेदनशीलता, सांस्कृतिक ज्ञान और भारतीय समाज में एकता की भावना भी विकसित होती है। भाषा एक समाज की पहचान होती है और इसका अध्ययन छात्रों को अपनी संस्कृति के प्रति गहरी समझ प्रदान करता है। भारतीय भाषाओं का योगदान शिक्षा प्रक्रिया में सामूहिक सहभागिता और विद्यार्थियों की समर्पण क्षमता को बढ़ावा देता है।

भारतीय भाषाओं का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अत्यंत

महत्वपूर्ण है। इससे छात्रों को उनकी मातृभाषा का महत्व समझने, संरक्षण करने और संवृद्धि करने का संकेत मिलता है। इससे हमारी संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान को आगे बढ़ाने का कार्य होता है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी भाषाओं का सम्मान और समर्थन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूर्ण रूप से सम्पन्न करें, जिससे हमारे देश के सभी छात्र और नागरिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को नए और सुधारित मानकों तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। इस नीति में भारतीय भाषाओं का महत्वपूर्ण योगदान है, जो हमारे देश की भूमिका, संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं।

भारत एक अद्वितीय और विविध देश है जहां कई भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा, तमिल, तेलगु, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया, कन्नड़, मलयालम जैसी अनेक भाषाएं मौजूद हैं। यह भाषाएं हमारे समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को प्रमुखता प्रदान करती हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण विषय के रूप में आदर्श बनाया गया है। यह छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने का मौका देती है। इससे उन्हें अपनी भाषा को प्राप्ति मिलती है और वे स्वतंत्रता से विचार करने और भाषा का उपयोग करके व्यक्ति करने का क्षमता प्राप्त करते हैं। इससे छात्रों की भाषा क्षमता और भाषा गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है।

इसके साथ ही, भारतीय भाषाओं के प्रयोग से छात्रों की अवधारणा शक्ति, ज्ञान और सांस्कृतिक संवेदनशीलता विकसित होती है। भाषा एक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका अध्ययन छात्रों को अपनी संस्कृति के प्रति गहरी समझ प्रदान करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण दिया जाना छात्रों को उनके शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे लाभ प्रदान करता है।

भारतीय भाषाओं का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण पहलू है। इससे छात्रों को भाषाई और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव होता है, जो उनके मनोविज्ञानिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, यह भारतीय समाज

को उनकी भाषाओं के प्रति संवेदनशील बनाने में मदद करता है और राष्ट्रीय एकता और समरसता को मजबूती मिलाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं के संगठन को प्रोत्साहित करती है और भाषा संबंधी कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का समर्थन करती है। इससे छात्रों के बीच सहभागिता और सामरिकता की भावना विकसित होती है, जो उनके बीच एकांतरित होने और सहयोग करने का माध्यम बनती है। भारतीय भाषाओं का प्रयोग शिक्षा संस्थानों के विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों में संभव होता है, जिससे विद्यार्थियों का एकांतरण और संयोजन होता है। इससे छात्रों को समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक अनुभव मिलता है

और उनकी अभिव्यक्ति क्षमता और संवाद कौशल विकसित होते हैं। समाप्ति के रूप में, भारतीय भाषाओं का योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमारे देश की भाषाओं की महत्ता को समझने, संरक्षण करने और समृद्ध करने का संकेत मिलता है। इससे हमारी संस्कृति, ऐतिहासिक परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ियों तक ले जाने का कार्य होता है। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपनी भाषाओं का सम्मान और समर्थन करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से सम्पन्न करें, जिससे हमारे देश के सभी छात्र और नागरिकों का संघर्ष सहजता से संभव हो सके।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



श्री तय्यब हुसैन

आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर

भारत को कूटनीति में एक के बाद एक सफलता मिल रही है उससे भारतीय राजनय का सशक्त पहलु सामने आया है। यूक्रेन-रूस युद्ध को लेकर भारत ने जो स्टैंड लिया है उसे लेकर अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों को भी अपना रुख नरम करना पड़ा है। अब ब्रिटेन ने भी रूस को लेकर भारत के स्टैंड को स्वीकार करने के संकेत दे दिए हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बातचीत हुई। सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई थी कि रूस को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोई दबाव बनाएंगे या नहीं? यह भी काफी सुखद रहा है कि बोरिस जॉनसन ने रूस-यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें भारत के रुख से अवगत कराया।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने शांति का पक्ष लिया है और हम चाहते हैं कि इस बारे में बातचीत और कूटनीति के जरिये आगे बढ़ा जाना चाहिए और संघर्ष जल्द समाप्त होना चाहिए। नरेन्द्र मोदी और बोरिस जॉनसन के संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में भी दोनों ने कहा कि हम यूक्रेन में तुरन्त युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति पर बल देते हैं। भारत-ब्रिटेन सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। कोई समय था जब अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ अन्य देश पाकिस्तान के पाले में खड़े दिखाई देते थे।

भारत ऊँची आवाज में बार-बार कहता रहा कि आतंकवाद की खेती

करने वाले पाकिस्तान को मदद मत करें लेकिन अमेरिका पाकिस्तान पर डालरों की वर्षा करता रहा। पाकिस्तान कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक के आतंकवाद को सींचता रहा। अंततः दुनिया को पाकिस्तान की असलियत का पता चला और अब वह अलग-थलग पड़ा हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। मोदी सरकार से पूर्व की सरकारों की तरह कोई नीतिगत अपंगता नहीं है। भारत आज अपने फैसले लेने में सक्षम है। अमेरिका, ब्रिटेन हो या फिर कोई दूसरा देश कोई भी भारत के रूस से संबंधों पर अंगुली नहीं उठा सकता।

भारत आज इन देशों से आँख से आँख मिलाकर बात करता है, आँख झुका कर नहीं। ब्रिटेन ने भी रूस से भारत के ईंधन और ऊर्जा खरीदने को लेकर कोई दबाव नहीं बनाया। रूस-यूक्रेन युद्ध मसले से अलग हटकर भारत और ब्रिटेन ने रिश्तों को नया आयाम देने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है। दोनों देश रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में मजबूत गठजोड़ बनाने पर सहमत हुए हैं। दोनों देश मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और इस वर्ष के अंत तक मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने पर भी सहमति हुई है। ब्रिटेन के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और भारत भी रक्षा क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटेन सहित कई देशों से सामान खरीदता है। वैसे भी यूरोपीय संघ से अलग हो जाने के बाद ब्रिटेन के लिए भारत का महत्व काफी ज्यादा बढ़ गया है। एक लाख से ज्यादा भारतीय छात्र वहाँ विभिन्न शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे हैं। भारतीय मूल के लोग वहाँ वित्त मंत्री और गृहमंत्री जैसे पदों पर हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारतीय पेशेवरों खासतौर पर आईटी पेशेवरों के लिए वीजा देने की नीति को और उदार बनाने के संकेत दिए हैं। इससे भारतीयों को काफी फायदा होगा। ब्रिटेन भी भारत से कई तरह का सामान आयात करता है। दोनों देशों ने जहाँ व्यापार को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि पारम्परिक आर्थिक और कारोबारी हित ही दोनों देशों के रिश्तों को नई ऊँचाई तक पहुँचाएंगे।

दूसरी तरफ भारत की सुरक्षा चुनौतियाँ भी कुछ कम नहीं हैं। ऐसे में

ब्रिटेन का हिन्द प्रशांत महासागरीय पहल से जुड़ने का फैसला भारत के हित में ही है। दोनों देश बदली हुई दुनिया में अपने द्विपक्षीय रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बोरिस जॉनसन इन दिनों घरेलू मोर्चे पर काफी घिरे हुए हैं। ब्रिटेन के राजनीतिज्ञ महसूस करते हैं कि पिछले दशकों में भारत की ताकत कम आंक कर ब्रिटेन की सरकारों ने काफी गलती की है। जॉनसन चाहते हैं कि भारत के साथ सहयोग का कोई बड़ा फैसला हो जाए जिसे वह घरेलू मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर दिखा सके। उनके लिए प्राथमिकता रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं है बल्कि उनके लिए

प्राथमिकता इस समय द्विपक्षीय रिश्ते हैं। इसीलिए ब्रिटेन ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश बढ़ाने की बात भी की है। कूटनीतिज्ञ भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि विश्व की राजनीति में भारत का महत्व काफी बढ़ गया है और शीत युद्ध के दौर वाली बातें अब अर्थहीन हो चुकी हैं। भारत के बढ़े हुए महत्व को अब कोई भी नजरंदाज नहीं कर सकता। रूस-यूक्रेन युद्ध पर दोनों देशों में मतभेद होते हुए भी जॉनसन रूस से भारतीय संबंधों को अच्छी तरह से समझते हैं इसलिए उन्होंने भारत के शांति के पक्ष को समर्थन किया है।

“ राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की
शीघ्र उन्नति के लिये आवश्यक है।

- महात्मा गांधी।

हिन्दी के प्रचार प्रसार में मीडिया की भूमिका



डेनियल रायमन

सहायक
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

मीडिया की भूमिका हिंदी के प्रचार प्रसार में हिंदी एक महत्वपूर्ण भाषा है, जो भारत के अधिकांश लोगों की मातृभाषा है। इसके प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन मीडिया भी है। विश्वास कीजिए या ना, मीडिया आजकल हमारे जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका है। यह आपसी संवाद को स्थायीकरण करने, जागरूकता फैलाने और लोगों को विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम हिंदी मीडिया की भूमिका के बारे में स्वयं के आलेख में विस्तृत जानकारी लिख रहा हूँ, हिंदी मीडिया के प्रकार आम तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला प्रिंट मीडिया- यह मीडिया लोगों को लिखित रूप में समाचार, विचार और जानकारी प्रदान करता है। इसमें अखबार, पत्रिकाएं, और जैसे प्रकारों के आउटलेट्स शामिल होते हैं, जो हिंदी भाषा में उपलब्ध होते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया- इसमें टीवी चैनल, रेडियो स्टेशन, वेबसाइट्स, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल होते हैं, जो विभिन्न विषयों पर हिंदी भाषा में समाचार और जानकारी प्रसारित करते हैं। तीसरा डिजिटल मीडिया- यह इंटरनेट पर हिंदी भाषा में सामाजिक मंच, ब्लॉग, वीडियो पोर्टल्स और डिजिटल खबर पत्रिकाओं को शामिल करता है। हिंदी मीडिया का महत्व विभिन्न क्षेत्रों में होता है। यह जनता को समाचार, विचार, और जानकारी प्रदान करके उन्हें समय रहते जागरूक बनाता है। हिंदी भाषा अपने विविधता और समृद्धि के कारण भारत में विभिन्न

क्षेत्रों में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसलिए, हिंदी मीडिया का माध्यम होने से भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों तक जानकारी पहुँचती है और उन्हें समझने में मदद करती है। हिंदी मीडिया के द्वारा समाजिक मुद्दों, राजनीतिक घटनाओं, आर्थिक विकास, खेल-कूद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। इससे लोगों को अपने आस-पास के दुनिया के मामलों के बारे में जागरूकता होती है और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा मिलती है। हिंदी मीडिया की चुनौतियों की बात करे, तो हिंदी मीडिया को भारतीय समाज के विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यहां कुछ मुख्य चुनौतियां जो मेरे हिसाब से हो सकती हैं। हिंदी एक संस्कृतिक भाषा है और इसके लिए शब्दावली और विविधता का महत्वपूर्ण स्तर है। हिंदी मीडिया को भाषा की संस्कृति को समझने, समर्थन करने, और उसे सुरक्षित रखने का भी ध्यान रखना होता है। भारत एक विविधता से भरा भी देश है और इसके भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भाषा और संस्कृति में अंतर होता है। हिंदी मीडिया को इस विविधता के साथ संवाद करने के लिए अपने संवेदनशीलता का उपयोग करना पड़ता है। इंटरनेट और डिजिटल तकनीक के साथ, हिंदी मीडिया को भी तकनीकी विकास के साथ कदम मिलाना होता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जानकारी प्रसारित करने के लिए उच्च गुणवत्ता के सामग्री बनाने में भी इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज को समय रहते जागरूक करने, विभिन्न विषयों पर जानकारी प्रदान करने, और समाज के उत्थान में योगदान देने में। हिंदी मीडिया को इसके विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि यह आगे बढ़कर भारतीय समाज को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सके।

हिंदी, भारतीय भाषाओं में से एक है जो देश की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त करती है। हिंदी भाषा की उपयोगिता और महत्व को माध्यम द्वारा प्रचारित किया जाना चाहिए, ताकि इसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ाया जा सके। मीडिया एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हिंदी भाषा को दर्शकों तक पहुंचाया जा सकता है। इस विषय में हम मीडिया की भूमिका पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि

हिंदी के प्रचार प्रसार में मीडिया कैसे मदद कर सकता है।

मूल भूमिका: मीडिया एक सक्रिय विज्ञापन माध्यम है जो लोगों को जागरूक करने, समाचार प्रसारित करने और मतभेदों को प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में मीडिया एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह दर्शकों तक हिंदी की अद्यतन और सुधार की सूचना पहुंचाता है। मीडिया कई रूपों में मौजूद होता है जैसे अखबार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि। ये रूप व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों स्तरों पर हिंदी के प्रचार प्रसार में मदद करते हैं।

अखबार: अखबार हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रदान करते हैं और उन्हें विशेष रूप से हिंदी भाषा में सूचित करते हैं। इसके साथ ही अखबारों में कविताएं, कहानियाँ, लेख भी प्रकाशित की जाती हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देती हैं।

टेलीविजन: टेलीविजन एक शक्तिशाली माध्यम है जो हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को विविध टीवी शो, समाचार, चलचित्र, कार्यक्रम आदि के माध्यम से हिंदी भाषा का आनंद लेने की सुविधा प्रदान करता है। टेलीविजन के जरिए भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय एकता, राजनीति, खेल आदि के विषय में जानकारी

भी प्रसारित की जाती है और भाषा के विकास में मदद करते हैं।

रेडियो: रेडियो भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में एक महत्वपूर्ण साधन है। विभिन्न रेडियो चैनल और कार्यक्रम हिंदी के बोलचाल को प्रोत्साहित करते हैं। यह गांवों और दूरदराज इलाकों में भी पहुंच प्रदान करता है और हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में मदद करता है।

इंटरनेट और सोशल मीडिया: आधुनिक समय में इंटरनेट और सोशल मीडिया भी हिंदी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोग इंटरनेट के माध्यम से हिंदी न्यूज़, लेख, ब्लॉग, वेबसाइट आदि को पढ़ सकते हैं और सोशल मीडिया के जरिए हिंदी को वायरल कर सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति आदि को प्रचारित किया जा सकता है और भाषा के विकास में मदद की जा सकती है।

मीडिया की भूमिका हिंदी के प्रचार प्रसार में कायम है और यह भाषा को विभिन्न स्तरों पर प्रोत्साहित करता है। अखबार, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से हिंदी को प्रसारित करने से लोग हिंदी भाषा में जुड़ते हैं और इसका भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए, मीडिया को जागरूकता और संवेदनशीलता के साथ भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना चाहिए ताकि हिंदी भाषा का उत्थान हो सके।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



शशांक जैन

एकाउंटेंट

वेतन एवं लेखा कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

“अरुण गगन की महाप्रगति पर, अब फिर मंगलगान हुआ।

करवट बढ़ती अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा ॥”

उपर्युक्त पंक्तियां अनायास ही मेरे मन में आ जाती हैं जब मैं वर्तमान में भारत की बढ़ती भूमिका के बारे में सोचता हूँ। एक ऐसा देश जो कुछ समय पहले तक अमेरिकी गेहूँ पर निर्भर था, आज अपने उगाए गए अन्न से न केवल अपना पेट भर रहा है वरन् अन्य देशों की भी सहायता कर रहा है। हमारे इतिहास का एक वो दौर था जब हमें अपना खर्चा चलाने के लिए अपना सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था इसके विपरीत आज हम कई बिलियन डॉलर की सहायता राशि अनेक देशों व संस्थाओं को दे रहे हैं। ये सभी विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका के द्योतक हैं। आज भारत को तीसरी दुनिया का देश नहीं समझा जाता जो केवल सहायता पर निर्भर हो अपितु विश्व के बड़े व महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए भारत की आवाज को बखूबी सुना जाता है। अभी हाल के कुछ घटनाक्रम विश्व में भारत की बढ़ती भूमिका के संकेतक सिद्ध हुए हैं :-

कोरोना महामारी और भारत की वैक्सिन मैत्री - विगत कुछ वर्षों में विश्व भर में कोरोना महामारी ने विध्वंसक तबाही मचाई। ऐसे में जहां विकसित देश एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे थे तब भारत ने आपसी राजनीति और विद्वेष को पीछे छोड़ मुक्त-हस्त होकर सहायता की। भारत ने 98 देशों को टीके की 235 मिलियन खुराक दी। भूटान, मालदीव, श्रीलंका आदि देश भारत की वैक्सिन

के प्रथम लाभार्थियों में से थे। अक्टूबर, 2022 में अपनी भारत यात्रा के दौरान यूएन सेक्रेट्री जनरल एंटोनियो गुटेरस ने कहा, “कोविड-19 महामारी के चरम पर दवाओं, उपकरणों और टीकों के भारत के दान से लेकर अफगानिस्तान और श्रीलंका को मानवीय और वित्तीय सहायता ने भारत का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ाया है। भारत आज संयुक्त राष्ट्र का पसंदीदा भागीदार है।”

विश्व शांति में भारत का बढ़ता वर्चस्व – भारत विश्व में शांति व सद्भाव अग्रदूत बनकर उभरा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों के लिए सैन्य और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा प्रदाता है, जिसमें पहली महिला टुकड़ी की नियुक्ति भी शामिल है। 1948 के बाद से 49 शांति मिशन में भाग लेकर भारत ने दुनिया में शांति के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव ही है कि आज यूएन, अमेरिका और यूक्रेन जैसे देश रूस-यूक्रेन युद्ध के समय भारत को मध्यस्थ की भूमिका के रूप में देख रहे हैं। सद्भाव भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रूस और यूक्रेन दोनों से युद्ध की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करना तथा ‘यह युद्ध का दौर नहीं है’ जैसे व्यक्तव्य देना भारत के विश्व पटल पर बढ़ते प्रभाव को बता रहा है।

विभिन्न वैश्विक मंचों पर भारत का उभरता हुआ स्थान- हाल ही के वर्षों में भारत को कई वैश्विक निकायों की अध्यक्षता करने का मौका मिला। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने 16 नवंबर 2022 को जी-20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से भारत को सौंप दी, यह पहली बार है जब 200 से ज्यादा जी-20 की बैठकों का आयोजन भारत में होगा। भारत को सितंबर 2022 में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता भी सौंपी गई, इसके अतिरिक्त दिसंबर 2022 में भारत को यूएनएससी का अध्यक्ष बनने का मौका मिला। साल 2022 में ही भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दो दिवसीय आतंकवाद विरोधी बैठक की मेजबानी करने का गौरव मिला। इसके अतिरिक्त जी-7 व इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) द्वारा भारत को सदस्य न होते हुए भी आमंत्रित किया गया जो भारत के बढ़ते हुए वैश्विक प्रभाव को बताता है। ऐसा ही उदाहरण तब देखने को मिला जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के चुनाव के लिए भारत के उम्मीदवार के विरुद्ध युनाइटेड किंगडम ने अपने उम्मीदवार को नहीं उतारने का फैसला किया।

मजबूत आर्थिक भविष्य व सामरिक महत्ता- उदारीकरण की शुरुआत बाद भारत के द्वार विश्व के लिए खोल दिए गए। वर्तमान परिदृश्य में भारत वैश्विक कंपनियों के लिए एक बड़ा बाजार है जहां वे अपना सामान बेच कर लाभान्वित होना चाहते हैं वहीं दूसरी ओर कोरोना संकट के बाद जिस तरह चीन के कारण विश्व की आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई उससे सबक लेते हुए बड़े वैश्विक निर्माता भारत में एक विकल्प तलाश रहे हैं। सस्ती मजदूरी, उत्कृष्ट प्रतिभा, निरंतर सरल होते नियम तथा वैश्विक निवेश को सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन ने इस क्षेत्र में उत्प्रेरक का काम किया है।

भारत के बढ़ते प्रभाव के कारण आज अमेरिका, चीन के विकल्प के रूप में भारत को देखता है और एक शांत हिन्द-प्रशान्त क्षेत्र के लिए भारत के साथ भागीदार का इच्छुक है वहीं दूसरी ओर भारत रूस के कच्चे तेल का प्रमुख ग्राहक तथा महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। भारत की प्रगतिशील सांस्कृतिक पहचान - भारत ने विगत के वर्षों में अपने अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरों को विश्व के सामने रखा है। विश्व के सामने भारत एक विविधतापूर्ण देश है जहां विभिन्न जातियां,

समुदाय के लोग शांतिपूर्वक रहते हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का निर्माण करते हैं। आज भारत के आह्वान पर पूरा विश्व 21 जून को योग करता है। भारत के आह्वान पर ही संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज के लिए समर्पित वर्ष के रूप में घोषित किया है। भारत 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की विचारधारा वाला देश है जो सभी से भाईचारे की भावना रखता है। स्वागत के दौरान पापुआ-न्यू-गिनी के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी के चरण-स्पर्श करना विश्व पटल पर भारत के प्रभाव की व्याख्या करता है।

अप्रैल, 2023 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत को विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश घोषित किया गया। इस मानव संसाधन रूपी पूंजी का यदि सही उपयोग किया गया तो निश्चित ही भारत विश्व का सिरमौर बन सकता है। हमारी 65% आबादी युवाओं की है। आज गूगल, एडोबे, आईबीएम जैसी कंपनियों के प्रमुख भारत से हैं। अभी हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष श्री अजय बग्गा को चुना गया है, जो एक भारतीय हैं। वर्तमान में विश्व उत्सुकतापूर्वक भारत की ओर देख रहा है और हमारी आगामी पीढ़ी निश्चय ही विश्व फलक पर छाने को तैयार है।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



आकाश मित्रवार

वरिष्ठ तकनीकी सहायक, खनन
भारतीय खान ब्यूरो, जबलपुर

स्वतंत्रता भारत की शान है, लोकतंत्र इसकी आन है”, भारत, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश है जिसमें लोगों को स्वतंत्रता के साथ अपने देश के निर्माण में सहयोग करने का अवसर मिलता है। भारत विश्व में एक शक्तिशाली और समृद्ध लोकतंत्र के रूप में अपनी पहचान बनाये हुए है जो नागरिकों को सशक्त बनाने में सहायता करता है और विश्व में भारत को एक बड़ी संख्या में उच्च मान्यता देता है। भारत के लोकतंत्र विश्व भर के अनेक देशों को प्रेरित कर रहा है और उन्हें अपने देश में लोकतंत्र के मूल्य जैसे लोकतंत्री विचारधारा, सामाजिक समानता को अपनाने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित होने के कारण उसके लोकतंत्र के सफलता और विकास के कारण निकटवर्ती राष्ट्र भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रेरित होकर वे भी अपने क्षेत्र में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। भारतीय समाज विविधता का सम्मान करता है और विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और जातियों को संरक्षित रखता है। इस अनुभव से प्रेरित होकर अनेक देश भी अपने समाज में विभिन्नता को समर्थन देते हैं और संरक्षित रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका इसका एक मुख्य उदाहरण है भी है की भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी कर रहा है। G20 विश्व के अर्थव्यवस्थाओं के 20 महत्वपूर्ण देशों का समूह है,

जो ग्लोबल आर्थिक मुद्दों को समझाने, समस्याओं का समाधान करने और वैश्विक आर्थिक सहयोग को समर्थन करने के लिए एकत्र होते हैं। यह पहला ऐसा मौका है जब G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में और दक्षिण एशिया में हो रहा है। भारत, G20 अध्यक्ष के तौर पर बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित करेगा।

भारत एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है जो अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक सार्थक भूमिका निभाता है। भारत विश्व में एक बड़ी राजनीतिक बदलाव का केंद्र बन गया है। इसकी बड़ी आबादी और भौगोलिक स्थिति के कारण यह विश्व की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक खिलाड़ी है। रूस और यूक्रेन के बिच चल रहे संघर्ष को कम करने में भी भारत अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। भारत रूस और यूक्रेन के साथ पुराने संबंधों का द्विपक्षीय नया संपर्क बनाने का प्रयास कर रहा है। इससे रूस-यूक्रेन युद्ध में तनाव कम हो सकता है और संघर्ष का समाधान संभव हो सकता है। भारत ने रूस-यूक्रेन युद्ध को कम करने में एक वैश्विक नेता के रूप में अपना योगदान दिया है। भारत के संबंधों को सुदृढ़ करके यह दोनों देश एक अधिक सौहार्दपूर्ण और विकासशील दिशा में अग्रसर हो सकते हैं और रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद कर सकते हैं।

भारत ने 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की है जिसे विश्वभर में धूमधाम से मनाया जाता है। भारत ने योग को विश्वभर में प्रचारित और प्रसारित करने के लिए विभिन्न पहल किए हैं। विश्वभर में योग संस्थानों, गुरुकुलों और शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई है जो योग शिक्षा को लोगों के पास पहुंचाती है। भारत योग शिक्षकों को विभिन्न देशों में प्रशिक्षित करने के लिए योग संस्थानों और अधिकृत संगठनों के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

भारत विज्ञान और तकनीक में भी अग्रणी देशों में से एक है। यहां अनेक वैज्ञानिक, चिकित्सा और अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रशंसा प्राप्त करते हैं। चंद्रयान प्रोग्राम ने भारत को

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहचान दिलाई है। इससे भारत के लोगों में राष्ट्रीय गर्व एवं सम्मान की भावना उत्पन्न होती है।

हिंदी एक व्यापक भाषा है जिसे दुनिया भर में लाखों लोग बोलते हैं। यह भारत की राजभाषा है और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, जिससे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका साबित होती है। इसके माध्यम से भारत की भाषा और संस्कृति विश्व के लोगों तक पहुंचती है। विदेशों में हिंदी का प्रचार-प्रसार: हिंदी के बढ़ते हुए प्रचार-प्रसार के कारण, विदेशों में भी हिंदी के प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। यह भाषा विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी अध्ययन की जा रही है। हिंदी विश्व में विश्वस्तरीय भाषा के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है और इसका प्रचार-प्रसार भारतीय संस्कृति, विरासत और धार्मिकता को विश्व में प्रदर्शित करता है।

वैश्विक शांति कायम रखने में भारत की भूमिका रही है। भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति सेना में एक प्रमुख और सक्रिय सदस्य राष्ट्र है, जो विश्वभर में शांति और सुरक्षा की रक्षा करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में अपनी सशक्त और समर्पित शक्तियों को दिखाया है और इसके माध्यम से विश्व में शांति और सुरक्षा के संरक्षण में मदद करता है। भारत विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में अपने फौजियों को भेजकर विश्व के समग्र विकास में सहयोग करता है। यह शांति मिशन

विभिन्न देशों में संघर्षों को रोकने और शांति का संरक्षण करने में मदद करते हैं।

भारत एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और विज्ञानात्मक देश है जो विभिन्न क्षेत्रों में विश्व के लिए विश्वगुरु बनने का संकल्प रखता है। "विश्वगुरु" शब्द भारत के उच्चतम मूल्यों और ज्ञान की प्रतिष्ठा को दर्शाता है। भारत धार्मिकता का एक विश्वव्यापी केंद्र रहा है और विभिन्न धार्मिक संप्रदायों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। इसके माध्यम से भारत विश्वभर में धार्मिक सम्प्रदायों के बीच समझदारी और सद्भावना को बढ़ाता है। भारत विविधता, समरसता, और सांस्कृतिक सम्पन्नता के साथ एक एकता में समर्थ रहा है। इसे विभिन्न विश्व समुदायों के बीच विश्वस्तर पर प्रचारित करके भारत विश्वगुरु बन रहा है। इस तरह से, भारत विश्वभर में विभिन्न क्षेत्रों में विश्वगुरु बनने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है और इसके माध्यम से विश्व को अपने मूल्यों और संस्कृति को समझाने में मदद कर रहा है।

भारत विश्व मंच पर अपना प्रभाव बना रहा है और विश्व की अर्थव्यवस्था, राजनीति और अन्य क्षेत्रों में अपना योगदान दे रहा है। भारत आने वाले समय में भी विश्व में अपने महत्वपूर्ण स्थान को बढ़ाने में सक्रिय रहेगा। भारत विश्व की एक महत्वपूर्ण राष्ट्र है जिसका योगदान विश्व समृद्धि और उत्थान में अहम रूप से है। इसके सांस्कृतिक धरोहर, अर्थतंत्र, और विज्ञान-तकनीकी क्षेत्र में उन्नति विश्व को प्रेरित करते हैं।

“ हिंदी और नागरी का प्रचार तथा विकास कोई भी रोक नहीं सकता। ”
- गोविन्दवल्लभ पंत।

आजादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिन्दी



अज़मतउल्लाह शरीफ

आशुलिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, हैदराबाद

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रभावशाली नेतृत्व में आज जब पूरा देश आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है और प्रत्येक क्षेत्र में हम नए-नए लक्ष्यों को तय कर रहे हैं, ऐसे में हमारा प्रयास होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी को लेकर संविधान द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। 15 अगस्त 2022 को भारत को आजाद हुए 75 वर्ष पूरे हो गए हैं और यह उन सभी देशों के मुंह पर तमाचा है जो भारत की आजादी के वक्त यह कहते थे कि भारत में ज्यादा समय तक एकता नहीं रह पाएगी और भारत विभिन्न टुकड़ों में बंट जाएगा। भारत की इस महान अखंडता और बंधुता को बनाए रखने में राजभाषा हिंदी की उपयोगिता सर्वोपरी है। हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है यह कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक और गुजरात से लेकर अरुणांचल प्रदेश तक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोए हुए है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने भी अपने कई वक्तव्यों में कहा है कि "राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है और हृदय की कोई भाषा नहीं होती है। हृदय-हृदय से बात-चीत करता है और हिंदी हृदय की भाषा है एवं हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।"

महात्मा गाँधी हिंदी को हिंदुस्तानी कहते थे, उनके अनुसार हिंदुस्तानी हिंदी और उर्दू का खूबसूरत मिश्रण है यह किसी एक समाज के प्रति झुकी हुई नहीं है, वरन् यह हिंदुओं और मुसलमानों एवं उत्तर और दक्षिण के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का सबसे

उत्तम ज़रिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के साबरमती से आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज़ किया जो कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ से लगभग 75 सप्ताह पूर्व का समय था। यह महोत्सव 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। 12 मार्च की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी ने साबरमती से दांडी तक दांडी यात्रा की थी और 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे जहाँ उन्होंने नमक कानून तोड़कर ब्रिटिश सत्ता का पुरजोर विरोध किया। भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और अब भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। अगले 25 वर्षों का यह अमृत काल भारत के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने वाला है। इन 25 वर्षों में भारत को युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए नागरिकों के लिए अवसर की समता लाना, रोजगार सृजन में वृद्धि करना, सुदृढ़ और स्थिर वृहत-आर्थिक वातावरण तैयार करना जैसे महान लक्ष्यों को प्राप्त करना है। हमारा देश एक युवा देश है हमारी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग युवावस्था में है वर्तमान काल की 18 से 35 वर्षीय युवा पीढ़ी आजादी के संघर्ष और लोकतंत्र को प्राप्त करने में हुए बलिदानों को भूल रही है। वह लोकतंत्र के महत्त्व को बेहतर ढंग से नहीं समझ पा रही है कई विचारधाराओं में बंटकर एक कुचक्र में फंस गई है, ऐसे में उसे अपने देश के इतिहास और वर्तमान से जोड़ना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, उसका भूगोल बदलते देर नहीं लगती और ऐसा होने के प्रमाण सर्वविदित हैं। भारत को आजाद कराने के लिए किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, न जाने कितनी कुर्बानियाँ देनी पड़ी, यह आज युवा पीढ़ी को जानना जरूरी है हमारे पाठ्यक्रम में बहुत हद तक इस बारे में जानकारी मिलती है, परंतु इतिहास की बहुत सी बातें पाठ्यक्रम में नहीं हैं, जिन्हें जानना एवं बताना जरूरी है। किसी लोकतांत्रिक देश में सरकारी कामकाज की भाषा तभी सार्थक भूमिका अदा कर सकती है जब देश के जन सामान्य से वो जुड़ी हो और जितने भी निर्णय लिए जाते हैं, जितनी भी नीतियाँ बनती हैं वो तभी लोकभोग्य हो सकती हैं, जब वो स्थानीय लोगों की भाषा में हों। हिंदी की इन्हीं उपयोगिताओं को देखते हुए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है।

आजादी के इन 75 वर्षों में हिंदी का प्रौद्योगिकी विकास बहुत तेजी

से हुआ है। सन 1965 में देवनागरी से संबंधित एक आवश्यक साफ्टवेयर विकसित किया गया। इसके बाद अनेक नई तकनीकें विकसित हुईं, जिनसे हिंदी में काम करने में आसानी हुई। हिंदी में प्रौद्योगिकी योगदान ने इसकी सार्थकता बढ़ा दी है। वर्तमान में मनाया जा रहा आजादी का अमृत महोत्सव पाँच थीम्स पर आधारित है पहला है स्वतंत्रता संग्राम। इस थीम के अंतर्गत भारत के गुमनाम नायकों को उनकी हकदार आभा से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अंतर्गत बिरसा मुंडा जयंती, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतिम सरकार की घोषणा, शहीद दिवस जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। दूसरा है विचार 75। इसके अंतर्गत ऐसे विचारों को आगे बढ़ाया जाएगा जो भारत के अमृत काल को स्वर्ण युग बनाने में जुटे हुए हैं। तीसरा है संकल्प 75। इस थीम का फोकस भारत के भविष्य को आकार देने वाले व्यक्तियों, समूहों के दृढसंकल्प और सामूहिक संकल्प पर आधारित है। इसके अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को दृढ संकल्पित होकर भारत के भाग्य निर्धारण में अपनी अहम भूमिका निभाने की आवश्यकता है। चौथा है एक्शन 75। इसका

फोकस भारत की विश्व स्तर पर छवि को उभारने पर है जो कि कई मायनों में हो भी रहा है, चाहे वह कोविड 19 के दौरान भारत की वैक्सीन नीति के रूप में हो या युक्रेन रूस युद्ध में एक निष्पक्ष देश के रूप में हो और पाँचवां एवं अंतिम है उपलब्धियां 75। देश के 5000 साल पुराने इतिहास और आजादी के इन 75 वर्षों की उपलब्धियों पर इस थीम का फोकस है। इसके अंतर्गत भारत अपनी उन उपलब्धियों को रेखांकित करेगा जिसका विश्व स्तर पर योगदान रहा है। हमें आत्मनिर्भर भारत, शक्तिशाली भारत, स्वावलंबी भारत के सपने को सच करते हुए अपने कर्तव्य परायण भावना का परिचय राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर करना चाहिए। ताकि हम शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर सकें। ताकि भविष्य में कोई भी आसुरी शक्ति भारत की ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानियां देकर हमें आजादी दी है उसे हमें सुरक्षित रखना है तथा उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहना है। इसी प्रकार हमें आजादी का अमृत महोत्सव मनाना है और अमृत काल में भारत के स्वर्णिम भविष्य को मूर्त रूप देना है।

हिंदी के प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका



सुरेश अरुण पाटिल

सहायक रसायनविद
भारतीय खान ब्यूरो, हिंमना, नागपुर

हिंदी का प्रचार करेगी हमारी सोशल मीडिया ट्विटर की चिड़िया ।

लेके साथ में हमारी गूगल की दुनिया ।

नहीं भूलेंगे फेसबुक तथा बहत्सप्प व्हाट्सप्प की अदाकारी ।

जो हिंदी के प्रसार तथा प्रसार में रंग लाई ।



भाषा राष्ट्र की पहचान होती है, देश की जान होती है। किसी भी देश की राष्ट्र भाषा का गौरव उसी भाषा को मिल सकता है जो विशाल जनसमुदाय की बोली हो। भारत में हिन्दी ऐसी भाषा है जो उत्तर से दक्षिण को और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है। हिंदी देश की संपर्क भाषा है, राज भाषा है और राष्ट्र भाषा बनने की पूर्ण रूप से अधिकारी है, पर इसमें अहम रोल निभाता है सोशल मीडिया।

कभी ऐसा समय था जब सोशल मीडिया पर ज्यादातर अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग होता था, और यह हिन्दी भाषियों के लिए सोशल

मीडिया की राह में एक बाधा की तरह देखा जाता था। हालांकि यह बात और है कि हिन्दी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन अब बदलते वक्त के साथ-साथ हिन्दी भाषा ने सोशल मीडिया के मंच पर दस्तक देकर अपने अस्तित्व को और भी बुलंद तरीके से स्थापित किया है।

हिंदी को हमारी राष्ट्रभाषा का दर्जा मिला है इसलिए इसमें विभिन्न चरणों में संशोधन कर इसकी कठनाईयाँ दूर करने का सफल काम आज सोशल मीडिया द्वारा किया जा रहा है उसमें हमारे सभी वर्ग का सहयोग मिला है और इसे उन्नत बनाये रखने में अंत्यत प्रभावी हथियार रहा है। सिर्फ हमारी हिंदी भाषा ही ऐसी भाषा है, जो अनपढ़ वर्ग भी बड़ी आसानी से इस्तेमाल में सोशल मीडिया द्वारा उसे आत्मसात करता है और उसे समझता है।

सोशल मीडिया में हिंदी का प्रयोग वर्तमान समय में बढ़ा है एक समय था जब सोशल मीडिया में इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया ही प्रभावी था पर अभी हर वर्ग उसे आसानी से जनसमुदाय में उसका प्रसार तथा प्रचार करने में काफी हद तक अग्रिम स्थान में आगे बढ़ा हुआ है। न केवल फेसबुक या ट्विटर, बल्कि अब वाट्सएप और टेक्स्ट मैसेज को भी सार्थक बनाने और मैसेज की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न कंपनियां तक हिन्दी भाषा का सहारा ले रही है। वे जानती है कि हिन्दी भाषा का विस्तार काफी अधिक है और अगर उन्हें भी खुद को दूर तक स्थापित करना है तो वही भाषा चुननी होगी, जिसके प्रति पाठक या ग्राहक सहज और पारिवाहिक महसूस करता हो इसके लिए हिन्दी से अच्छा विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। कुछ ही साल पहले तक विश्व में बहुसंख्यक लोग हिन्दी समझते, बहुसंख्यक बोलते और बहुसंख्यक लिखते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर हिन्दी के बढ़ते इस्तेमाल के चलते, अब अंग्रेजी उपयोगकर्ताओं में भी हिन्दी का आकर्षण बढ़ा है और इन आंकड़ों में भी तेजी से वृद्धि हुई है।

वर्तमान में भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इंटरनेट उपयोगकर्ता है, जिसका श्रेय हिन्दी भाषा को भी जाता है। दरअसल भारत की आबादी का एक बड़ा तबका हिन्दी भाषा के प्रति सबसे अधिक सहज है और उसे सोशल मीडिया से जोड़ने में हिन्दी का सबसे बड़ा

योगदान है। सोशल मीडिया पर हिन्दी भाषा के विस्तार की गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जुलाई 2014 तक देश में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 12.6 करोड़ रही, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की संख्या पिछले एक साल में 100 प्रतिशत तक बढ़कर ढाई करोड़ पहुंच गई जबकि शहरी इलाकों में यह संख्या 33 प्रतिशत बढ़कर 9.8 करोड़ रही।

सबसे खास बात यह है, कि न केवल उम्रदराज भारतीय, बल्कि अंग्रेजी का अच्छा-खासा ज्ञान रखने वाले युवा भी अब सोशल मीडिया पर हिन्दी भाषा में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हिन्दी भाषा को और भी विस्तारित करने का कार्य क्रिया ब्लॉगर्स ने। हिन्दी ब्लॉगर्स की संख्या पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। वहीं हिन्दी ब्लॉगिंग के जरिए ऐसे लोगों को विचारों की अभिव्यक्ति का बेहतरीन मंच मिला, जिनके लिए भाषा की रूकावट थी।

14 सितम्बर तक सोशल मीडिया पर इतना हिंदी दिवस को साझा किया गया की भारत तथा हिंदी भाषिक देशों में भी इसकी



जानकारी कुछ ही समय में बड़े पैमाने पर प्रसारित हुई और इसका प्रभाव यह हुआ कि अहिंदी भाषी भी इससे प्रति आकर्षण लगाए देखने मिले। इसका एकमात्र निष्कर्ष रहा कि सोशल मीडिया ही इतना प्रभावी हथियार है की कुछ ही क्षणों में वह अहम जानकारी हिंदी माध्यम द्वारा अनगिनत मीलों तक ले जा सकता है।

पाठकों साहित्यकारों तथा जिन्हें लिखने की अभिलाषा है आज सोशल मीडिया द्वारा और हिंदी का लेखन कम्प्यूटर पर न आते हुए भी वह गूगल ट्रांसलेटर, गूगल इनपुट द्वारा अपने विचार उचित माध्यम से हर समुदाय तक आमजन की भाषा हिंदी पहुँचाया जा सकती है। मैंने सोचा न था की हमारी विशालकाय हिंदी भाषा पुरे विश्व में कैसे पहुँचाई जाएगी पर मेरा ये सपना सोशल मीडिया की मदद से बड़ी आसानी से पूरे विश्व में इसका आगाज कर रहा है।

भारत की भाषा है हिंदी ...

आमजन की पहचान है हिंदी ..

सोशलमीडिया की रानी है हिंदी ..

चाहे न लिखना आवे न पढ़ना ...

पर बोलना आता ही है हिंदी ..

इस लिए कहलाती है

उपरवाले की भाषा भी है हिंदी ।

जयहिन्द। जयहिंदी।

अमृत महोत्सव



आर. सी. महतो

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, गोवा

आइए अमृत महोत्सव मनाएं, देश के प्रति अपना दायित्व निभाएँ।
देश सेवा को अपना उद्देश्य बनाएं, सदैव इसी दिशा में बढ़ते जाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

नेता, नियत को अडिग बनाएं, अपनी कथनी-करनी में एकता लाएँ।
जनता से श्रेष्ठ स्वयं को बनाएँ, यथोचित अगुवाई सदा करते जाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

मंत्री खुद को महान बनाएं, मंत्रालय-कार्य के विशेषज्ञ बन जाएँ।
उद्यम इस तरह करते जाएँ, समय से लक्ष्य प्राप्त होता जाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

कर्मचारी के कार्य प्रशंसा पाए, देश प्रगति पथ पर बढ़ता जाए।
सद् समृद्धि सभी क्षेत्र में आए, सुखद जीवन-धारा बहती जाए।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

किसान की कर्मठता रंग लाए, खेत हरियाली से पट जाए।
उत्पादन अन्न का बढ़ता जाए, अन्नदाता के गुण सब गाए।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

कामगार कर्मठ हो जाएँ, मुफ्तखोरी को कह दे बाय।
परिश्रम के मंत्र अपनाएं, स्वाभिमान को सदा बढ़ाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

शिक्षक सदाचारिता दिखाएं, संस्कृति का सम्मान बढ़ाएँ।
देश को सही दिशा दिखाएं, भारत को विश्वगुरु बनाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

विद्यार्थी अपनी पहचान बनाएं, ज्ञान-गंगा में गोता लगाएँ।
ज्ञान-रत्न लेकर बाहर आएँ, प्रज्ञा की प्रभा चारो ओर फलाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

वैज्ञानिक के कदम बढ़ते जाए, नित्य नये अनुसंधान हो जाए।
अविष्कारों की झड़ी लग जाए, भारत उत्पादक-निर्यातक बन जाए।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

पुलिस अपना पौरुष दिखाएँ, अपराधी उनसे खौफ खाएँ।
सदाचारी के सहायक हो जाएँ, समाज की सराहना पाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

सेना के पराक्रम पहचाने जाएँ, उनके प्रति सम्मान बढ़ता जाएँ।
राष्ट्र सतत सुरक्षित होता जाए, दुश्मन टेढ़ी नजर डाल न जाए।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

सकल सामर्थ्य समन्वित हो जाए, प्रगति की दिशा में लग जाए।
सबके प्रयास परमपराकाष्ठा पाए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाएँ।
आइए अमृत महोत्सव मनाएँ।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



श्रीमती वीनू खत्री

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर

भारत एक गरीब देश है, इसका विकास होना अभी शेष है। हमारे बचपन में हमें यही बताया जाता था तथा हमारे पाठ्यक्रमों में भी इसका कई बार उल्लेख होता था। साथ ही यह भी कहा जाता था कि भारत गावों का देश है। परंतु आज समय बदल चुका है। हमारे देश में आदिकाल से ही बड़े-बड़े वैज्ञानिक, ऋषि-मुनि और विचारक पैदा हुए हैं। चिकित्सा शास्त्र, गणित, नक्षत्र विज्ञान तथा अन्य अनेक ज्ञान-विज्ञानों में भारत ने अनुपम उन्नति की थी। पिछले कुछ वर्षों में भारत कुछ पिछड़ा रहा पर अब आजादी के बाद भारत ने फिर से तेजी से उन्नति आरंभ की है।

आज हमने हर प्रकार के आधुनिक कारखाने लगाए हैं। अणु शक्ति के क्षेत्र में भी भारत ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग की देखरेख में अणुशक्ति संबंधी परीक्षण हमारे देश में लगातार हो रहे हैं। आज भारत ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, उद्योग, विज्ञान, खाद्यान्न, कृषि और अन्य कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आज भारत कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हुआ है। नेविगेशन प्रौद्योगिकी में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत का आईआरएनएसएस अमेरिका के ग्लोबल पोजिसनिंग सिस्टम (जीपीएस), रूस के ग्लोनास, यूरोप के गलीलियो जैसा है। इस कामयाबी के साथ ही भारत का अपना जीपीएस शुरू हो जाएगा। अब इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

आज पूरी दुनियां भारत के प्रतिभाओं का लोहा मान रही है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कल भी कमी नहीं थी और आज भी नहीं है। आज विश्व के अनेक देशों में कई महत्वपूर्ण पदों पर भारतवंशियों को देखा जा सकता है। नई डिजिटल अर्थव्यवस्था में हमारी युवा पीढ़ी अपने ज्ञान और कौशल से बैंकिंग, डाटा एनालिसिस, आईटी, उद्योग, चिकित्सा, साइबर सुरक्षा आदि में अपना योगदान देते हुए दिख रही है। भारत के लिए यह एक गौरव की बात है कि दुनिया के विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की कई नामी कंपनियां भारतीय कौशल का फायदा हासिल करने के उद्देश्य से भारत का रुख कर रही है। इलेक्ट्रानिक्स एवं रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत आज इनका निर्यात कर रहा है। कई वैश्विक रिपोर्टों में कई बार इसका उल्लेख हो रहा है कि भारतवंशी एवं प्रवासी भारतीय वैश्विक तंत्र का अहम हिस्सा है।

हमारा देश आदिकाल से पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। पूर्व में अंग्रेजों ने भी अपना व्यापार करने के लिए भारत को चूना था हालांकि यह अलग बात है कि बाद में वे यहां के शासक बन गए थे। उसी प्रकार आज का भारत भी विदेशी निवेशकों का पसंदीदा देश बन गया है। आज भारत दुनिया के सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले देशों की सूची में आठवें स्थान पर है। भारत को विदेशी निवेशकों का पसंदीदा देश बनाने में तेजी से बढ़ती अर्थ व्यवस्था की विशेष भूमिका है। भारत में निवेश पर अच्छे रिटर्न हैं तथा यहां का बाजार बढ़ती मांग वाला है। योग के क्षेत्र में भी हमारे देश ने विश्व को एक नई दिशा प्रदान की है।

फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी आज ऐतिहासिक दौर में पहुंच गयी है। आज देश में तेजी से कई आर्थिक सुधार हो रहे हैं। हमारे देश में मजबूत राजनीतिक नेतृत्व है। चार वैश्विक रूझान जनसांख्यिकी, डिजिटलीकरण, डीकार्बोनाइजेशन और डीग्लोबलाइजेशन आज नए भारत के पक्ष में हैं। वैश्विक बाजार में आज भारत का अच्छा प्रभाव है। कोरोनाकाल में भी जब समूचा विश्व असहाय सा नजर आ रहा था ऐसे समय में भारत ने कई देशों की अलग-अलग प्रकार से मदद कर यह साबित कर दिया कि आज का भारत किसी भी स्थिति में किसी से कम

नहीं है और पूरी दुनिया ने इसका अनुभव भी किया।

हाल ही में भारत का चंद्रयान-3 मिशन देश के लिए महान गौरव का विषय है। इससे भारत एक नया इतिहास बना सकता है। यह मिशन देश का तिसरा मिशन है जो चांद के अन्वेषण हेतु किया गया है। पूरी दुनिया की नजरे आज चंद्रयान -3 मिशन पर है क्योंकि यह चांद के उस जगह पर पहुंचने वाला है जहां पर जाने में कोई भी देश आज तक सफल नहीं हो पाया है और यह चांद के काफी गूढ़ रहस्यों की जानकारी हासिल

करेगा जो दुनिया के लिए अज्ञात है।

अतः आज की स्थिति में भारत एक विश्वगुरु के रूप में उभर रहा है। भारत को देखने का दुनिया के देशों का नज़रिया अब बदल चुका है। पूरी दुनिया आज भारत को एक प्रगतिशील देश के रूप में देख रही है। यही कारण है कि वर्तमान में अधिकांश देश भारत की ओर मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व में एक शक्तिशाली एवं प्रगतिशील देश के रूप में उच्च स्थान पर अपनी जगह सुनिश्चित करेगा।

वैश्विक परिदृश्य में भारत की बढ़ती भूमिका



विकास कुमार

उच्च श्रेणी लिपिक
भारतीय खान ब्यूरो, रॉची

आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा भारत की विश्व पटल पर बढ़ती भूमिका के पीछे एक लम्बी तपस्या है। दो सौ वर्ष की लम्बी गुलामी पश्चात हमें स्वंत्रता मिली। उस समय भारत के सामने दो विकास के मॉडल थे पूंजीवाद और समाजवाद। इससे इतर भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया ताकि देश की मुलभुत समस्याओं को दूर कर आर्थिक विकास करना मुख्य लक्ष्य था। समयानुकूल 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति उपरांत भारत ने अपनी विदेश नीति में बदलाव करते हुए अमेरिका की ओर रुख किया जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित होने लगी।

वर्तमान समय में भारत वैश्विक स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सैन्य क्षेत्र में भारत की सराहनीय भूमिका रही है। भारत एक सुव्यवस्थित बाजार के रूप में उभरकर सामने आया है। हमारी बदलती विदेश नीति के ही परिणाम है की एक ओर जहाँ सम्पूर्ण विश्व में महत्वपूर्ण संबंधों के लिए जाने जाते हैं वहीं दूसरी ओर आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद परस्त देशों के साथ कड़ा रुख अपनाने के कारण इसका वैश्विक प्रभाव भी नजर आने लगा है। 'डोकलाम विवाद' पर भारत का कड़ा रुख या 'गलवान घाटी' विवाद में भारत का करारा जवाब भारत की मजबूत विदेश नीति को दर्शाता है। आज हम आतंकवाद के खिलाफ जिस तरह अपनी बात रखना चाहते हैं सम्पूर्ण विश्व उसका समर्थन कर रहा है यह हमारी बदली विदेश नीतियों का ही परिणाम

है। अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस यहाँ तक की चीन का भी हमारे प्रति बदलता रुख हमारी सफलता को दर्शाता है। आज भारत की विदेश नीति स्टैंड बाई की तरह नहीं बल्कि एक्शन मोड में आ चुका है।

कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है योग को वैश्विक मान्यता मिलना। आज 21 जून को सम्पूर्ण विश्व योग दिवस मना रहा है। आज भारत को G 20 की मेजबानी मिलने से सम्पूर्ण विश्व में भारतीय कला संस्कृति का प्रचार प्रसार को काफी प्रोत्साहन मिला।

नई वैश्विक व्यवस्था में हर देश की ताकत उसकी आर्थिक मजबूती तय करती है। आर्थिक मोर्चे पर आज भारत को कर्ज लेने वाले देश के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक मदद करने वाले देश के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत की संवृद्धि दर दहाई अंको की ओर अग्रसर है। कोरोना काल के दौरान भारत की पहल पर ही वैश्विक वर्चुअल सम्मेलनों की शुरुआत हुई। कोरोना की वैक्सीन को भारत ने जरूरत मंद देशों को उपलब्ध कराया। कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से निरंतर प्रगतिशील रही। आज भारत एक निवेश के रूप हर देशों की पहली पसंद है।

आज भारत ब्रम्होस, अग्नि - 5 जैसे हथियारों के साथ एशिया की प्रमुख सामरिक सक्ती के रूप में उभरा है किन्तु इसके बाबजूद भी भारत ने शांतिपूर्ण परमाणु नीति अपनाई है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित नाभिकीय समझौता वैश्विक स्वीकृति का ज्वलंत प्रमाण है। आज भारत ने अन्तरिक्ष कार्यक्रम में भी काफी प्रगति की है। चंद्रयान, मंगल मिशन ने भारत की साख को पूरी दुनिया ने माना है।

इस प्रकार अंत में यह कहा जा सकता है की हमारे विदेश नीति हमें वैश्विक स्तर पर एक मजबूत स्थिति में ला रही है परन्तु यह हमारे लिए शुरुआत है हमें और भी अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी हमें भी बहुत सारे वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति में सुधार करना है। हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए की हमें भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्य और एनएसजी की सदस्यता मिल सके।

आजादी का अमृत महोत्सव और राजभाषा हिंदी



श्रीनाथ राज

कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारतीय खान ब्यूरो, भुवनेश्वर

आजादी का अमृत महोत्सव एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण आयोजन है। भारत की आजादी के 75 वें वर्षगांठ को मनाने के लिए आयोजित किया गया है इस अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय गर्व और स्वाधीनता की महिमा को स्मरण करते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत संघर्ष करके इस देश को आजाद कराया था और इस महोत्सव से हम अपनी राष्ट्रीय अस्मिता, गौरव, उनके संघर्ष और त्याग को याद करते हैं। यह आयोजन देशवासियों के लिए भारतीय गर्व को बढ़ाने और उन्नति की ओर प्रेरित करने का महान अवसर है।

आजादी का अमृत महोत्सव अपनी स्वतंत्रता के साथ अपनी संस्कृति, भाषा और ऐतिहासिक धरोहरों के प्रति अपनी विशेष आसक्ति व्यक्त करता है। दूसरी तरफ हमारे देश की राजभाषा हिंदी है जो हमारे देश में लगभग 40% लोगों द्वारा बोली जाती है हिंदी को एक ऐसी भाषा माना जाता है जो भारतीय संस्कृति और ऐतिहासिक विरासत के आधार पर ही विकसित हुई है। भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हिंदी दिवस उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व को प्रोत्साहित करना है, जो भारत की संस्कृति और विरासत का हिस्सा है। हाल के समय में सरकार ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भाषा के महत्व को और ज्यादा प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है। हमारा देश विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं का आद्यान्त विलोम से पूर्ण है इसी में हमारी

समृद्धि का सूत्र समाहित है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है जो हमारे देश की भाषा-भूमिका को महत्वपूर्ण बनाती है। भाषा हमारी सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक है।

आजादी के 75वें वर्ष में यह एक विशेष उत्सव है। जो इस अवसर को याद दिलाने और देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया है। इस उत्सव में देशभक्ति और स्वाधीनता को समर्पित अनेक कार्यक्रम वर्षांत आयोजित किए गए। आजादी का अमृत महोत्सव एक नया मानदंड है इस उत्सव से हम संगठित रूप से अपनी भावनाओं को जोड़ सकते हैं और एक नया भारत बनाने में योगदान दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी भारत की राजभाषा है देश की सबसे अधिक बोली, लिखी और समझी जाने वाली भाषा है हिंदी को संविधान में आधिकारिक राजभाषा के रूप में स्वीकृति दी गई है हिंदी का वर्तमान स्वरूप विकसित होता जा रहा है। इसका महत्व और प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है आज हिंदी ना सिर्फ लेखन की भाषा है बल्कि उससे आगे बढ़कर विज्ञापन, अभिव्यक्ति और सोशल मीडिया पर चैट की प्रमुख भाषा बन चुकी है। आज सभी पुरानी वर्जनाओं को तोड़कर हिंदी गर्व और अभिव्यक्ति की भाषा बन चुकी है। वर्तमान में हिंदी का विकास को बढ़ावा मिल रहा है कई कारणों से हिंदी की प्रगति और प्रभाव वर्धित हो रही है।

1. सरकारी समर्थन: सरकार ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाओं की शुरुआत की है। भाषा विकास और प्रसार के लिए कई सरकारी संस्थानों का संचालन किया जाता है और राजभाषा विभाग हिंदी के प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार और उपयोग को प्रोत्साहित करता है।

2. शिक्षा में हिंदी का महत्व: हिंदी भाषा की महत्ता को समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी को प्रोत्साहन मिल रहा है। हिंदी को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में स्कूलों और कालेजों में शामिल किया जाता है और हिंदी माध्यम के शिक्षा संस्थानों का प्रशासनिक समर्थन किया जाता है। हिंदी के प्रति छात्रों की रुचि भी बढ़ी है।

3. विशेष महोत्सव और कार्यक्रमों का आयोजन: हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के वर्धन के लिए विभिन्न महोत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। टेलीविजन, रेडियो, अखबार और जनसंचार का माध्यम बन गई है।

4. सरकारी कार्यालयों, कार्यक्रमों, विज्ञापनों और संवाद की प्रमुख भाषा हिंदी बन चुकी है। विभागों, न्यायालयों, सार्वजनिक स्थानों पर हिंदी का प्रयोग बढ़ रहा है।

उपरोक्त प्रयासों के अतिरिक्त गत दशक में राजनीतिक रूप से हिंदी हेतु अपनाई जाने वाली स्वीकार्यता और सहजता भी अमृत काल में इस भाषा हेतु राजसी वैभव लौटाने जैसा है। वैसे भी अब हिंदी ने एक लंबा सफर तय कर लिया है और इसकी प्रगति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है की आजादी के शताब्दी वर्ष आते आते यह अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरती संवाद के शिखर पर होगी।

गत वर्ष के दौरान हिंदी संबंधी कार्यों का विवरण ।

भारतीय खान ब्यूरो अपने मुख्यालय तथा सभी अधीनस्थ कार्यालयों में भारत सरकार की राजभाषा नीति को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित कर रहा है। भारतीय खान ब्यूरो का मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है जो 'ख' क्षेत्र में स्थित है। 06 अधीनस्थ कार्यालय 'क' क्षेत्र में, 01 अधीनस्थ कार्यालय 'ख' क्षेत्र में तथा शेष 07 अधीनस्थ कार्यालय 'ग' क्षेत्र में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो के सभी अधीनस्थ कार्यालयों ने राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम उल्लिखित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। वर्ष 2022-23 के दौरान हिंदी कार्यान्वयन से संबंधित प्रगति का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. मुख्यालय में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक:-

दिनांक 08/07/2022 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 122 वीं बैठक, दिनांक 07/10/2022 को 123 वीं बैठक, दिनांक

05/01/2023 को 124 वीं बैठक तथा दिनांक 12/04/2023 को 125 वीं बैठक का आयोजन किया गया। इन बैठकों में कार्यालय में बोर्ड, नामपट्ट इत्यादि का क्षेत्रीय भाषा में भी लिखा जाना, राजभाषा के सरलीकरण हेतु सुझाव, ई-ऑफिस में हिंदी टिपण्णी पृष्ठों की गणना, भारतीय खान ब्यूरो की 75 वीं स्थापना दिवस पर हिंदी पत्रिका का विशेषांक का प्रकाशन, भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय में वार्षिक एवं तिमाही रिपोर्ट विषय पर हिंदी कार्यशाला का आयोजन, भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय के दो अनुभागों / प्रभागों को राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट करना, ई-ऑफिस में उपलब्ध हिंदी टिप्पणियों की गणना की सुविधा, आदि अनेक विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाता है और रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाती है।



2. भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय में हिंदी पखवाड़ा – 2022 का आयोजन :-

भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर में दिनांक 14/09/2022 से दिनांक 29/09/2022 तक हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशानुसार हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर, 2022 को सुरत, गुजरात में केंद्रीकृत रूप से किया गया और समापन दिनांक 30 सितंबर, 2022 को कार्यालय में किया गया।

उक्त कार्यक्रम में भारतीय खान ब्यूरो की ओर से डॉ. वाय. जी. काले, खान नियंत्रक (टी.एम.पी.) एवं राजभाषा अधिकारी तथा श्री गुमना राम, उप खान नियंत्रक, गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय ने भाग लिया। साथ ही दिनांक 15 सितम्बर 2022 को संपन्न हुए द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मलेन में भी उक्त अधिकारी उपस्थित थे।

हिंदी पखवाड़ा - 2022 के दौरान दिनांक 29/09/2022 से 30/09/2022 तक कार्यालय में विभिन्न प्रतियोगिताएं एवं कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रतियोगिताओं में सामान्य हिंदी निबंध प्रतियोगिता, तकनीकी हिंदी निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी अनुवाद प्रतियोगिता, हिंदी शुद्ध लेखन प्रतियोगिता, हिंदी टंकण प्रतियोगिता, राजभाषा हिंदी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी तात्कालिक वाक् प्रतियोगिता एवं राजभाषा प्रश्नमंच प्रतियोगिता प्रमुख हैं। कार्यालय के हिंदी एवं हिंदीतर भाषी कर्मिकों के लिए अलग - अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन सभी प्रतियोगिताओं में कार्यालय के कर्मिकों ने

अधिकाधिक संख्या में भाग लिया।

दिनांक 30/09/2022 को श्री पंकज कुलश्रेष्ठ, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी) की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा - 2022 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर माॅयल लिमिटेड के अध्यक्ष-सह प्रबंध निदेशक श्री मुकुंद पी. चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। साथ ही डॉ. वाय. जी. काले, खान नियंत्रक (टी.एम.पी.) एवं राजभाषा अधिकारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा कर्मिक भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कार्यक्रम के आरम्भ में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, माननीय संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी जी तथा मंत्रीमंडल सचिव श्री राजीव गौबा का सन्देश मंचासीन अधिकारियों द्वारा वाचन किया गया। हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह के अवसर पर भारतीय खान ब्यूरो नागपुर की हिंदी गृह पत्रिका 'खान भारती' - 2022 का विमोचन भी किया गया।



हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी विषयक प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को अध्यक्ष, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी), मुख्य अतिथि महोदय एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा पुरस्कार वितरित किए गए।

3. तकनीकी एवं प्रशासनिक पत्रों का अनुवाद कार्य :-

वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण तकनीकी एवं प्रशासनिक दस्तावेजों का अनुवाद हिंदी में किया गया। वर्ष 2021-22 के लिए खान मंत्रालय के वार्षिक रिपोर्ट के करीब 90 पृष्ठों का हिंदी में अनुवाद किया गया। इसी प्रकार कोयला एवं इस्पात पर स्थायी संसदीय समिति

से संबंधित सामग्री की करीब 25 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया तथा टंकण कर तकनीकी सचिव अनुभाग को भेजा गया। इसी प्रकार खनन एवं खनिज सांख्यिकी प्रभाग से संबंधित सामग्री की करीब 15 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया। साथ ही, तकनीकी सचिव अनुभाग से प्राप्त भारतीय खान ब्यूरो की उपलब्धियों से सम्बंधित 15 पृष्ठों का हिंदी अनुवाद किया गया।

4. राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण:- मुख्यालय के प्रभाग /अनुभाग यथा मुख्य खान नियंत्रक कार्यालय, खनिज अर्थशास्त्र प्रभाग, भंडार अनुभाग तथा लेखा अनुभाग, जी. एम. सेल, आधुनिक खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक संयंत्र, हििंगणा, बजट अनुभाग एवं स्थापना अनुभाग, खान नियंत्रक (मध्य) कार्यालय, प्रकाशन अनुभाग, केंद्रीय पुस्तकालय, टी. एम. पी. प्रभाग, सतर्कता अनुभाग, सामान्य अनुभाग, तकनीकी सचिव अनुभाग, नागपुर क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई।

5. भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन :-

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रचार – प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 09/06/2022 को

भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 19 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। साथ ही दिनांक 26/09/2022 को एक अर्द्ध दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 21 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। दिनांक 15 दिसंबर 2022 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 18 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दिनांक 16 मार्च, 2023 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 28 अधिकारी एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

6. खान भारती के रचनाकारों को मानदेय :-

वर्ष 2022 में प्रकाशित भारतीय खान ब्यूरो, (मुख्यालय), नागपुर की हिंदी गृह – पत्रिका 'खान भारती' के रचनाकारों को मानदेय की स्वीकृति प्रदान की गई।



7. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का राजभाषा निरीक्षण :-

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का दिनांक 14/05/2022 को राजभाषा निरीक्षण किया गया। इस हेतु निरीक्षण प्रश्नावली के मुख्यालय से संबंधित जानकारी के 03 पृष्ठ तैयार किए गए एवं उक्त निरीक्षण से संबंधित अन्य आवश्यक कार्य किए गए। भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर से उक्त निरीक्षण के दौरान श्री पंकज

कुलश्रेष्ठ, मुख्य खान नियंत्रक (प्रभारी) उपस्थित थे। देहरादून क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से श्री मनीष क. मेंदीरत्ता, क्षेत्रीय खान नियंत्रक एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

8. भूवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण:-

डॉ. वाय. जी. काले, खान नियंत्रक (टी.एम.पी.) एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा दिनांक: 26/05/2022 को भूवनेश्वर क्षेत्रीय

कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई।

9. हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण:-

डॉ. वाय. जी. काले, खान नियंत्रक (टी.एम.पी.) एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा दिनांक: 07/07/2022 को हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई।

10. चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण:-

भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा दिनांक: 01/09/2022 को चेन्नई क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई। निरीक्षण के पश्चात दिनांक: 02/09/2022 को उक्त कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। साथ ही उक्त कार्यालय के संबंध में संसदीय राजभाषा निरीक्षण समिति की निरीक्षण प्रश्नावली में आवश्यक सुधार कराया गया।

11. संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा बेंगलुरु कार्यालय का राजभाषा निरीक्षण :-

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा बेंगलुरु कार्यालय का दिनांक 04/11/2022 को राजभाषा निरीक्षण किया गया। इस हेतु निरीक्षण प्रश्नावली के मुख्यालय से संबंधित जानकारी के 03 पृष्ठ तैयार किए गए एवं उक्त निरीक्षण से संबंधित अन्य आवश्यक कार्य किए गए। भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय), नागपुर से उक्त निरीक्षण के दौरान डॉ. वाय. जी. काले, खान नियंत्रक (टी.एम.पी.) एवं राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे।

12. भारतीय खान ब्यूरो की पत्रिका 'खान भारती' नराकास पुरस्कार से सम्मानित :-

वर्ष 2021 के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नागपुर,

(का-2), द्वारा भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय की पत्रिका 'खान भारती अंक-7' को प्रथम प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर की ओर से श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक एवं श्रीमती मिताली चटर्जी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 19/12/22 को आयोजित छःमाही बैठक में ग्रहण किया गया। विदित हो यह पुरस्कार खान भारती के ई-पत्रिका / फ्लिप बुक प्रारूप को प्राप्त हुआ है।

13. भारतीय खान ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालयों को राजभाषा पुरस्कार :-

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राजभाषा सम्मलेन का आयोजन भुवनेश्वर में दिनांक 08 दिसम्बर को आयोजित हुआ। जिसमें क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर को राजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2020-21 के लिए द्वितीय पुरस्कार और वर्ष 2021-22 के लिए प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ एवं दिनांक 16.12.2022 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति जबलपुर द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारतीय खान ब्यूरो, के जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय को प्रथम पुरस्कार दिया गया।

14. गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण :-

भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय द्वारा दिनांक:13/01/2023को गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय का राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण रिपोर्ट भेजी गई। निरीक्षण के पूर्व दिनांक: 12/01/2023 को उक्त कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

15. खान मंत्रालय की दिनांक 15.02.2023 को आयोजित ऑनलाइन समीक्षा बैठक:-

खान मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.02.2023 को श्री शकील आलम, आर्थिक सलाहकार, खान मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन से सम्बंधित ऑनलाइन समीक्षा बैठक का आयोजन

किया गया जिसमें भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर सहित सभी आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला, आदि के वर्ष 2021 - 2022 के दौरान राजभाषा सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा की गई। उक्त बैठक में भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय, नागपुर से डॉ. वाय. जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी ने भाग लिया। बैठक हेतु मुख्यालय स्तर पर आवश्यक कार्य किये गए। सभी आंचलिक/ क्षेत्रीय कार्यालयों/ खनिज प्रसंस्करण प्रयोगशाला, से निर्धारित प्रपत्र में वर्ष 2021 - 2022 के लिए हिंदी कार्यों के आंकड़े मंगाए गए और उन्हें संग्रहित कर खान मंत्रालय को भेजा गया। उक्त आंकड़े एक्सेल फॉर्मेट में भी भेजे गए। बैठक में खान मंत्रालय द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु अनुदेश सभी कार्यालयों को प्रेषित कर दिए गए हैं।

16. भारतीय खान ब्यूरो के 75वें स्थापना दिवस समारोह के आयोजन से सम्बंधित कार्य:-

भारतीय खान ब्यूरो के 75वें स्थापना दिवस समारोह के आयोजन से सम्बंधित आवश्यक कार्य किये गए जिसमें स्मारिका हेतु सन्देश, प्रेस नोट, विज्ञापन आदि का अनुवाद भी शामिल है।



17. राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के तहत व्यक्तिश आदेश :-

राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय के 15 अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने हेतु व्यक्तिश आदेश जारी किया गया।

18. संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 04/11/2022 को बेंगलुरु कार्यालय का किए गए राजभाषा निरीक्षण के उपरांत दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई :-

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 04/11/2022 को बेंगलुरु कार्यालय का किए गए राजभाषा निरीक्षण के उपरांत दिए गए आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई खान मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित की गई।



19. मूल हिंदी टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना:-

मूल हिंदी टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 हेतु भारतीय खान ब्यूरो के कुल 17 कार्यालयों के 74 कर्मिकों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

20. भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 14/06/2023 को अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला का आयोजन :-

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रचार - प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तथा खान मंत्रालय के निदेशानुसार भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर के अधीनस्थ क्षेत्रीय एवं आंचलिक कार्यालयों में कार्यरत हिन्दी संपर्क अधिकारियों एवं हिन्दी कार्य से जुड़े कुल 31 कर्मिकों ने दिनांक 14 जून, 2023 को भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला में उत्साहपूर्वक भाग लिया।



इस अवसर पर आयोजित उदघाटन समारोह की अध्यक्षता मुख्य खान नियंत्रक श्री पी. एन. शर्मा ने की तथा मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्य खान नियंत्रक श्री पंकज कुलश्रेष्ठ उपस्थित थे। इस अवसर पर खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी डॉ. वाय. जी. काले विशेष रूप से उपस्थित थे।

अपने संबोधन में राजभाषा अधिकारी डॉ. वाय. जी. काले ने इस कार्यशाला की भूमिका एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी को अपने क्षेत्रों में ऐसी कार्यशाला आयोजित करने का सुझाव दिया। मुख्य खान नियंत्रक श्री पंकज कुलश्रेष्ठ ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रतिभागी अपने कार्यालय में लौटने के पश्चात हिन्दी में कार्य करने हेतु प्रेरित करें। मुख्य खान नियंत्रक श्री. पी. एन. शर्मा ने हिन्दी में होनेवाली त्रुटियों व आनेवाली समस्या तथा इसके समाधान पर अपने विचार रखते हुए इस कार्यशाला को उपयोगी बताया। श्री. ए. के. शर्मा, संपादक ने हिन्दी कार्यशाला का संक्षिप्त परिचय दिया।

हिन्दी कार्यशाला में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के डॉ. मनोज कुमार, सचिव नराकास ने राजभाषा नीति व तिमाही प्रगति रिपोर्ट, श्री असीम कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली, राजभाषा अधिकारी डॉ. वाय. जी. काले ने राजभाषा विभाग द्वारा जारी निदेश, एवं श्री. ए. के. शर्मा, संपादक

ने ई-ऑफिस में हिन्दी टंकण की जानकारी आदि विषयों पर अपने व्याख्यान दिए।

अपने व्याख्यान में डॉ. मनोज कुमार ने राजभाषा नीति विषय पर व्यापक रूप से अपने विचार रखे तथा तिमाही प्रगति रिपोर्ट को भरने में आने वाली कठिनाईयों का समाधान किया। श्री असीम कुमार, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने विभिन्न समितियों की जानकारी देते हुए संसदीय राजभाषा समिति के कार्यों के बारे में विस्तार से बताया साथ ही संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली को भरने में आने वाली समस्याओं का समाधान किया। राजभाषा अधिकारी डॉ. वाय. जी. काले ने संविधान में राजभाषा से संबंधित विभिन्न अनुच्छेदों, कानूनी प्रावधानों, नियमों, अधिनियमों की विस्तृत जानकारी देते हुए हिन्दी के कार्यान्वयन हेतु भारत में विभाजित किए गए 'क', 'ख', एवं 'ग' क्षेत्रों के विषय में विस्तृत जानकारी दी। श्री. ए. के. शर्मा, संपादक ने ई-ऑफिस में हिन्दी टंकण में आने वाली समस्याओं व कठिनाईयों का समाधान किया।



कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों ने अपनी विशेष रुचि दिखाते हुए व्याख्याताओं से अपनी समस्याओं का निवारण किया साथ ही ऐसी कार्यशाला समय – समय पर नियमित रूप से आयोजित किए जाने की इच्छा व्यक्त की।

कार्यशाला के पश्चात सभी प्रतिभागियों से कार्यशाला के विषय में

उनकी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त की गई। सभी प्रतिभागियों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की साथ ही यह भी कहा कि कार्यशाला में व्याख्याओं के साथ विचार – विमर्श आवश्यक है तथा ऐसी कार्यशाला दो दिन आयोजित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए इस कार्यशाला को पूरी तरह से परिपूर्ण बताया। कार्यशाला के अंत में डॉ. वाय. जी. काले, राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रतिभागियों को प्रतिभागिता प्रमाण – पत्र भी प्रदान किया गया। कार्यशाला आयोजन की विस्तृत रिपोर्ट आई.बी.एम. फेसबुक, ट्वीटर एवं वेबसाइट पर भी अपलोड की गई। इसके अतिरिक्त प्रमुख विभिन्न स्थानीय दैनिक समाचार – पत्रों हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में

कार्यशाला आयोजन के संबंध में समाचार प्रकाशित किए गए।

कार्यशाला का मंच संचालन श्रीमती वीनू खत्री, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने किया। अंत में श्रीमती मिताली चटर्जी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी द्वारा दिए गए धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस विशेष हिंदी कार्यशाला के आयोजन में हिंदी अनुभाग के श्रीमती मिताली चटर्जी, श्री असीम कुमार, श्री किशोर डी. पारधी, श्रीमती वीनू खत्री, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, प्रदीप कुमार सिन्हा, श्री एम. एन. मोरे तथा श्री राहुल कौशिक ने भी योगदान दिया।

भारतीय खान ब्यूरो : सुर्खियों में



दैनिक भास्कर - महानगर
नागपुर, शनिवार, १ अक्टूबर २०२२ । १४

हिंदी पखवाड़ा के पुरस्कार वितरित

नागपुर, भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय) नागपुर में पंकज कुलश्रेष्ठ, मुख्य खान निबंधक (प्रवासी) की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा का सम्पन्न एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विभिन्न क्षेत्र के अग्रणी-सह प्रबंध निदेशक मुकुंद पी. चौधरी उपस्थित थे। डॉ. वाण.जी. कान्ते, खान निबंधक (टीएचबी), राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। गृह एवं सहायता मंत्री, संसदीय कार्य बोधना एवं खानमंत्री तथा सौरभदेव मंडल का संदेश अधिकांशतः द्वारा वाचन किया गया। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर की हिंदी गुरु पत्रिका 'खान भारती - 2022' का विमोचन भी किया गया। अशोक कुमार शर्मा, संवादक ने 'सात वर्ष की हिंदी संस्था काशी' की उपलब्धियां रखीं। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को श्री कुलश्रेष्ठ, श्री चौधरी तथा डॉ. कान्ते ने पुरस्कार वितरित किए। संसालन विनय कुमार रामसेना, अर्चित पुस्तकालय एवं सूचना सहायक ने विन्या। आभार अस्सीन कुमार, कानिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने माना।

आयबीएममध्ये कार्यशाळा

नागपुर, भारत सरकारचे राजभाषा धोरणाचे कार्यान्वयन व हिंदीचा प्रचार-प्रसार व प्रगतीचा उद्देश लक्षात घेता भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालयात हिंदी पंथरवडा आयोजित करण्यात आला. कार्यशाळेत भारतीय खान ब्यूरोच्या विविध प्रभागतील एकूण 21 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. हिंदी कार्यशाळेत वेस्टन कॉलकॉलेज कार्यालयाचे डॉ. मनोज कुमार खोनी संचाचे राजभाषा धोरण व भाषा आदी विषयांवर व्याख्यान दिले. कुमार खोनी उपस्थितांना भारत सरकारचे राजभाषा धोरण, संचाचा घटनाक्रम व अंकाचे रोमन, इंग्रजी व देवनागरी स्वरूपांवायत विस्तृत माहिती दिली. अभिनय कुमार शर्मा यांनी संचाचे आभार मानले.

लोकमत समाचार - अपना नागपुर
रविवार, ९ अक्टूबर २०२२ । ३

भारतीय खान ब्यूरो में पुस्तकालय वितरित

नागपुर : भारतीय खान ब्यूरो (मुख्यालय) के मुख्यालय में मुख्य खान निबंधक (प्रवासी) पंकज कुलश्रेष्ठ की अध्यक्षता में हिंदी पखवाड़ा का सम्पन्न एवं पुरस्कार वितरण समारोह का दिनांक 05 अक्टूबर को आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद विभिन्न क्षेत्र के अग्रणी-सह प्रबंध निदेशक मुकुंद पी. चौधरी उपस्थित थे। डॉ. वाण.जी. कान्ते, खान निबंधक (टीएचबी), राजभाषा अधिकारी उपस्थित थे। गृह एवं सहायता मंत्री, संसदीय कार्य बोधना एवं खानमंत्री तथा सौरभदेव मंडल का संदेश अधिकांशतः द्वारा वाचन किया गया। भारतीय खान ब्यूरो नागपुर की हिंदी गुरु पत्रिका 'खान भारती - 2022' का विमोचन भी किया गया। अशोक कुमार शर्मा, संवादक ने 'सात वर्ष की हिंदी संस्था काशी' की उपलब्धियां रखीं। पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजयी प्रतिभागियों को श्री कुलश्रेष्ठ, श्री चौधरी तथा डॉ. कान्ते ने पुरस्कार वितरित किए। संसालन विनय कुमार रामसेना, अर्चित पुस्तकालय एवं सूचना सहायक ने विन्या। आभार अस्सीन कुमार, कानिष्ठ अनुवाद अधिकारी ने माना।

भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय नागपुर के ३१ अधिकारी हुए शामिल

अ.भा. विशेष हिन्दी कार्यशाळा आयोजित

नागपुर : भारत सरकार के राजभाषा धोरणाचे कार्यान्वयन व हिंदीचा प्रचार-प्रसार व प्रगतीचा उद्देश लक्षात घेता भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालयात हिंदी पंथरवडा आयोजित करण्यात आला. कार्यशाळेत भारतीय खान ब्यूरोच्या विविध प्रभागतील एकूण 21 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला. हिंदी कार्यशाळेत वेस्टन कॉलकॉलेज कार्यालयाचे डॉ. मनोज कुमार खोनी संचाचे राजभाषा धोरण व भाषा आदी विषयांवर व्याख्यान दिले. कुमार खोनी उपस्थितांना भारत सरकारचे राजभाषा धोरण, संचाचा घटनाक्रम व अंकाचे रोमन, इंग्रजी व देवनागरी स्वरूपांवायत विस्तृत माहिती दिली. अभिनय कुमार शर्मा यांनी संचाचे आभार मानले.





संसदीय राजभाषा समिति द्वारा बेंगलुरु कार्यालय के निरीक्षण के दौरान पुस्तक प्रदर्शनी



संसदीय राजभाषा समिति द्वारा रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण



नराकास नागपुर द्वारा खान भारती पत्रिका हेतु पुरस्कार ग्रहण करते हुए श्री अभिनय कुमार शर्मा, संपादक एवं श्रीमती मिताली चटर्जी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी



भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय में आयोजित अखिल भारतीय विशेष हिन्दी कार्यशाला में प्रमाण – पत्र वितरित करते हुए डॉ. योगेश जी. काले, खान नियंत्रक एवं राजभाषा अधिकारी



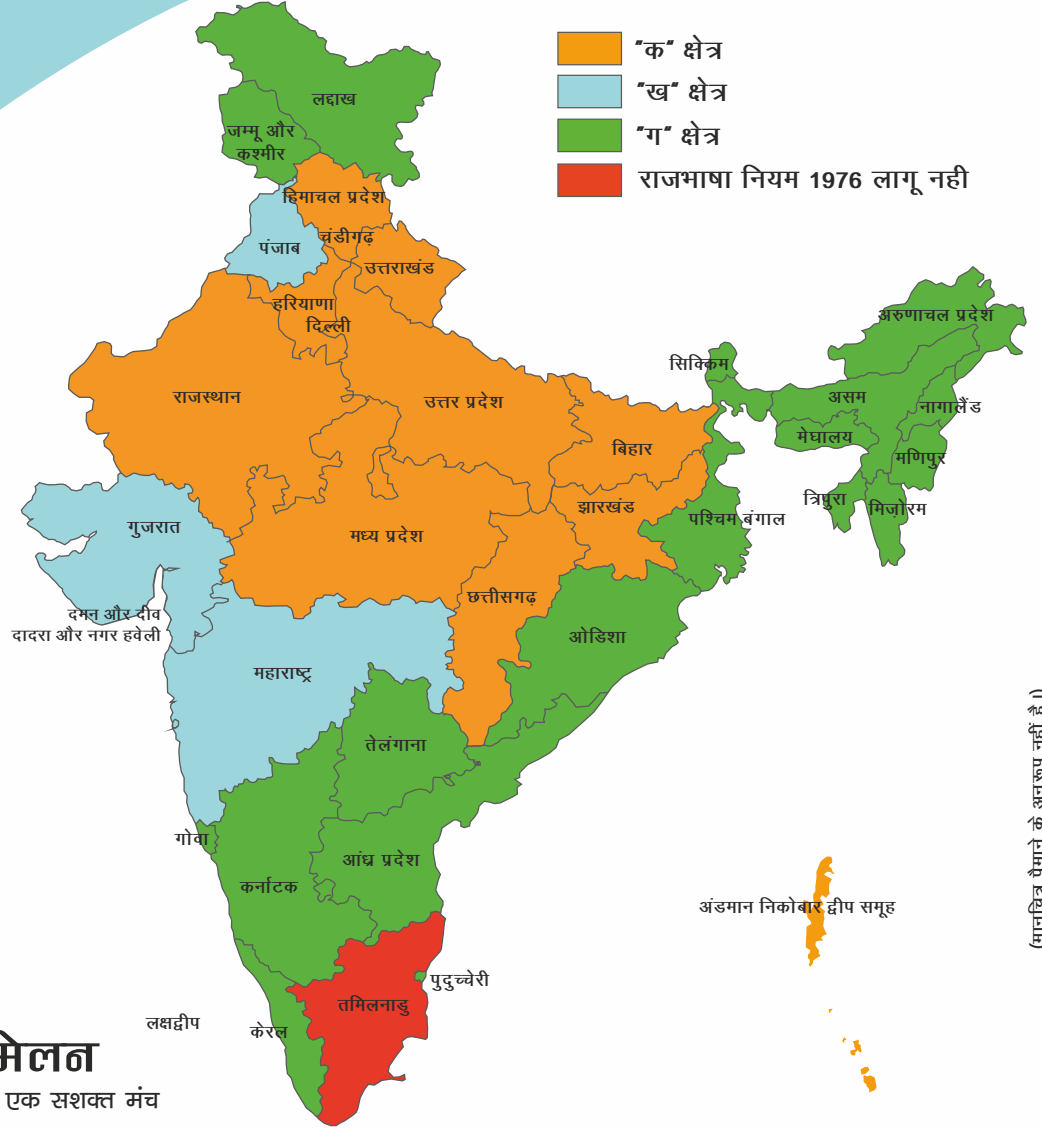
जबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के निरीक्षण के दौरान हिंदी कार्यशाला का आयोजन



अखिल भारतीय विशेष हिंदी कार्यशाला के उद्घाटन अवसर पर उपस्थित अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण

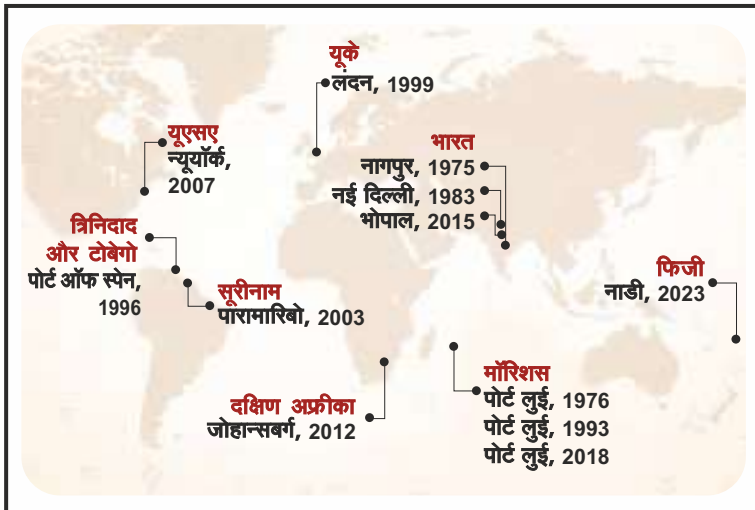
राजभाषा नियम 1976

के अंतर्गत 'क' 'ख' एवं 'ग' क्षेत्र में विभाजित राज्य



विश्व हिन्दी सम्मेलन

हिन्दी के वैश्विक प्रचार-प्रसार के लिये एक सशक्त मंच



भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर